चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 22 जून -28 जून 2015 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

लालू-नीतीश का तूफ़ानी क़दम

हम यहां बिहार को लेकर सुबह चार बजे देखा हुआ सपना लिख रहे हैं. हमें नहीं मालूम कि हम जो सपना लिख रहे हैं, उसमें कितना सच है, कितना नहीं, लेकिन यह सपना इतना मजेदार है कि इससे जनता परिवार के मनोविज्ञान का, जनता परिवार के क़दमों का और जनता परिवार की सोच का पता चलता है. इसलिए हम जान-बूझ कर पहली बार सुबह चार बजे देखा हुआ सपना आपके सामने रख रहे हैं. आइए, देखते हैं कि सपने में हमने क्या देखा?

संतोष भारतीय

सात तारीख की शाम साढ़े चार बजे दिल्ली में श्री मुलायम सिंह के निवास स्थान पर बैठक शुरू हुई और उस बैठक में लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव और स्वयं मुलायम सिंह उपस्थित थे. उस बैठक में समाजवादी पार्टी के महामंत्री राम गोपाल यादव भी मौजूद थे. बैठक बहुत अच्छे वातावरण में शुरू हुई, लेकिन अचानक नीतीश कुमार कुछ उखड़ गए. नीतीश कुमार ने सख्त लहजे में कहा, मुझे न मुख्यमंत्री बनना है, न मुझे कुछ करना है. अब मैं चाहता हूं कि सारी बातचीत यहीं रोक दी जाए. उन्होंने राम गोपाल यादव से भी कहा कि आपने इस तरह के बयान अख़बारों में क्यों दिए कि बिहार में गठबंधन होगा, एक पार्टी नहीं बनेगी. दरअसल, नीतीश कुमार चाहते थे कि एक पार्टी बने और मुलायम सिंह उसके नेता के नाते सीटों का बंटवारा करें और जो भी फ़ैसला करें, उसे लालू यादव और वह (नीतीश) मान लें, ताकि लोगों के सामने एक पार्टी, जिसका अस्तित्व बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में होता, वह राष्ट्रीय पार्टी बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ती. श्री राम गोपाल यादव के एक बयान से यह प्रक्रिया समाप्त हो गई. इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा, मैं जा रहा हूं, मुझे काम है और वह उस बैठक से बाहर निकल गए. सपने में हमने यह भी देखा कि लालू यादव नीतीश के बाहर जाने से दु:खी हुए और क्रोधित भी हुए. मुलायम सिंह को यह बात खराब लगी कि उस बैठक में जाने से पहले दिन में नीतीश कुमार क्यों राहुल गांधी से मिलने गए. बैठक वहीं पर रुक गई. नीतीश कुमार बिहार भवन चले गए. शरद यादव अपने घर चले गए और मुलायम सिंह जी एवं लालू यादव जी राम गोपाल जी के साथ वहां रह गए.

सपने में हम देखते हैं कि मुलायम सिंह ने लालू यादव को समझाया कि अगर बिहार में आप दोनों मिलकर नहीं लड़ेंगे, तो जीतना असंभव है और चुनाव एकतरफ़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाएगा. शायद मुलायम सिंह को यह दिखाई दे रहा होगा कि बिहार की हार का नतीजा उन्हें उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ सकता है. मुलायम सिंह के समझाने के बाद न राम गोपाल जी को समझाने की ज़रूरत पड़ी और न लालू यादव को. श्री लालू यादव वहां से उठे और शरद यादव के घर चले गए.

शरद यादव के घर पर अकेले लालू यादव गए. हमने सपने में देखा कि शरद यादव के ड्रॉइंग रूम में किसी का भी आना-जाना नहीं हो रहा है. शरद यादव और लालू यादव की बातचीत हो रही है. शरद यादव लालू यादव को बताते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने मुझे यह संकेत दे दिया है कि अगर कांग्रेस साथ आती है, जिसके बारे में राहुल गांधी

बिहार में टूट जाने वाला धागा अचानक मजबूत बनकर सपने में हमें दिखाई दिया. इसके बाद हम देखते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव खुले मन से पटना चले गए. मुलायम सिंह यादव को बहुत देर बाद यह समझ में आया कि उनकी रणनीति में कहीं कोई चूक हो रही है. दरअसल, मुलायम सिंह यादव के सामने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश करने का यह आख़िरी अवसर है.

ने उनसे वादा किया है, तो सिर्फ़ हम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे. आप अपने लड़ने की तैयारी कीजिए. शरद यादव और लालू यादव का रिश्ता बहुत अच्छा है. शरद यादव ने तस्वीर का दूसरा रुख भी बताया कि इसका राजनीतिक परिणाम क्या हो सकता है. लालू यादव ने कहा, मैंने तो कभी मना नहीं किया. अब मेरे साथी कोई इम्प्रेशन दें, बयान दें, तो उससे मेरा क्या लेना-देना. शरद यादव ने लालू यादव से यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने अपना दिमाग बना लिया है और वह इस चुनाव में देवेगौड़ा, ओम प्रकाश चौटाला और कमल मोरारका को अपने पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए बुलाएंगे. शरद यादव ने यह भी कहा कि इसका एक मतलब यह है कि फिर आरजेडी और समाजवादी पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नई एकता की शुरुआत हो जाएगी. लालू यादव ने शरद यादव से साफ़ कहा कि आप नीतीश कुमार को मुलायम सिंह जी के यहां फिर बुलाइए और हम लोग बातचीत करेंगे. जब नीतीश कुमार के पास शरद यादव की यह ख़बर गई, तो उन्होंने उस बैठक में जाने से मना कर दिया. नीतीश कुमार ने कहा, मैं किसी भी प्रकार की घोषणा के पक्ष में नहीं हूं, न बैठक के पक्ष में हूं. मैं चाहता हूं कि जिसे जितनी सीटों पर लड़ने का मन है, वह लड़े. मैं किसी चीज

का दावेदार नहीं हूं. यह मेरे ऊपर ग़लत आरोप है कि मैं मुख्यमंत्री या गठबंधन का नेता बनना चाहता हूं.

सपने में हम देखते हैं कि शरद यादव बार-बार नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोग, जिनमें केसी त्यागी प्रमुख हैं, बार-बार नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि जब सब लोग आप से कह रहे हैं कि रास्ता निकल रहा है, तो आप मुलायम सिंह के यहां क्यों नहीं जाते? अंतत: रात के साढ़े आठ बजे के आस-पास नीतीश कुमार फिर मुलायम सिंह के घर पहुंचते हैं और वहां पर नए सिरे से बैठक शुरू होती है. इस बार उस बैठक में सीधा फ़ैसला होता है कि बिहार में दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे और लालू यादव इसकी घोषणा करेंगे. सीटों के बंटवारे पर पहले नीतीश कुमार का कहना था कि जब एक पार्टी रहेगी, तो कौन-सी सीट किसे दी जाए, इसका फ़ैसला मुलायम सिंह करें और हम दोनों मानें. लेकिन अगर गठबंधन होगा, तो हम दोनों बराबर सीटों पर लड़ेंगे और बची हुई सीटों में हम कांग्रेस या अगर वामपंथी साथ आए, तो उन्हें समाहित करने की कोशिश करेंगे. लालू यादव ने कहा कि सीटों के ऊपर कोई मतभेद नहीं होगा. तीन-तीन लोगों की समिति इसके ऊपर बैठकर बात कर लेगी, जहां परेशानी होगी, वहां मैं और नीतीश कुमार मिलकर उसका फ़ैसला कर लेंगे.

बिहार में टूट जाने वाला धागा अचानक मजबूत बनकर सपने में हमें दिखाई दिया. इसके बाद हम देखते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव खुले मन से पटना चले गए. मुलायम सिंह यादव को बहुत देर बाद यह समझ में आया कि उनकी रणनीति में कहीं कोई चूक हो रही है. दरअसल, मुलायम सिंह यादव के सामने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश करने का यह आख़िरी अवसर है. आख़िरी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एक फौजी की निगरानी में है हज मिशन इस बार धोखेबाजों की खैर नहीं | P-3

जोशी और कटियार ने ठोंकी ताल | P-5

लालू और नीतीश की एकजुटता ने बिगाड़ा भाजपा का खेल | P-6

बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद

लालू-नीतीश का तूफ़ानी क़दम

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

पृष्ठ 1 का शेष

अवसर इसलिए, क्योंकि राजनीति में नए-नए लोग आते रहते हैं और पुराने लोगों को किनारे करते रहते हैं. मुलायम सिंह के सामने इतिहास ने एक नया अवसर दिया, जहां उन्हें देवगौड़ा, ओम प्रकाश चौटाला, नीतीश कुमार, लालू यादव एवं कमल मोरारका ने अपना नेता मान लिया, एक पार्टी का नेता मान लिया और जनता परिवार का मुखिया मान लिया. अगर इस गठबंधन की जगह एक पार्टी बनती, तो मुलायम सिंह नरेंद्र मोदी के सामने देश में एक विकल्प की तरह सामने आते और वे सारे लोग, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करते, जो कांग्रेस का भी समर्थन नहीं करते, इस पार्टी में शामिल होने की कतार में खड़े हो जाते. यानी गुजरात से प्रवीण सिंह जडेजा, ओडिशा से कांग्रेस का एक बड़ा तबका और पश्चिम बंगाल से वे सारे लोग, जो सीपीएम, कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के साथ नहीं हैं. इन सबके संदेश दिल्ली में मुलायम सिंह के यहां पहुंच चुके थे. भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथी बार-बार मुलायम सिंह जी के यहां यह संदेश भेज रहे थे कि यदि पार्टी बने, तो हम सब भी उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं. एक बड़ा राजनीतिक संगठन विपक्ष का स्थान लेने के लिए सामने आ रहा था. हालांकि, कांग्रेस को यह बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन कांग्रेस भी उसके साथ मिल सकती थी और देश में एक नया राजनीतिक समीकरण उभर सकता था.

अब मुलायम सिंह को लगा कि उनके साथियों की वजह से थोड़ी-सी चूक हो गई. अब मुलायम सिंह खुद इस दिमाग के हैं कि जल्द से जल्द एक पार्टी बन जानी चाहिए. इस सपने के एक हिस्से में हमने यह भी देखा कि मुलायम सिंह लखनऊ में अपने दस-बारह घनिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं. उस बातचीत में उन्होंने यह कहा, मैं दिल्ली में अपनी पार्टी में किसके साथ बात करूं? एक मेरा पोता है, एक मेरी बहू है, एक मेरा भतीजा है यानी जो पांच लोग हैं लोकसभा में, वे सब मुलायम सिंह के परिवार के हैं. मुलायम सिंह ने इस बात को लेकर अपने पुत्र एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा कि हमारी बहुमत की सरकार है, सारे प्रदेश में लोग हमारा समर्थन करते हैं, लेकिन हम सिर्फ़ चार सीटों पर सिमट गए. पांचवीं सीट उपचुनाव में हमारे पास आई. इसका मैं क्या मतलब निकालूं? यह तो मेरी राजनीति के डगमगाने का संकेत है. उन्होंने कहा कि आप सारे लोग बैठे हुए हैं और प्रदेश में हम चुनाव हार जाते हैं. उन्होंने कई चीजों के बारे में उस बैठक में कहा. और, सबसे अपने दिल की बात कही कि आप लोग अगर काम नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं देश की राजनीति में हम हाशिये पर चले जाएंगे.

हमने सपने में यह भी देखा कि दो दिन पहले मुलायम सिंह ने कुछ लोगों से कहा, मुझे समझ में आ गया है कि किसने-किसने इस काम को रोका यानी एक पार्टी बनने में किसने रोड़ा अटकाया और किसने ग़लतफहमियां फैलाईं, यह मेरी समझ में आ गया है. शायद मुलायम सिंह के पास ओम प्रकाश चौटाला की कही हुई यह बात पहुंची है कि मुलायम सिंह जी को हम सब प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह के आस-पास के लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते. शायद इसी कसौटी पर मुलायम सिंह ने सारे क़दमों को कसा और देश की राजनीति को लेकर थोड़े ज़्यादा चिंतित हमें सपने में दिखाई दिए.

लालू यादव का रोल इस सारी चीज में सबसे पॉजिटिव रहा. हमने सपने में देखा कि चार महीने पहले जब लालू यादव के सामने यह बात रखी गई कि हमें एक पार्टी बनानी चाहिए, तो उसका समर्थन सबसे पहले लालू यादव ने किया. यह बात लालू यादव के सामने अन्य लोगों के अलावा सबसे पहले देवेगौड़ा जी ने रखी. हमने देखा कि लालू यादव देवेगौड़ा जी से कह रहे हैं, मैं इसमें पूरी तरह सहमत हूं और इसमें जो सैक्रिफाइस करना हो, वह मैं करने के लिए तैयार हूं. मैं पुराना लालू यादव नहीं हूं. मैं अब नए सिरे से, नई सच्चाइयों के साथ देश की स्थितियां देख रहा हूं. देश कहां जा रहा है, यह भी मैं समझ रहा हूं. और यह बात लालू यादव ने सिर्फ़ देवेगौड़ा जी से ही नहीं कही, उन्होंने यह बात कई सारे लोगों से कही. लालू यादव दरअसल नए सिरे से एक बड़े परिवर्तन का गणित बनाने में लगे हुए हैं. लेकिन, लालू यादव के बारे में भी एक सोची-समझी योजना के तहत कई सारी ख़बरें अख़बारों में आईं. आज बिहार में जीत का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ़ लालू यादव की समझ, लालू यादव की रणनीति और लालू यादव के प्रचार अभियान की शैली के ऊपर निर्भर होता दिखाई दे रहा है. सपने में हमने यह भी देखा लालू यादव अपने सारे नज़दीकियों से बिल्कुल साफ़ कह रहे हैं कि हर हालत में बिहार का चुनाव नीतीश को सामने रखकर जीतना ही जीतना है. उसके बाद देश में कैंपेन करना है.

सपने में हमने एक और चीज देखी. हमने देखा कि नीतीश कुमार ने दिल्ली की बैठक से पहले अपना यह दिमाग बना लिया था कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का सहयोग लेंगे. देवेगौड़ा, ओम प्रकाश चौटाला और कमल मोरारका का सहयोग लेंगे. उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान में लगे बिहार के लड़कों को तोड़ा और उन्हें बिहार में प्रचार करने की नई ज़िम्मेदारी सौंप दी. उस टीम के नेता प्रशांत कुमार ने नरेंद्र मोदी की शैली में ही नीतीश कुमार के प्रचार अभियान की शुरुआत की. इस प्रचार अभियान में पहले ही दिन से पैसे का रोल दिखाई दे रहा है. प्रचार सामग्री, थ्री-डी यानी वे सारे क़दम, जो नरेंद्र मोदी ने आजमाए थे, बिहार में नीतीश कुमार ने आजमाने की तैयारी कर ली और उनकी टीम ने आठ तारीख को बिहार में यह पोस्टर लगवा दिए कि एक बार फिर नीतीश कुमार. यानी प्रचार अभियान का तरीका दिल्ली में केजरीवाल की तरह का उन्होंने डिजायन किया. नीतीश कुमार की रणनीति का एक छोटा शिफ्ट. पहले नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुक़ाबला करने की बात सोचते थे, लेकिन अब वह नरेंद्र मोदी स्टाइल में राजनीति के साथ घनघोर प्रचार अभियान की शैली को अपना समर्थन दे चुके हैं.

राहुल गांधी पशोपेश में थे कि बिहार में वह किस तरह से चुनाव लड़ें. वह लालू यादव के साथ गठबंधन कर चुनाव में नहीं जाना चाहते थे. नीतीश कुमार उनकी पहली पसंद थे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ भी वह अकेले जाने में थोड़े हिचक रहे थे. इसलिए उनकी तरफ़ से संदेशवाहकों ने यह साफ़ कर दिया कि अगर लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो उनका उस गठबंधन में शामिल होना ज़्यादा आसान है. अगर दोनों अलग-अलग लड़ते हैं, तो कांग्रेस फिर क्या फ़ैसला करेगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता. इस संकेत को लालू यादव एवं नीतीश कुमार ने समझा और उन्हें लगा कि इस स्थिति में छह-सात प्रतिशत वोटों का बहुत मतलब है. लालू यादव को भी लगा कि सिर्फ़ 29 प्रतिशत वोटों से सरकार नहीं बनती. नीतीश कुमार को भी लगा कि सिर्फ़ 12-14 प्रतिशत से सरकार नहीं बनती और कांग्रेस के सामने साफ़ था. इसलिए अगर मुक़ाबला करना है, तो मिलकर मुक़ाबला करना चाहिए.

बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता सुशील कुमार मोदी हैं. बिहार में यह बात चल पड़ी है कि सुशील कुमार मोदी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी तीनों एक वर्ग से आते हैं. सुशील कुमार मोदी को अगर बिहार में भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाए, तो जीत मिल सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उस स्थिति में उच्च जातियों, मसलन भूमिहारों एवं राजपूतों में उसके समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार की ओर चला जाएगा. इस बात को दिल्ली में बैठे नेता स्वीकार नहीं करते, लेकिन राजीव प्रताप रूडी और रविशंकर प्रसाद आपसी बातचीत में इस समझ को नकार भी नहीं रहे हैं.

सपने में हमने एक चीज और देखी कि देवेगौड़ा अपने साथियों से कह रहे हैं कि बिहार में अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है, जैसा लालू यादव ने उन्हें इशारे में कहा था, तभी वह चुनाव प्रचार में जाएंगे. हालांकि, देवेगौड़ा जी का कोई रोल बिहार में नहीं है, लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री आख़िरकार भूतपूर्व प्रधानमंत्री होता है. जो प्रधानमंत्री रह चुका होता है, उसकी एक आभा होती है. देवेगौड़ा देश में किसानों के नेता माने जाते हैं. देवेगौड़ा और चौटाला की इस सोच ने कि इस सबकी ज़िम्मेदारी मुलायम सिंह की है, अगर वह इसे नहीं बना पाते हैं, तो फिर देश में एक डिजास्टर होगा, बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार को न केवल एक साथ आने के लिए मजबूर किया, बल्कि ईमानदारी के साथ उन्हें एक साथ रहने के लिए दबाव में भी ले लिया.

यह सुबह का सपना है चार बजे का. सपना सच है या नहीं, मैं नहीं जानता. लेकिन, सपने में इतने रंग हैं, इतनी घटनाएं हैं कि मुझे लगा कि यह सपना आपके साथ साझा करूं. अब इस सपने का एक टेल पीस है, आख़िरी हिस्सा. वह भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं. मैं यह देख रहा हूं कि अगले पच्चीस दिनों में यानी बिहार चुनाव का शंखनाद होने से पहले इस देश में एक नई राष्ट्रीय पार्टी का अभ्युदय हो सकता है. उस पार्टी का नाम समाजवादी दल हो सकता है, समाजवादी जनता दल हो सकता है, समाजवादी पार्टी हो सकता है. और, इस बात के लिए मुलायम सिंह मुझे सोचते-विचारते भी दिखाई दिए और मुलायम सिंह मुझे आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दिए.

भारतीय जनता पार्टी की बिहार में एक अजीब स्थिति हो गई है. भारतीय जनता पार्टी यह मान बैठी थी कि लालू और नीतीश कुमार का गठबंधन नहीं होगा तथा उसके यहां बिहार चुनाव में जीतने के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, इसकी लड़ाई शुरू हो गई थी. लेकिन, जैसे ही इस गठबंधन की घोषणा हुई, हमने सपने में देखा कि सारे नेताओं के चेहरे बुझ गए. हमने देखा बिहार के बड़े नेता बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ़ दो समूह ऐसे हैं, जिनके समर्थन के बग़ैर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला. इनमें एक हैं मुसलमान और दूसरे हैं यादव. लेकिन, मुसलमानों और यादवों के नेता भी सपने में बातचीत करते हुए दिखाई दिए कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे करेगी नहीं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के दावे से बहुत दूर खड़ी दिखाई देगी. शाहनवाज हुसैन मुसलमानों के नेता हैं और नंद किशोर यादव यादवों के नेता हैं. भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के नामों के ऊपर विचार ही नहीं कर रही है. जबकि ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी में अपने आपको बिहार के मुख्यमंत्री पद का सबसे सुयोग्य उम्मीदवार साबित करने में लगे हैं. नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को धूमिल कर दिया है.

बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता सुशील कुमार मोदी हैं. बिहार में यह बात चल पड़ी है कि सुशील कुमार मोदी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी तीनों एक वर्ग से आते हैं. सुशील कुमार मोदी को अगर बिहार में भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाए, तो जीत मिल सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उस स्थिति में उच्च जातियों, मसलन भूमिहारों एवं राजपूतों में उसके समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार की ओर चला जाएगा. इस बात को दिल्ली में बैठे नेता स्वीकार नहीं करते, लेकिन राजीव प्रताप रूडी और रविशंकर प्रसाद आपसी बातचीत में इस समझ को नकार भी नहीं रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में पैसे का खुला खेल खेलना चाहती है. ठीक वैसे ही, जैसे देश के चुनाव में उसने पैसे के दम पर देश के लोगों को एक सपना दिखाया था, लेकिन चूंकि इस मामले में नीतीश कुमार ने बढ़त ले ली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने अब उसी प्रकार का प्रचार अभियान चलाने के अलावा कोई रास्ता है नहीं.

मुख्य प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने यह है कि क्या वह नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार का चुनाव लड़े? संशय यह भी है कि यदि भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार का चुनाव लड़ती है और चुनाव हार जाती है, तो देश में अगले प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊंचा दिखाई देने लगेगा. यह संशय या भ्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा-सा ही सही, लेकिन फ़ैसले लेने में दिक्कत पैदा कर रहा है. सुबह का सपना है. सच होता है, तो बहुत अच्छा. नहीं सच होता है, तो सपना तो आख़िर सपना ही होता है. सपने में कही हुई संपूर्ण घटनाओं का मजा लीजिए और बिहार चुनाव में किस तरह के रंग दिखाई देते हैं, उनका मजा लीजिए. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 16
दिल्ली, 22 जून –28 जून 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय	0120–6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022–42296060
	+91–8451050786
	+91–9266627379
फैक्स न.	0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

भारत में खाने को लेकर भी विविधता है. इस बात का ध्यान रखते हुए लोगों के लिए चार तरह के मेन्यू रखे गए हैं. यह ज़िम्मा भी विश्वसनीय और जानी–मानी कैटरिंग एजेंसियों को दिया जाएगा. उनमें से एक सऊदी एयरलाइंस को खाना मुहैया कराती है. ऐसा करने से हर किसी को अपनी पसंद का गुणवत्ता वाला भोजन यात्रा के दौरान मिल सकेगा. हाजियों की रिहाइश एक बड़ा मसला है. इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक लांग टर्म एकोमोडेशन कमेटी बनाई गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाजियों के रहने के लिए जगह हर साल लेते हो, तो आप एक साथ चार–पांच साल के लिए जगह क्यों नहीं लेते हो? इससे खर्च भी कम होगा और जगह भी अच्छी मिल सकेगी.

एक फौजी की निगरानी में है हज मिशन

इस बार धोखेबाजों की खैर नहीं

हर साल पूरी दुनिया से तक़रीबन 20 लाख लोग हज अदा करने सऊदी अरब पहुंचते हैं, जिसमें अकेले भारत की भागीदारी एक लाख से अधिक होती है. इस साल भी भारत से तक़रीबन 1.36 लाख मुसलमान इस मुक़द्दस फ़र्ज़ की अदायगी केलिए सऊदी अरब रवाना होंगे. दरअसल, इतने बड़े पैमाने पर लोगों केआने–जाने, उनके ठहरने, खाने–पीने के साथ–साथ हज अदायगी की व्यवस्था करना पेचीदा और कठिन काम है. इसलिए हज का सफ़र शुरू करने से लेकर वतन वापसी तक हाजियों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. चौथी दुनिया अक्सर हज और हाजियों से जुड़े मसले उठाता रहा है. भारत सरकार ने इस बार हज के महकमे की ज़िम्मेदारी विदेश राज्यमंत्री जनरल (रिटा.) वीके सिंह को सौंपी है. इसलिए हज और हाजियों से जुड़े तमाम मुद्दों की तरफ़ सरकार का ध्यान आकर्षित करने और उनके हल के लिए चौथी दुनिया ने जनरल वीके सिंह की एक प्रेस कांफ्रेंस दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित की. इस प्रेस कांफ्रेंस में दिल्ली के नामचीन उर्दू अख़बारों केसाथ–साथ अधिकांश छोटे–बड़े मीडिया हाउसेस को शिरकत की दावत दी गई थी. उनमें से कुछ के नुमाइंदे आए और बाकियों ने हाजियों की समस्याओं को ध्यान देने के काबिल नहीं समझा. उनमें उर्दू केबड़े अख़बार भी शामिल थे. प्रस्तुत है जनरल वीकेसिंह की प्रेस कांफ्रेंस पर आधारित *चौथी दुनिया* की रिपोर्ट...

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारत सरकार इस बार हाजियों के लिए नए तरीके से काम कर रही है. इस बार हज यात्रा की ज़िम्मेदारी विदेश राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह को दी गई है, जिसे पूरा करने के लिए जनरल वीके सिंह जद्दा का दौरा भी कर चुके हैं और हज यात्रा से संबंधित कई मामलों पर सऊदी सरकार के साथ बातचीत भी. पहले की तुलना में कई प्रमुख बदलाव किए गए हैं. स्टैंडर्ड बैगेज, लोगों के खाने–पीने, आने–जाने, ठहरने और कुर्बानी जैसे कई बुनियादी मसलों पर दोनों सरकारों के नुमाइंदों के बीच रजामंदी हुई. इन्हीं तमाम बातों का इजहार जनरल वीके सिंह ने चौथी दुनिया की हज से जुड़ी इस प्रेस कांफ्रेंस में किया. उन्होंने कहा कि इस बार हज यात्रा की कमान एक फौजी के हाथों में है, इसलिए किसी भी तरह की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इस बार 20 देशों के लोगों से कहा गया है कि हज यात्री स्टैंडराइज्ड बैगेज लेकर आएं, जिनमें भारत भी शामिल है. सऊदी की अथॉरिटीज ने सवाल उठाया कि भारत के हज यात्री बोरियां और कई तरह के नॉन स्टैंडर्ड बैगेज लाते हैं, जिन्हें लाने–ले जाने, सुरक्षा जांच और कनवेयर बेल्ट पर रखने में असुविधा होती है तथा सामान गुम होने, देरी से पहुंचने जैसी शिकायतें मिलती हैं. इसलिए सऊदी सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वह अपने हज यात्रियों को स्टैंडर्ड बैगेज के साथ भेजे, जिसे भारत सरकार ने मान लिया है. जनरल सिंह ने कहा कि जब बांग्लादेश अपने हज यात्रियों को स्टैंडराइज्ड बैगेज के साथ भेज सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता. ऐसा करने से यात्रियों को सहूलियत होगी, उनका सामान उनके साथ ही पहुंचेगा. जब बैगेज की गुणवत्ता और क़ीमत के बारे में सवाल खड़े किए गए, तो जनरल सिंह ने कहा कि हमने वीआईपी और सेमसोनाइट जैसी कंपनियों से इस संबंध में निविदाएं मंगाई थीं. वीआईपी 5,100 रुपये में हर शहर में बैग उपलब्ध कराने की हमारी शर्त पर राजी हो गया, इसलिए वीआईपी को यह काम दे दिया गया. लेकिन जब क़ीमतों में अंतर के संबंध में जनरल सिंह से सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि हमने पूरी तफ्तीश और जांच के बाद ही यह फ़ैसला लिया है. उक्त बैग हज यात्रियों को बाज़ार मूल्य से 40 प्रतिशत कम दाम में मिलेंगे. बावजूद इसके कोई शिकायत या असंतोष हो, तो सैंपल विदेश मंत्रालय के हज विभाग में उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी जांच सकता है और आपत्ति दर्ज करा सकता है. यदि कंपनी किसी तरह की गड़बड़ी करती है, तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ राज्यों ने बैगेज की क़ीमत अदा करने की इच्छा जाहिर की है. केंद्र सरकार ने उन्हें इसके लिए अनुमति दे दी है.

जहां तक हज कोटे का सवाल है, तो सऊदी सरकार का इस संबंध में एक फॉर्मूला है. वह प्रत्येक 1,000 लोगों में से एक को हज करने का मौक़ा देता है. मक्का और मदीना में विस्तार का काम चल रहा है, इसलिए सऊदी सरकार ने दूसरे देशों के हज कोटे में 20 प्रतिशत की कटौती की और अपने कोटे से 50 प्रतिशत की. पिछले कुछ सालों से भारत का कोटा 1.76 लाख से घटाकर 1.36 लाख कर दिया गया है. जनरल सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने सऊदी सरकार से अपील की कि भारत के कोटे का निर्धारण 2001 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाए. इस पर सऊदी सरकार की तरफ़ से आश्वासन मिला कि वह इस अनुरोध पर विचार करेगी.

जहां तक प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का सवाल है, तो हाजियों की शिकायत उनके बारे में यह रहती है कि वे मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से हाजियों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है. इस संबंध में जनरल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनके 27 प्रतिशत के कोटे को बरकरार रखा गया है, हालांकि सरकार ने इस बार प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए नियमों में सख्ती कर दी है. जो टूर ऑपरेटर्स सरकार की शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें हाजियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा जिस किसी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के संबंध में अनियमितताओं की शिकायत मिलेगी, उसे ब्लैक लिस्टेट कर दिया जाएगा.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

हाजियों की सहायता के लिए खुद्दामों और अन्य अधिकारियों की टीम उनके साथ जाती है. आम तौर पर हाजियों की शिकायत यह रहती है कि इन खुद्दामों को न तो वहां के रास्तों की जानकारी होती है और न वहां की बोली की. ऐसे में वे हाजियों के लिए मददगार साबित नहीं हो पाते. यदि कोई वीआईपी डेलिगेशन हज पर जाता है, तो वे उसी की खिदमत में लग जाते हैं या फिर अपनी इबादत में मशगूल रहते हैं. जनरल सिंह ने कहा कि इस बार खुद्दामों और दूसरे अधिकारियों के लिए न्यूनतम अर्हता रखी गई है और उनका चुनाव उसी आधार पर पारदर्शी तरीके से किया जाएगा. उनके चुनाव के वक्त इस बात की अच्छी तरह तस्दीक की जाएगी कि वे वहां के रास्तों और वहां की भाषा से अच्छी तरह वाकिफ हों. उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. यदि उनके संबंध में शिकायतें मिलती हैं, वे अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह नहीं करते हैं, तो उन्हें तत्काल हटा दिया जाएगा. इस बार कोशिश की गई है कि कोई वीआईपी डेलीगेशन हज पर न जाए. यदि जाए, तो खुद्दाम उनकी सेवा में न लगे रहें. हाजियों के साथ डॉक्टरों का एक दल भी जाता है और वहां एक मेडिकल कैंप लगाता है. इसके लिए पहले हज कमेटी दवाइयां खरीदती थी, लेकिन इस बार सरकार ने ऑर्म्ड फोर्सेस सर्विसेस के हेड के मार्फत दवाएं मंगाई हैं, ताकि दवाइयां सही क़ीमत पर और गुणवत्ता वाली हों. साथ ही दवाओं की खरीद में किसी तरह की धांधली भी न हो. सरकार ने ऑर्म्ड फोर्स के कुछ डॉक्टरों की भी मांग की है, ताकि हाजियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके.

सऊदी सरकार की ओर से यह प्रावधान है कि हाजियों को कुर्बानी के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के कूपन दिए जाते हैं. भारत सरकार भी अपने हाजियों के लिए कूपन लेती रही है. लेकिन, सऊदी अधिकारियों ने भारत का नाम लिए बगैर कहा कि दक्षिण एशिया के कुछ देशों के दलाल नकली कूपन बांटने का धंधा करते हैं. जाहिर है कि यदि ऐसे दलालों से कोई कूपन खरीदता है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी. इसलिए इस बार भारत सरकार कूपन उपलब्ध कराएगी और काउंसलेट जनरल को हिदायत दी गई है कि हर कुर्बानी की पुष्टि के लिए एक व्यक्ति तैनात करें, ताकि हाजियों को संतुष्टि हो जाए कि उनका हज मुकम्मल हो गया है.

हाजियों को हवाई यात्रा के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस बार हज यात्रियों को ले जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस को 30 प्रतिशत कोटा दिया गया है. पिछले साल तक इंडियन एयरलाइंस को 50 प्रतिशत कोटा दिया जाता था, जिसमें से कुछ हिस्सा इंडियन एयरलाइंस आउटसोर्स कर देती थी. ऐसे में कई कांट्रेक्ट एयरलाइंस बीच में आ जाती थीं, जिससे हाजियों को उड़ान भरने और उतरने के लिए घंटों विमान में इंतजार करना पड़ता था. इस बार इंडियन एयरलाइंस को कहा गया है कि उसे जिन निजी ऑपरेटर्स के विमान लेने हैं, वह उनसे पहले ही समझौता कर ले. बीच में किसी और को घुसने नहीं दिया जाएगा. सरकार ने इस बार सीधे तौर पर विमानन क्षमता के अनुरूप इंडियन एयरलाइंस का कोटा घटाकर तीस प्रतिशत कर दिया, ताकि वह सही तरीके से हाजियों को ले जा सके. बाकी 70 प्रतिशत कोटे में से 60 प्रतिशत सऊदी एयरलाइंस और 10 प्रतिशत सऊदी अरब की एक अन्य एयरलाइंस को दिया गया है. और, ऐसी एयरलाइंस को ज़िम्मेदारी दी गई है, जो नियमित तौर पर अपने विमानों से एयर सर्विसेस उपलब्ध कराती हैं. इस बार मान्यता प्राप्त एयरलाइंस को कोटा दिया गया है, इसलिए इस बार फ्लाइट्स में देरी नहीं होगी. एक मसला आब–ए–जमजम का भी है. पिछले साल शिकायत आई कि कई हाजियों का आब–ए–जमजम उन्हें नहीं मिला. ज़्यादातर लोगों का आब–ए–जमजम उनके साथ भारत नहीं आया. जनरल सिंह ने कहा कि स्टैंडराइज्ड बैगेज होने की वजह से आब–ए–जमजम हाजियों के साथ ही आएगा.

भारत में खाने को लेकर भी विविधता है. इस बात का ध्यान रखते हुए लोगों के लिए चार तरह के मेन्यू रखे गए हैं. यह ज़िम्मा भी विश्वसनीय और जानी–मानी कैटरिंग एजेंसियों को दिया जाएगा. उनमें से एक सऊदी एयरलाइंस को खाना मुहैया कराती है. ऐसा करने से हर किसी को अपनी पसंद का गुणवत्ता वाला भोजन यात्रा के दौरान मिल सकेगा. हाजियों की रिहाइश एक बड़ा मसला है. इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक लांग टर्म एकोमोडेशन कमेटी बनाई गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाजियों के रहने के लिए जगह हर साल लेते हो, तो आप एक साथ चार–पांच साल के लिए जगह क्यों नहीं लेते हो? इससे खर्च भी कम होगा और जगह भी अच्छी मिल सकेगी. शाहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी जद्दा इसी सिलसिले में गई थी, लेकिन वहां लांग टर्म के लिए बात नहीं बन पाई. लोग दो साल के लिए तो जगह देने को तैयार हैं, लेकिन हम कम से कम तीन साल के लिए चाहते हैं. इस बार सऊदी सरकार द्वारा स्वीकृत जगहों पर ही हाजियों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, जहां खाना बनाने के लिए किचन भी उपलब्ध रहेगा. इसके लिए सऊदी के काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया की देखरेख में एक मॉनीटरिंग कमेटी बनाई गई है. इसके साथ ही जनरल सिंह ने आश्वासन दिया कि उम्रदराज हाजियों के रहने के लिए भूतल और पहली मंजिल पर व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो. साथ ही उन्हें काबा के निकट रुकने की जगह देने की कोशिश की जाएगी.

शिकायत के लिए सेंट्रलाइज्ड ई–मेल और ऐप्प

जनरल वीके सिंह ने कहा कि वह कोशिश कर रहे हैं कि हाजियों की शिकायतों और सुझावों के लिए एक ऐप्प और ई–मेल उपलब्ध कराएं. अब तक हम हाजी लोकेटर नामक एक ऐप्प उपलब्ध कराते हैं. हम एक नया ऐप्प डेवलप करेंगे, ताकि शिकायत या सुझाव एक साथ चार–पांच लोगों के पास पहुंच जाए, जिससे हाजियों की समस्याओं का समाधान हो सके.

हज कमेटी को सरकारी उपक्रम बनाने पर विचार

हज कमेटी का हाजियों के साथ कोई लीगल कॉन्ट्रेक्ट नहीं होता है. हज कमेटी की कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है. ऐसे में हाजी हज कमेटी को कंज्यूमर फोरम या अदालत में चुनौती नहीं दे सकते. हज कमेटी यह दावा करती है कि वह मुफ्त में सेवाएं देती है, जो कि झूठ है. हज कमेटी को सरकार हर साल तक़रीबन आठ करोड़ रुपये देती है. प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ हाजी का एग्रीमेंट होता है, उसे आप कंज्यूमर फोरम में ले जा सकते हैं. तो क्या भारत सरकार के उपक्रम के रूप में हज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन नहीं किया जा सकता? इस सवाल के जवाब में वीके सिंह ने कहा कि इस मसले पर बहुत सलाह–मशविरा करने की ज़रूरत है. विभिन्न पक्षों के साथ बैठकर फ़ायदा और नुक़सान देखकर इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है. साथ ही मौजूदा सेटअप में हज कमेटी को कैसे ज़िम्मेदार बनाया जा सकता है, इस पर भी विचार करेंगे.

हाजियों की सहायता के लिए खुद्दामों और अन्य अधिकारियों की टीम उनके साथ जाती है. आम तौर पर हाजियों की शिकायत यह रहती है कि इन खुद्दामों को न तो वहां के रास्तों की जानकारी होती है और न वहां की बोली की. ऐसे में वे हाजियों के लिए मददगार साबित नहीं हो पाते. यदि कोई वीआईपी डेलिगेशन हज पर जाता है, तो वे उसी की खिदमत में लग जाते हैं या फिर अपनी इबादत में मशगूल रहते हैं.

उर्दू पत्रकारों की उदासीनता

छह जून को हज कमेटी की उक्त प्रेस कांफ्रेंस को कवर करने के लिए उर्दू के रिपोर्टर बड़ी तादाद में मौजूद थे, क्योंकि वहां खाने–पीने का बेहतरीन इंतजाम था. लेकिन, हज के मुद्दे पर जनरल वीके सिंह की प्रेस कांफ्रेंस में बहुत कम पत्रकार पहुंचे. इस पर तुर्रा यह कि दूसरे दिन के अख़बारों में जहां हज कमेटी के चेयरमैन के वक्तव्यों को भरपूर कवरेज मिली, वहीं जनरल वीके सिंह को कोने में कहीं थोड़ी–सी जगह दी गई. जबकि हज के बारे में आधिकारिक तौर पर सभी निर्णय विदेश मंत्रालय ही लेता है. इससे पत्रकारों की इस मुद्दे को लेकर गंभीरता जाहिर हो जाती है. ■

हज कमेटी की प्रेस कांफ्रेंस

आम तौर पर हज कमेटी की तरफ़ से कोई ऐलान किया जाता है, तो समझा जाता है कि वह सरकारी फ़ैसला है. लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हज कमेटी एक ग़ैर सरकारी संस्था है. इसके हज यात्रा से संबंधित अधिकार सीमित हैं. हाजियों के संबंध में तमाम बड़े फ़ैसले विदेश मंत्रालय द्वारा लिए जाते हैं. हज कमेटी उन फ़ैसलों की देखरेख करती है. सऊदी अरब में हाजियों की देखरेख की ज़िम्मेदारी वहां स्थित वाणिज्य दूतावास की होती है. जहां तक हज कमेटी का सवाल है, तो उसे सही तथ्यों की जानकारी नहीं होती, लेकिन वह उसकी अपने कार्यक्रमों में घोषणा कर देती है. मसलन, छह जून को ही हज कमेटी के चेयरमैन शमीम कैसर ने प्रेस कांफ्रेंस में हज के संदर्भ में ऐसी बातें बताईं, जो जनरल सिंह के बयान से मेल नहीं खाती. हाजियों की रिहाइश की परेशानियों के बारे में जब शमीम कैसर से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ग्रीन कैटेगरी के लिए पांच टॉवरों का एक शानदार कॉम्पलेक्स चुन लिया गया है. हाजियों के रहने के लिए जिस कॉम्पलेक्स की बात कैसर कह रहे हैं, जनरल सिंह के अनुसार, वहां कमरों में रसोई घर नहीं है. रसोई की व्यवस्था होने पर ही अंतिम फ़ैसला होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लांग टर्म एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है. उस पर भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है. हज कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि वीआईपी को बैग का काम दे दिया गया, क्योंकि किसी और कंपनी ने निविदा नहीं भेजी. जबकि जनरल सिंह ने कहा कि वीआईपी और सैमसोनाइट के दाम एक जैसे थे, लेकिन हर शहर में डिलीवरी देने की सुविधा को ध्यान में रखकर वीआईपी को यह ज़िम्मेदारी दी गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर दिल्ली के मौजूदा विवाद के संबंध में संविधान क्या कहता है? इस मसले पर क़ानून के जानकारों की राय क्या उप-राज्यपाल के हक में है. एक अख़बार को दिए बयान में दिल्ली के चार मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके दिल्ली विधानसभा के सचिव के पद पर काम कर चुके एस के शर्मा कहते हैं कि अधिकारों को लेकर इस तरह कि लड़ाई मुख्यमंत्री और एलजी के बीच कभी नहीं हुई थी. उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का हवाला देते हुए कहा कि वे कहा करते थे कि वे केवल एक मुख्य सचिव हैं.

राज्य मंत्री के इशारे पर दी गई दबिश में झुलसे पत्रकार की मौत

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का अंजाम

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर ताकतवर नेताओं और मंत्रियों की करतूतों को उजागर करने वाले पत्रकारों या आम लोगों की जान आफत में है. ताकतवर मंत्री आजम खान के इशारे पर लोगों की गिरफ्तारियां और उत्पीड़न की घटनाएं सुर्खियों में रहीं. अब प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा के इशारे पर सोशल मीडिया से जुड़े शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह का उत्पीड़न करने और उन्हें जला कर मार डालने का मामला गरमा गया है. जलने से बुरी तरह जख्मी हुए पत्रकार की लखनऊ में आठ जून को मौत हो गई. उन्हें जख्मी हालत में लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पत्रकार की मौत की खबर आग की तरह फैलने के बाद पत्रकारों की नाराजगी के आगे शासन ने घुटने टेक दिए और राज्य मंत्री व इंस्पेक्टर समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया. राज्य मंत्री की गिरफ्तारी अभी (खबर लिखे जाने तक) नहीं हुई है.

आरोप है कि शाहजहांपुर के रहने वाले राज्यमंत्री राममूर्ति वर्मा ने पिछले दिनों अपने गुर्गों से सोशल मीडिया के एक पत्रकार को जिंदा जलाने की घटना को अंजाम दिया. पहले यह कह कर मामले को मोड़ देने की कोशिश की गई कि उत्पीड़न से तंग आए पत्रकार ने मंत्री के गुर्गों को अपने घर में घुसता देख अपने शरीर में आग लगा ली थी, लेकिन पत्रकार ने खुद मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में कहा था कि मंत्री के इशारे पर पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें जिंदा जला कर मारने की कोशिश की. पत्रकार को गंभीर हालत में लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्रदेश सरकार ने आरोपित मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और न ही मंत्री के खिलाफ घटना के फौरन बाद कोई एफआईआर लिखी गई थी. आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने जख्मी पत्रकार से सिविल अस्पताल जाकर मुलाकात भी की थी.

बताया गया कि बीते एक जून को दिन में आवास विकास कॉलोनी सदर बाजार, शाहजहांपुर स्थित मकान में सदर कोतवाल श्रीप्रकाश राय ने दबिश दी थी. वहां पत्रकार जगेंद्र सिंह पर राज्यमंत्री के गुर्गों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दिया. आग लगने से जगेंद्र 60 फीसदी से अधिक जल गए थे. अस्पताल में मुलाकात के दौरान जगेंद्र ने अमिताभ ठाकुर से कहा था कि राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा के इशारे पर इंस्पेक्टर श्रीप्रकाश राय ने यह सब किया. उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी 28 अप्रैल को उनके आवास के पास जानलेवा हमला किया गया, पर उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा हाल ही में बलात्कार के मामले में फंसने पर जगेंद्र को ही दोषी मानते थे. हमला कराने के पीछे यही वजह है. जगेंद्र के परिजनों का कहना था कि मंत्री राममूर्ति वर्मा की तमाम गड़बड़ियों, जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करने के कारण उन्हें यह सब झेलना पड़ रहा है. आईजी अमिताभ ठाकुर ने शाहजहांपुर के एसपी बबलू कुमार से फोन पर बात कर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने का अनुरोध किया था और डीजीपी ए के जैन को पत्र लिख कर मामले की जांच करवाने की मांग की थी.

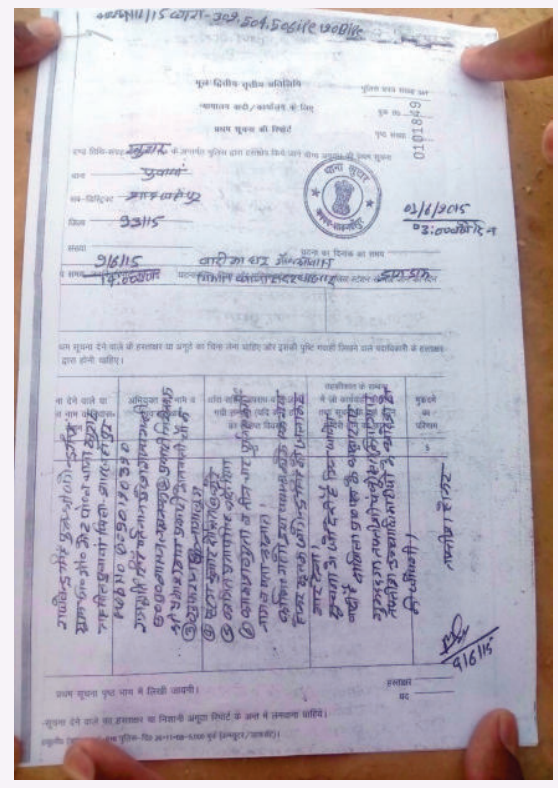

डीजीपी को लिखे पत्र में आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सिविल अस्पताल में बर्न वार्ड के बेड नंबर 15 पर भर्ती जगेंद्र सिंह से उन्होंने मुलाकात की थी. सिंह बुरी तरह जले हुए थे. वहां उनके दो बेटे राजवेन्द्र सिंह और पुष्पेन्द्र सिंह तथा उनकी पत्नी मिली थीं. जगेंद्र सिंह ने उनसे बताया था कि उन्हें राज्यमंत्री के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने और इस सम्बन्ध में खबर लिखने के कारण अनवरत प्रताड़ित किया जा रहा है. पत्रकार का यह भी कहना था कि एक जून 2015 को स्थानीय कोतवाल ने उनके घर पर दबिश दी और इस दौरान उन पर आग लगा दी. ये सारी बातें मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान किया हुआ है. लगभग यही बात उनके दोनों बेटों और पत्नी ने भी कही. श्री ठाकुर के पास जगेंद्र सिंह का वीडियो में बयान दर्ज है. इसके बावजूद डीजीपी ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की.

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में जो कुछ हुआ, वह वाकई दिल दहला देने वाला है. एक पत्रकार को सोशल मीडिया पर लिखने की कीमत यह चुकानी पड़ी कि एक मंत्री उसे परेशान करने लगा और मंत्री के इशारे पर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे पड़ गई और अंततः पत्रकार आग में झुलस कर मर गया. पिछले कई दिनों से पत्रकार जगेंद्र सिंह और राज्य मंत्री के बीच विवाद चल रहा था. इन्हीं विवादों के बीच पहले जगेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला हुआ, जिसकी रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज करवाई गई थी. इसके बाद पत्रकार जगेंद्र सिंह पर पिछले माह कोतवाली पुलिस ने एक युवक की तहरीर पर 307 का मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में पुलिस उनको गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची थी, जब आगजनी की घटना हुई. पुलिस ने घायल अवस्था में जगेंद्र सिंह को अपनी गाड़ी में डालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया. सूचना पाकर एसपी बबलू कुमार, एडीएम (फाइनेंस) प्रमोद श्रीवास्तव, एसडीएम सदर समेत कई अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे. एसडीएम सदर ने पत्रकार का मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज किया. इस मामले में एसपी बबलू कुमार का कहना है कि कोतवाली पुलिस जगेंद्र सिंह को धारा 307 के मुक़दमे में गिरफ्तार करने गई थी, उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली. एसपी ने एएसपी सिटी को मामले की जांच का भी आदेश दिया, लेकिन उस जांच का कोई नतीजा सामने नहीं आया, जबकि पत्रकार जगेंद्र जब तक जिंदा रहे, तब तक यह कहते रहे कि राज्य मंत्री के इशारे पर उन्हें जिंदा जलाया गया. उनका कहना था कि शाहजहांपुर कोतवाली पुलिस ने उनके मकान की दीवार से कूदकर उनके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. शाहजहांपुर के रहने वाले जगेंद्र सिंह राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ खबरें लिखने को लेकर चर्चा में रहे. लखनऊ सिविल अस्पताल में भी जगेंद्र ने कहा था कि यह इंस्पेक्टर श्रीप्रकाश राय द्वारा राज्यमंत्री राममूर्ति वर्मा के इशारों पर किया गया.

प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राममूर्ति वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण के नाम पर लाखों-करोड़ों की कोठी अपने लिए बना ली. वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ मंत्री पर ब्लात्कार का भी संगीन आरोप है. सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे पत्रकार जगेंद्र सिंह ने मंत्री के खिलाफ खूब लिखा. इस पर मंत्री ने उन पर जानलेवा हमला करवाया, जिसमें उनकी टांग तक टूट गई थी.

दोषियों पर कार्रवाई हो

शाहजहांपुर निवासी सोशल मीडिया पत्रकार जगेंद्र सिंह की संदेहास्पद स्थिति में मौत के दोषियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग की गई है. सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के साथ-साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी प्रदेश सरकार से यह मांग की है. जगेंद्र सिंह एक जून 2015 को दिन में अपने आवास विकास कॉलोनी, सदर बाज़ार स्थित मकान में सदर कोतवाल श्रीप्रकाश राय द्वारा दी गई दबिश के दौरान आग लगने से बुरी तरह जल गए थे. उनकी आठ जून को सिविल अस्पताल, लखनऊ में मौत हो गई. जगेंद्र ने उन्हें जलाने की घटना इंस्पेक्टर श्रीप्रकाश राय द्वारा राज्यमंत्री राममूर्ति वर्मा के इशारों पर किए जाने की बात कही थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. जगेंद्र ने राज्य मंत्री राममूर्ति द्वारा अवैध खनन, जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करने के कारण ऐसी घटना कराने का आरोप लगाया था. श्री ठाकुर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के कारण हुई इस मौत को एक अत्यंत गंभीर घटना बताते हुए सभी दोषी व्यक्तियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की है.

राज्य मंत्री पर हत्या का मुकदमा

पत्रकार की हत्या से नारा मीडिया के सामने झुकते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सहमति दे दी. इसके बाद शाहजहांपुर के पुवायां थाने में राज्य मंत्री राम मूर्ति सिंह वर्मा, शाहजहांपुर कोतवाली चौक के प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश राय, गुफरान, हृदय कुमार दीक्षित उर्फ घूरे, अमित प्रताप सिंह भदौरिया, आकाश गुप्ता व तीन-चार अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड़यंत्र) व कुछ अन्य संज्ञेय धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. नौ जून को हुई एफआईआर के बाद खबर लिखे जाने तक मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

मुख्यमंत्री-एलजी विवाद

आख़िर कब तक चलेगी वर्चस्व की लड़ाई

शफीक आलम

आम अदमी पार्टी जब से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है, उसका विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है. कुछ विवादों को राजनीति से प्रेरित कहा जा सकता है, लेकिन कुछ विवाद ऐसे हैं जो उसके अपने पैदा किए हुए हैं. आप देश में एक अलग तरह की राजनीति के वादे और एक असाधारण जनमत के साथ सत्ता में आ तो गई, लेकिन बहुत जल्द ही उसे यह अहसास हो गया कि अलग राजनीति की राह बहुत कठिन है. अभी कार्यकारी मुख्य सचिव और एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) के अधिकार और उनके अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर उप-राज्यपाल(एलजी) और आप सरकार के बीच रस्साकशी का खेल चल ही रहा था कि इसी बीच राज्य सरकार के कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्रीयों का मामला सामने आ गया. एलजी के साथ चले विवाद को राजनीति से प्रेरित साबित कहा जा सकता है, लेकिन जो पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई हो और उस पर लोगों ने इतना विश्वास जताया हो. उस पार्टी के एक मंत्री को फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस हिरासत लिया जाए, तो उस पार्टी की छवि को कितना नुक़सान होगा. इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है. क्योंकि यह बात बिलकुल साफ़ है कि आप के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिन दागी उम्मीदवारों के नाम पार्टी के आंतरिक लोकपाल को दिए थे. उनमें जितेंद्र तोमर का भी नाम शामिल था. यदि उसी वक्त तोमर की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई होती तो पार्टी को आज इस फज़ीहत से बच जाती, और उसकी साख पर बट्टा भी नहीं लगता.

बहरहाल तोमर की फर्जी डिग्री प्रकरण से पार्टी की छवि को जितना नुकसान होना था हो चुका. अब ख़बरें आ रही हैं कि तोमर को पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय पार्टी ने ले लिया है. कानून मंत्री के पद से तो उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया है. लेकिन मामले की जांच पुलिस अभी भी कर रही है, वहीं पत्नी के उत्पीड़न के मामले में पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर भी कार्रवाई कभी भी हो सकती है. उनकी पत्नी, दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करा चुकी हैं. शिकायत की जांच के बाद पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी. इससे दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ जायेगा. लेकिन अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल और नजीब जंग के बीच शुरू हुई जंग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है. इस लड़ाई की शुरुआत कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति से हुई थी. गैमलिन की नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने वाले दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिंदो मजुमदार को हटाकर उनकी जगह अरविंद केजरीवाल ने अपने सचिव राजेन्द्र कुमार को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया था. इस फैसले को बाद में एलजी नजीब जंग ने गैर क़ानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया था.

इस बीच एसीबी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी. जिसमें दिल्ली की शासन व्यवस्था में एलजी की भूमिका की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई थी. इसके साथ ही एसीबी के मामले में दिल्ली सरकार के सीमित अधिकारों की बात कही गई थी. इस अधिसूचना पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज किया था. लेकिन कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि अगर कोई संवैधानिक या क़ानूनी अड़चन न हो, उप-राज्यपाल को जनादेश का सम्मान करना चाहिए. हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में गृह मंत्रालय की अधिसूचना को संदिग्ध करार दिया था. इसपर गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की संदिग्ध की टिप्पणी को आधारहीन और गैरजरूरी करार देते हुए इसे खारिज कर दिया.

अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर दिल्ली के मौजूदा विवाद के संबंध में संविधान क्या कहता है? इस मसले पर क़ानून के जानकारों की राय क्या उप-राज्यपाल के हक में है. एक अख़बार को दिए बयान में दिल्ली के चार मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके दिल्ली विधानसभा के सचिव के पद पर काम कर चुके एस के शर्मा कहते हैं कि अधिकारों को लेकर इस तरह कि लड़ाई मुख्यमंत्री और एलजी के बीच कभी नहीं हुई थी. उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का हवाला देते हुए कहा कि वे कहा करते थे कि वे केवल एक मुख्य सचिव हैं. दिल्ली सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है. वहीं दिल्ली की अनोखी संवैधानिक स्थिति को संविधान की धारा 239 में साफ़ किया गया है, जिसके मुताबिक यहां एक मंत्री परिषद होगी. यहां मंत्रिमंडल कुल विधायकों की संख्या का 10 प्रतिशत के बराबर होगा, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे. विधायकों को कोई अधिकार नहीं है. उन्हें सिर्फ़ वही अधिकार हैं कि जो फैसला वह लें, उसे उप-राज्यपाल को भेजें. अब यह उप राज्यपाल पर निर्भर है कि उस फैसले को लागू करते हैं या नहीं. मामले को केंद्र सरकार के पास भी भेजा जा सकता है. केंद्र का फ़ैसला आने तक मामले में उप-राज्यपाल के निर्देश लागू होंगे. कहने का मतलब यह है कि दिल्ली के मौजूदा विवाद के मामले में क़ानूनी तौर पर उप- राज्यपाल का पक्ष भारी है. उनका यह कहना तर्कसंगत है कि दिल्ली के अधिकारियों की नियुक्ति उनके अधिकार क्षेत्र में हैं न कि राज्य सरकार के. लेकिन यह भी हकीकत है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार है. यदि यह सरकार अपनी पसंद के अधिकारियों को प्रमुख पदों पर नियुक्त करना चाहती है तो उप राज्यपाल को इसे अहम का विषय नहीं बनाना चाहिए. मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को भी इस संवैधानिक पद की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए. उन्हें यह भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र का अर्थ केवल टकराव ही नहीं होता, सहमति भी इसका एक अहम तत्व है. यदि केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो इसके लिए उप-राज्यपाल से टकराव के आलावा भी बहुत से रास्ते हैं.

जहां तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने का सवाल है तो दिल्ली की राजनीति में दखल रखने वाली तीनों पार्टियां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा सभी इस पक्ष में नज़र आती हैं. भाजपा तो साहेब सिंह वर्मा के मुख्यमंत्रित्व काल से यह मांग करती आई है, लेकिन इसके विपक्ष में यह दलील दी जाती है कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए इससे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की राह में कई तरह की तकनीकी अड़चने हैं. ऐसे में यह सवाल भी उठ सकता है कि यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, तो फिर एक चुनी हुई सरकार की यहां आवश्यकता क्या है. जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री कहा करते थे कि उनकी हैसियत एक मुख्य सचिव की है. एक मुख्य सचिव के होते हुए दूसरे की आवश्यक्ता क्या है. एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं ऐसे में टकराव होना लाजिमी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोदी के अधिनायकवाद के ख़िलाफ़ विद्रोह का बिगुल

जोशी और कटियार ने ठोंकी ताल

जोशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना पर भी तीखा कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, गंगा में जहाज चलाना तो दूर, बड़ी नाव भी नहीं चल पाएगी, जबकि गडकरी कह रहे हैं कि भारी उत्पादों की ढुलाई के लिए गंगा नदी में बड़े-बड़े पोत चलाएंगे. उन्हें गंगा की मौजूदा स्थिति का तो पता लगा लेना चाहिए. जोशी का आशय नदियों की हालत और उसकी भौगोलिक स्थिति को लेकर जहाजरानी मंत्रालय के सामान्य ज्ञान से था. जिन पंडित महामना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देकर भाजपाई अघाते नहीं, उन्हीं महामना की उपेक्षा करने का जोशी ने आरोप लगाया. कहा कि महामना ने नदी में जल प्रवाह कायम रखने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था और हरिद्वार में गंगा नदी में सतत प्रवाह का न्यूनतम स्तर कायम रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था. इसका अंग्रेजों के शासनकाल तक पालन होता रहा, लेकिन अब इसकी घोर उपेक्षा की जा रही है.

प्रभात रंजन दीन

केंद्र में भाजपा की सरकार कहने से अधिक सटीक और प्रासंगिक नरेंद्र मोदी की सरकार कहना होता है, जिसके एक साल पूरा होने पर सरकार, मंत्री और नेता फूले नहीं समा रहे. मथुरा में मोदी की रैली से लेकर तमाम आयोजनों–प्रायोजनों के जरिए सालभर का गुणगान जबरन परोसा जा रहा है, लेकिन इस बात पर चुप्पी सधी हुई है कि सालभर बीतते–बीतते नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध के स्वर मुखर क्यों होने लगे. विरोध के स्वर डॉ. मुरली मनोहर जोशी के गंगा सफाई को लेकर हों या राम मंदिर निर्माण के मसले पर विनय कटियार के हों या किसी अन्य मुद्दे पर किसी अन्य नेताओं के, विरोध का निशाना नरेंद्र मोदी ही हैं, जिनकी अधिनायकी पर राजनीतिकों की सालभर की चुप्पी बहुत है. विनय कटियार ने यहां तक कह दिया कि चंद्रशेखर कुछ और दिन प्रधानमंत्री रह गए होते तो राम मंदिर बन चुका होता.

बहरहाल, केंद्र सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर मथुरा के नगला चन्द्रभान में आयोजित रैली में मोदी ने अपनी सरकार का सालभर का हिसाब–किताब पेश करने की कोशिश की, लेकिन यह लेखा–जोखा जनता को उतना प्रभावित नहीं कर पाया. मोदी ने अपने कार्यों का जो हिसाब दिया, उस पर जनता ने उन्हें पूरा नम्बर नहीं दिया. विपक्षी पार्टियां तो उन्हें जीरो नम्बर दे ही रही हैं. यह भी अहम है कि विपक्ष के मूल्यांकन से आम जनता असहमत ही है. मोदी के एक साल के कार्यकाल की समीक्षा करते वक्त विपक्षी पार्टियां यह ईमानदारी से नहीं सोच पा रही हैं कि जब वे सत्ता में थीं तो उन्होंने सालभर में क्या किया था और एक साल में विकास के कितने कीर्तिमान स्थापित किए थे. उंगली उठाने की तेज हुए सियासी प्रतिस्पर्धा का दिलचस्प पहलू यह है कि विपक्ष अपनी सरकार के एक वर्ष वाले पहलू पर भूल से भी बात नहीं कर रहा.

खैर, भाजपा संसदीय दल में उठने वाली विरोध की आवाजें, भविष्य के संकेत देने लगी हैं. सांसदों का यह असंतोष सांसद निधि के प्रति उपेक्षा से भी जाहिर हो रहा है. यह तथ्य प्रकाश में आ चुका है कि खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी ही सांसद–निधि का इस्तेमाल करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे. यह अरुचि बड़े मामले से लेकर अत्यंत छोटे मामले तक प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप को लेकर है. कई सांसदों का कहना है कि भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री की अतिरिक्त संलग्नता एक नकारात्मक माहौल भी पैदा कर रही है. सांसदों में संदेश यह जा रहा है कि जब सारे सांसदों को संदेहास्पद मानकर उन पर निगरानी रखी जा रही है, तो वे काम में दिलचस्पी क्यों लें. फिर ईमानदारी का पूरा पदक वही लोग लें, जो सत्ता केंद्र के नजदीक हैं. राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह दशा चिंताजनक होती है, क्योंकि एक ईमानदार और बाकी सब बेईमान, वाली आत्मकेंद्रित विचारधारा संगठन को मुख्य धारा से वंचित कर देती है. कुछ यही दशा भारतीय जनता पार्टी की हो रही है.

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, लालजी टंडन जैसे कई अन्य वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की सोची–समझी उपेक्षा नरेंद्र मोदी के लिए शीघ्र ही भारी पड़ने वाली है. यह मोदी को समझ में नहीं आ रहा है और उनके सिपहसालार उन्हें यह समझने भी नहीं दे रहे हैं. गंगा की सफाई और नमामि गंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय एजेंडे के रूप में प्रचारित है. इस पर प्रहार का मतलब ही है नरेंद्र मोदी पर प्रहार. राजनीतिक अनुभव के धनी बुद्धिजीवी मुरली मनोहर जोशी ने गंगा की सफाई के मसले पर जमीनी स्थिति को देखते हुए जब यह कहा कि गंगा अगले 50 साल में भी साफ नहीं हो सकेगी, ने भाजपा की अंदरूनी सियासत में भूचाल मचा दिया है. ऊपर–ऊपर जो शांति दिख रही है, वह तूफान के आने के पहले वाला सन्नाटा है. स्वच्छ गंगा परियोजना पर जोशी ने अपनी धारदार आपत्ति दर्ज की. जोशी ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम नमामि गंगे पर अलग रुख अख्तियार करने की सार्वजनिक अभिव्यक्ति दी और स्पष्ट कहा कि गंगा नदी की सफाई के लिए जिस तरह से परियोजना चलाई जा रही है, उससे अगले 50 साल में भी नदी साफ नहीं हो सकेगी. उन्होंने कहा, जब तक नदी में निर्बाध जल प्रवाह नहीं होता, गंगा की सफाई दूर का सपना होगा. जिस तरह नदी को छोटे हिस्सों में बांटकर, छोटे जलाशयों में बदलकर इसकी सफाई की जा रही है, नदी अगले 50 साल में भी साफ नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि गंगा हमारी जीवनरेखा है और गंगा पर मंडराया कोई खतरा हमारी संस्कृति और परंपरा के लिए खतरनाक होगा.

जोशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना पर भी तीखा कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, गंगा में जहाज चलाना तो दूर, बड़ी नाव भी नहीं चल पाएगी, जबकि गडकरी कह रहे हैं कि भारी उत्पादों की ढुलाई के लिए गंगा नदी में बड़े–बड़े पोत चलाएंगे. उन्हें गंगा की मौजूदा स्थिति का तो पता लगा लेना चाहिए. जोशी का आशय नदियों की हालत और उसकी भौगोलिक स्थिति को लेकर जहाजरानी मंत्रालय के सामान्य ज्ञान से था. जिन पंडित महामना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देकर भाजपाई अघाते नहीं, उन्हीं महामना की उपेक्षा करने का जोशी ने आरोप लगाया. कहा कि महामना ने नदी में जल प्रवाह कायम रखने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था और हरिद्वार में गंगा नदी में सतत प्रवाह का न्यूनतम स्तर कायम रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था. इसका अंग्रेजों के शासनकाल तक पालन होता रहा, लेकिन अब इसकी घोर उपेक्षा की जा रही है.

सियासत में रोचक मोड़ तब आ गया, जब द्वारिका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी मुरली मनोहर जोशी के समर्थन में आगे आ गए. शंकराचार्य ने कहा कि गंगा सफाई को लेकर मुरली मनोहर जोशी ने जो साहसिक कदम उठाए, वह बिल्कुल सही और सराहनीय है. सरस्वती ने कहा कि गंगा नदी को उत्तराखंड से लेकर बनारस तक कई जगह बांध दिया गया है, जिससे गंगा में अब जल ही नहीं रह गया तो ऐसी स्थिति में जहाज कहां से चलेंगे. उन्होंने कहा कि नदी की शुद्धि उसके वेग से होती है, जब उसके जल में वेग ही नहीं होगा तो उसके जल की शुद्धि कहां से होगी.

भाजपा के कई मौजूदा प्रभावशाली नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी के बयान का राजनीतिक गुणा–गणित समझने में लगे हैं. मोदी के खिलाफ चूं नहीं निकालने का जो खौफ सालभर बरपा था, वह लीक होने लगा है, अब उसकी हवा निकलना शुरू हो गई है. अभी तो मोदी–परिधि के नेता भाजपा नेता व सांसद विनय कटियार के नीतिगत हमले के ही राजनीतिक निहितार्थ समझने में लगे थे कि जोशी मसला सामने आ गया. इसके पहले पूर्वोत्तर के भाजपा नेता के सीधे प्रहार और उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसद के पत्र से वे बौखलाहट से भरे पड़े थे.

राम मंदिर को लेकर विनय कटियार का बयान तब आया, जब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या जाकर पार्टी की विवशता जाहिर कर दी. राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कह दिया था कि राम मंदिर का मसला तभी उठेगा, जब राज्यसभा में भी बहुमत होगा. यानी पांच साल के अगले पांच साल का सियासी एजेंडा फिट करने की राजनाथ ने कोशिश की. विनय कटियार ने इसे धो डाला. कटियार ने कहा कि भाजपा सरकार राम मंदिर बनाने का कानून लोकसभा में लाए, जहां उसे बहुमत प्राप्त है. इससे जनता के पास यह स्थिति साफ होगी कि भाजपा सरकार की मंशा में कोई खोट या सियासत नहीं है. कटियार बोले कि लोकसभा में तो हमारा बहुमत है ही. हम लोकसभा में पारित करें. कानून बनाएं. राज्यसभा में नहीं है, तो देखेंगे और फिर संयुक्त सत्र बुलाकर हम कानून बना ही सकते हैं.

विनय कटियार का कहना था कि राम मंदिर निर्माण की पहल करने में केंद्र सरकार के सामने कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है. इस मामले में मौजूदा केंद्र सरकार का रास्ता पूर्व की संप्रग सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र ही खोल दे रहा है. शपथ पत्र में संप्रग सरकार ने कहा था कि यदि साबित हो जाए कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी ढांचे को तोड़कर हुआ था, तो वह हिंदुओं की मांग का समर्थन करते हुए मंदिर निर्माण में सहयोग करेगी. कटियार ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो चुका है कि वहां पहले मंदिर था और आर्कियॉलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर लोकसभा में कानून पास करने का ये अच्छा वक्त है. केंद्र सरकार के सामने मंदिर निर्माण की दिशा में सहयोग को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. कटियार ने कहा कि मंदिर निर्माण की उपेक्षा ठीक नहीं है और इससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं. कटियार यह भी कह चुके हैं कि मंदिर निर्माण में देरी से रामभक्तों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट सकता है.

विनय कटियार ने सुझाव दिया कि मंदिर निर्माण का कानून बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल की तरह केंद्र सरकार लोकसभा में प्रस्ताव पेश करके इसे पारित कराने का प्रयास करे. कटियार ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार का प्रयास सबका साथ, सबका विकास के ही अनुरूप होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर व अटल विहारी वाजपेयी ने इस विवाद में बातचीत के जरिये समाधान की दिशा में ठोस पहल की थी, लेकिन समय कम होने के कारण दोनों नेताओं की इस दिशा आगे कुछ नहीं हो सका. यह महज एक संयोग नहीं माना जाना चाहिए कि विनय कटियार के बयान पर भी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि राममंदिर निर्माण को संसद में बहुमत की नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति की आवश्यकता है. भाजपा राज्यसभा में बहुमत न होने की बात उठाकर इस मामले में देश की जनता को भ्रमित कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 1990 में ही राममंदिर समेत आसपास की 65 बीघा जमीन का अधिग्रहण कर चुकी है. कोर्ट में सरकार के इस फैसले को न तो किसी ने अब तक कोई चुनौती दी है और न ही कोर्ट ने ही इस पर कोई सवाल उठाया है. ऐसे में सरकार को अपनी जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए किसी इजाजत की कोई जरूरत ही नहीं है. सदन में बहुमत की बात बेवजह की जा रही है. शंकराचार्य ने कहा कि कारसेवकों का 1990 में ढांचा गिराना बड़ी गलती थी, क्योंकि विवादित ढांचा मस्जिद नहीं थी. ऐसा करके कारसेवकों ने मुस्लिम समुदाय को यह कहने का मौका दिया कि वहां मस्जिद थी. विनय कटियार ने यह कह कर भी भाजपा नेताओं को बौखलाया है कि चंद्रशेखर यदि एक महीना और प्रधानमंत्री रह गए होते तो राममंदिर बन जाता. कटियार ने कहा कि चंद्रशेखर जी चार महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे और यह समस्या समाधान के नजदीक पहुंच गई थी. अगर वह एक महीने और प्रधानमंत्री रहते तो राममंदिर बन गया होता. उन्होंने कहा, जहां तक मोदी सरकार का सवाल है, एक साल बीत गया है पर अभी तक कोई कदम नहीं उठा है, नहीं उठाया गया है.■

feedback@chauthiduniya.com

सुलग रहा विद्रोह

अभी कुछ ही अर्सा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके प्रिय अमित शाह के खिलाफ असम के भाजपा नेता प्रद्युत बोरा का विद्रोह सुर्खियों में रहा था. बोरा ने इन दोनों पर पार्टी के लोकतांत्रिक ढर्रे को तबाह करने का खुला आरोप लगाया और इस्तीफा दे दिया. यह मोदी अधिनायकवाद के खिलाफ पहला विद्रोह था. बोरा ने कहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की प्राथमिकताओं में असम के लोगों के सरोकार सबसे निचले पायदान पर हैं. बोरा ने लिखा कि पार्टी ने असम से बांग्लादेशियों को बाहर करने का वादा किया था, लेकिन आज क्या हुआ? तब बोरा ने भी यह सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्टा बांग्लादेश की सद्भावना यात्रा पर चले जाएंगे और अपने सवा सौ गांव देकर और 50 गांव लेकर ऐतिहासिक समझौता कर आएंगे. बोरा ने तब विदेश सचिव को अपमानजनक तरीके से हटाए जाने पर विरोध जताया था और मोदी के इस रवैये पर गहरा खेद जताया था कि कोई कैबिनेट मंत्री अपना ओएसडी तक तैनात नहीं कर सकता. क्या इस देश में कोई कैबिनेट सिस्टम अस्तित्व में रह गया है? यह शर्मनाक स्थिति है कि कोई कैबिनेट मंत्री, पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी और सांसद मोदी से इन मसलों पर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता.

अभी हाल ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण शौरी ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए थे और मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा किया था. उसके बाद पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जालौन से भाजपा सांसद भानु प्रताप वर्मा के विद्रोह पत्र ने बवाल मचा दिया. हालांकि बाद में वर्मा ने कहा कि उस पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, लेकिन तब तक मुद्दा तो तीर की तरह निकल ही चुका था. सांसद के उस पत्र में भाजपा को चार गुजरातियों के हाथों का खिलौना बताया गया और कहा गया कि पार्टी में अपनापन का भाव समाप्त करके कॉरपोरेट संस्कृति अपनाई जा रही है. मोदी के आतंक का संकेत देते हुए कहा कि कांग्रेस में केवल एक मनमोहन हैं, पर भाजपा नेतृत्व ने तो हम सबको मौन–मोहन बना रखा है. क्या पार्टी और देश को केवल चार गुजराती (मोदी, शाह, अंबानी और अदाणी) चलाएंगे? कश्मीर मामले पर भी मोदी की कड़ी आलोचना की गई है. सांसद वर्मा ने आधिकारिक तौर पर इस पत्र को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पार्टी में जो हालात हैं, पत्र उन्हीं स्थितियों का खुलासा कर रहा है. पार्टी के कई नेताओं का दर्द यही है, लेकिन वे चुप हैं. प्रदेश की राजनीति में अग्रिम पंक्ति में रहे लालजी टंडन, विनय कटियार, सूर्य प्रताप शाही, ओमप्रकाश सिंह और हृदय नारायण दीक्षित जैसे नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया गया है. पार्टी के फायर ब्रांड युवा चेहरे के तौर पर चमके वरुण गांधी को भी परिदृश्य से गायब कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश पर बाहर से टपकाए गए नेता कोई असर नहीं बना पा रहे. पार्टी महासचिव और प्रदेश के प्रभारी बनाए गए ओम माथुर भी भाजपा की दुर्गति के ही गवाह बन रहे हैं. लोकसभा चुनाव में जीत का सेहरा अकेले अमित शाह के सिर बांधने से वे कार्यकर्ता भी ज्वालामुखी बने बैठे हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पर पूरे उत्साह से काम किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला. अब वे फटने के लिए तैयार बैठे हैं.

लब्बोलुबाव यह है कि भाजपा का आत्मसमीक्षा का भाव तिरोहित हो गया है और इसी वजह से दिल्ली के साथ–साथ उत्तर प्रदेश के सारे उपचुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा. बिहार भी चुनौती की तरह सामने खड़ा है। बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का ही चुनाव होना है. भाजपा के लिए यह संक्रमण काल है. पार्टी के अंदर बढ़ रही वैमनष्यता, अलगाव, निराशा और भाजपा सांसदों का रवैया पार्टी के लिए बेहद चिंताजनक परिस्थितियां पैदा कर रहा है.■

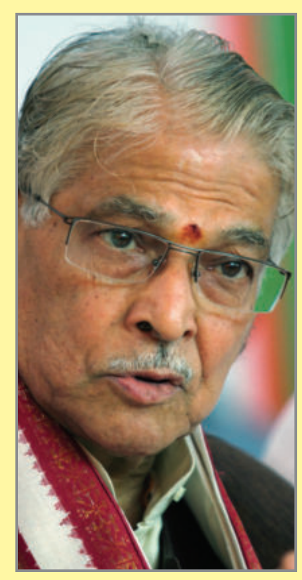

फोटो–प्रभात पाण्डेय

जनता परिवार व भाजपा–विरोधी अन्य दलों के इस गठबंधन के आकार लेने व नीतीश कुमार को नेता घोषित कर देने के बाद राज्य की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. यह बात सही है कि बिहार के अनेक दबंग सामाजिक समूहों में लालू प्रसाद को लेकर अब भी नाराजगी के स्तर तक आपत्ति है, लेकिन उनमें अनेक ऐसे तबके हैं, जिनकी सहानुभूति नीतीश कुमार व उनके राजनीतिक आचरण में है. नीतीश कुमार की राज–काज (गर्वनेंस) की शैली बिहार की बड़ी आबादी को आकृष्ट करती है. बिहारी मतदाताओं का बहुत बड़ा तबका उन्हें राजनीति की कई संक्रामक बीमारियों से मुक्त मानता है. फिर, नीतीश कुमार की छवि विकास–पुरुष की बन गई है.

लालू और नीतीश की एकजुटता ने बिगाड़ा भाजपा का खेल

बिहार की राजनीति को अब भाजपा से भावी नेता की अपेक्षा है, लेकिन लगता है, बिहार की जनता की यह अपेक्षा पूरी नहीं होगी. प्रदेश भाजपा पिछले कई वर्षों से अनेक गुटों में बंटी है और गंभीर अन्तःकलह से पीड़ित है. जितने गुट, उतने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं. राज्य के नेताओं को तो जाने दीजिए, कई केन्द्रीय मंत्री तक सींका के टूटने की प्रतीक्षा में ही नहीं, उसे अपने पक्ष में तोड़ने में लगे हैं. इसलिए भावी नेता की घोषणा का चुनावी राजनीति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. ऐसे में पार्टी नेतृत्व के लिए जरूरी है कि सारा कुछ अस्पष्ट ही रहने दिया जाए. अभी तक के संकेत तो यही हैं कि बिहार में भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को पेश नहीं करेगी और नरेन्द्र मोदी के करिश्माई व सौदागरी राजनीतिक व्यक्तित्व और केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को भुनाने का ही काम करेगी. लगता है, इस चुनाव में मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार केवल नीतीश कुमार ही होंगे और मुकाबले को नरेन्द्र मोदी ही रहेंगे.

सुकान्त

लंबे जद्दोजहद और अगर–मगर के अनेक पड़ावों से गुजरने के बाद बिहार में भाजपा, व्यापक अर्थ में राजग विरोधी गठबंधन ने अंततः आकार ग्रहण कर लिया. गठबंधन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बतौर इसके नेता की घोषणा मुलायम सिंह यादव ने गत दिना कर दी. इस लिहाज़ से आसन्न विधानसभा चुनावों के संदर्भ में जनता परिवार और भाजपा विरोधी दल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से एक कदम आगे निकल गए. वस्तुतः गठबंधन पहले भी आकार ग्रहण कर सकता था, पर ताज़ और राज के विवाद में यह फंस गया था और जनता परिवार के दोनों बिहारी नायक–नीतीश कुमार व लालू प्रसाद–इस मुद्दे पर एक–दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे. अंत भला तो सब भला–सारा विवाद सुलझ गया. राजद सुप्रीमो ने जहर पीकर जद (यू) सुप्रीमो नीतीश कुमार को चुनाव में अपना नेता मान लिया, उनके नाम का प्रस्ताव कर दिया. अर्थात् विधानसभा चुनाव में भाजपा विरोधी गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार होंगे और उनके नाम पर गठबंधन वोट मांगने निकलेगा. इस गठबंधन में जद (यू) और राजद के अलावा कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) भी शामिल रहेगी. हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं. इस गठबंधन के आकार लेने के साथ विधानसभा चुनाव का परिदृश्य बदल गया है. अब बिहार की सत्ता हासिल करने को बेताब भाजपा के लिए चुनावी विसात सहज नहीं रही. राज्य के प्रायः सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सीधी टक्कर तय हो गई है. गठबंधन में नेता का मसला तो सुलझ गया और सीटों के वितरण के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. इसमें जद (यू) और राजद के तीन–तीन सदस्य होंगे. समिति सीटों के वितरण का फॉर्मूला तो तैयार करेगी ही, विवादित सीटों को चिह्नित कर मसले के निपटारे का उपाय भी ढूंढ़ेगी. वैसे, राजद और जद (यू) के सूत्रों पर भरोसा करें तो यह काम भी रास्ते पर आ चुका है. जद (यू) और राजद के खाते में सौ–सौ सीटें जाएंगी, जबकि शेष 43 सीटों का बंटबारा अन्य दलों में किया जाएगा. कहते हैं, इसी फॉर्मूले के तहत विधान परिषद चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ है. परिषद के नगर निकाय निर्वाचन क्षेत्र की सभी 24 सीटों के लिए जुलाई में चुनाव हो रहे हैं और इसमें राजद–जद (यू) के जिम्मे दस–दस पड़ी हैं और कांग्रेस को तीन व राकांपा को एक सीट मिली है. गठबंधन के नेता परिषद चुनाव में सीटों के इस सहज वितरण को उपलब्धि मान रहे हैं. हालांकि विधानसभा चुनावों के लेकर सीटों का वितरण इसी सहजता से हो जाएगी, यह कहना कठिन है.

जनता परिवार व भाजपा–विरोधी अन्य दलों के इस गठबंधन के आकार लेने व नीतीश कुमार को नेता घोषित कर देने के बाद राज्य की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. यह बात सही है कि बिहार के अनेक दबंग सामाजिक समूहों में लालू प्रसाद को लेकर अब भी नाराजगी के स्तर तक आपत्ति है, लेकिन उनमें अनेक ऐसे तबके हैं, जिनकी सहानुभूति नीतीश कुमार व उनके राजनीतिक आचरण में है. नीतीश कुमार की राज–काज (गर्वनेंस) की शैली बिहार की बड़ी आबादी को आकृष्ट करती है. बिहारी मतदाताओं का बहुत बड़ा तबका उन्हें राजनीति की कई संक्रामक बीमारियों से मुक्त मानता है. फिर, नीतीश कुमार की छवि विकास–पुरुष की बन गई है. घोर पिछड़ापन के बाद उन्होंने इस राज्य में विकास की नई लौ जगाई और आमजन में विकास की भूख जगी. उनकी यह छवि मतदाताओं के कई समूहों को पसंद आ रहा है. हालांकि यह भी सही है कि ऐसे मतदाता समूहों के बड़े तबके को लालू प्रसाद के साथ उनका होना रास नहीं आ रहा है, लेकिन कई मोर्चे पर नीतीश कुमार जांचे–परखे राजनेता व प्रशासक हैं. इसलिए एकबारगी उन्हें दरकिनार करना असंभव नहीं, तो कठिन जरूर है. उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की ये ताकत गठबंधन को लाभ पहुंचाएगी, तो भाजाप की परेशानी भी बढ़ाएगी. नीतीश कुमार और उनके राजनीतिक (चुनाव) प्रबंधकों को इसका अनुमान है, इसीलिए उनके चुनाव अभियान के लॉचिंग का तौर–तरीका बदल दिया गया है. चुनाव अभियान की शुरुआत, अनौपचारिक ही सही, एक हाइटेक रथ से की गई है. इस हाइटेक रथ के जरिए नीतीश कुमार के गत दस साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ–साथ अगले दस साल के बिहार के विकास की रूपरेखा पेश की गई है–विजन 2025. यह हाइटेक रथ राज्य के गांवों में जाएगा, लोगों को उपलब्धियों और भावी कार्यक्रम की जानकारी देगा, उनकी राय ली जाएगी और फिर गठबंधन का चुनावी घोषणा–पत्र तैयार किया जाएगा. नीतीश कुमार इस लिहाज से चुनाव अभियान को एक नया आयाम दे रहे हैं–राजनीतिक कार्यक्रम तय करने में जन–भागीदारी सुनिश्चित करने की चेष्टा कर रहे हैं. आसन्न विधानसभा चुनाव में विजन 2025 अपने ढंग का पहला कार्यक्रम है. इसके समानान्तर ऐसा कोई सार्वजनिक अभियान भाजपा ने अब तक आरंभ नहीं किया है. इस लिहाज़ से गठबंधन एक कदम आगे है. इस हाइटेक रथ के जरिए नीतीश कुमार भाजपा के पर्चा अभियान का जवाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं. भाजपा ने एनडीए के साढ़े सात साल बनाम दो साल नाम से चार पेज का एक पर्चा छपवाया है और राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में उसका वितरण कर रही है. इसमें जद(यू) सरकार (16 जून, 2013 के बाद की नीतीश सरकार) की विफलता और कुशासन की बात की गई है.

नीतीश कुमार के लिए लालू-फैक्टर कम महत्वपूर्ण नहीं है. यह अब साफ हो गया है कि कांग्रेस का स्टैंड बिहार के इस राजनीतिक ध्रुवीकरण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व साबित हुआ. उसने भावी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को पेश करने का अनौपचारिक सुझाव देकर गठबंधन के प्रस्ताव को मूर्त्त करने में मदद की. फिर, लालू प्रसाद सामने आए और उन्होंने ताज़ अपने छोटे भाई को देने की बात कही. फिर गठबंधन ने आकार ग्रहण किया, लेकिन गठबंधन के लिए अगला दौर इतना आसान नहीं है.

बिहार की राजनीति को अब भाजपा से भावी नेता की अपेक्षा है, लेकिन लगता है, बिहार की जनता की यह अपेक्षा पूरी नहीं होगी. प्रदेश भाजपा पिछले कई वर्षों से अनेक गुटों में बंटी है और गंभीर अन्तःकलह से पीड़ित है. जितने गुट, उतने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं. राज्य के नेताओं को तो जाने दीजिए, कई केन्द्रीय मंत्री तक सींका के टूटने की प्रतीक्षा में ही नहीं, उसे अपने पक्ष में तोड़ने में लगे हैं. इसलिए भावी नेता की घोषणा का चुनावी राजनीति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. ऐसे में पार्टी नेतृत्व के लिए जरूरी है कि सारा कुछ अस्पष्ट ही रहने दिया जाए. अभी तक के संकेत तो यही हैं कि बिहार में भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को पेश नहीं करेगी और नरेन्द्र मोदी के करिश्माई व सौदागरी राजनीतिक व्यक्तित्व और केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को भुनाने का ही काम करेगी. लगता है, इस चुनाव में मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार केवल नीतीश कुमार ही होंगे और मुकाबले को नरेन्द्र मोदी ही रहेगें. यह सही है कि देश के सबसे बड़े वोट–जुगाड़ू राजनेता का नाम नरेन्द्र मोदी है. भारतीय मतदाताओं में उनका जादू बरकरार है. पर, यह भी सही है कि संसदीय चुनाव के दौरान जिस लोकप्रियता के शिखर पर नरेन्द्र मोदी थे, वह स्थिति अब नहीं है. यह लोकप्रियता अब ढलान की ओर है. लोग अब सरकार के कामकाज और निर्णयों को लेकर सवाल करने लगे हैं. फिर, यह विधानसभा चुनाव है. छोटे–छोटे स्थानीय मसले भी इस चुनाव के दौरान नासूर जैसे बन जाते हैं. यह देश का सवाल नहीं, राज्य के राज–काज पर फैसला देने का वक्त होता है. इसलिए भाजपा के लिए नरेन्द्र मोदी या केन्द्र सरकार एक सीमा तक काफी उपयोगी हो सकती है. बिहार को लेकर केन्द्र सरकार की नई–नई घोषणाएं इसी रणनीति का हिस्सा है. यह रणनीति भाजपा विरोधी गठबंधन और इसके नेता नीतीश कुमार के लिए परेशानी के सबब बन सकती हैं. इसका मुकाबला कैसे किया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा. इस गठबंधन से मुकाबले को भाजपा नया पैंतरा ले रहा है. वह नीतीश कुमार पर कम, लालू प्रसाद को अपने निशाने पर अधिक ले रहा है. वस्तुतः ऐसा कर भाजाप खुद को बहुत सारी जवाबदारी से बचा रही है. नीतीश कुमार के साथ वह भी साढ़े सात साल तक सरकार में रही और जून 2013 से पहले के सरकार के गलत–सही निर्णयों में वह भी बराबर की भागीदार है. उन दिनों भी सरकार के घपले–घोटाले की खबरें आई थी, भाजपा के लोगों को भी इसमें लाभ मिलने की खबर आई थी. इसलिए भाजपा के लिए नीतीश कुमार को बख्शना ही बेहतर है, वह यही कर भी रही है.

नीतीश कुमार के लिए लालू–फैक्टर कम महत्वपूर्ण नहीं है. यह अब साफ हो गया है कि कांग्रेस का स्टैंड बिहार के इस राजनीतिक ध्रुवीकरण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व साबित हुआ. उसने भावी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को पेश करने का अनौपचारिक सुझाव देकर गठबंधन के प्रस्ताव को मूर्त्त करने में मदद की. फिर, लालू प्रसाद सामने आए और उन्होंने ताज़ अपने छोटे भाई को देने की बात कही. फिर गठबंधन ने आकार ग्रहण किया, लेकिन गठबंधन के लिए अगला दौर इतना आसान नहीं है. लालू प्रसाद के कारण माय (मुस्लिम–यादव) के समर्थन की पूरी उम्मीद गठबंधन को है. कांग्रेस और लालू प्रसाद के होने के कारण मुस्लिम वोट के इस गठबंधन में थोक भाव से आने की आस है. पर, यादव मतदाताओं में दरार पैदा होने की आशंका पैदा हो रही है. इसका एक सिरा पप्पू यादव भी हो सकते हैं. इस संभावित दरार से लाभ हासिल करने को भाजपा भी बेताब है, वह पप्पू यादव को प्रत्यक्ष–परोक्ष तरीके से संपोषित तो करेगी ही, एनडीए में यादव प्रत्याशी की संख्या भी काफी बढ़ा देगी. भाजपा विरोधी गठबंधन के लिए इसका मुकाबला जरूरी है. पर कैसे? यह अब तक साफ नहीं हो सका है. वैसे, गठबंधन यादववाद से खुद को मुक्त रखने (कम से कम मुक्त दिखने की भी) की कोशिश करेगा और यहीं नीतीश कुमार के कौशल की परीक्षा होनी है. फिर, एक संकट और है. सूबे वैसे मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी है, जो भाजपा की अघोषित राजनीति और नेतृत्व के मंडलवादी नजरिए से आहत हैं और उसे वोट नहीं करना चाहते, लेकिन लालू प्रसाद के साथ होने के कारण नीतीश कुमार के भी निकट नहीं आ रहे हैं. ऐसे मतदाता अगड़ी जातियों के साथ–साथ पिछड़ी और अतिपिछड़ी जातियों में भी हैं. इन मतदाता समूहों का समर्थन हासिल करने के ठोस उपाय की तलाश नीतीश कुमार के राजनीतिक कौशल की अग्निपरीक्षा होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

मिलावटखोरों को फांसी दो

पिछले दिनों दिल्ली सहित देश के अधिकांश राज्यों में नैस्ले का प्रमुख उत्पाद मैगी खाद्य मानकों पर खरी नहीं उतरी. मैगी में लेड की मात्रा तय मानक से सात गुना ज़्यादा मिली. इसी के साथ हमेशा की तरह केंद्र और राज्य सरकारें उपभोक्ता अधिकारों के प्रति तथाकथित संजीदगी दिखाने में जुट गई हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, खाद्य पदार्थों के मसले पर कभी भी गंभीर नहीं रहीं. यदि सरकार चाहती, तो देश के डिब्बाबंद और प्रॉसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में बेहतर लेबलिंग, पैकेजिंग व परीक्षण के नियम सामने आ सकते थे, जिससे जनता अभी तक वंचित है. यही कारण है कि नैस्ले से पहले भी प्रमुख ब्रांड्स कैडबरी, केएफसी, कोका कोला भी भारत सहित अन्य देशों में अपने उत्पादों में समय-समय पर मिलावट करते रहे या उनके उत्पाद तय मानकों पर असफल पाए गए, लेकिन उक्त कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि आज भी उनके उत्पाद बाज़ार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं. सवाल यह है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाली कंपनियों पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी भी या इसी तरह उपभोक्ताओं की ज़िंदगी से खिलवाड़ चलता रहेगा?

राजीव रंजन
feedback@chauthiduniya.com

चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं. अब मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए. मैं अच्छे दिन ले आया. लेकिन, उपभोक्ताओं के अच्छे दिन तो तभी आएंगे, जब उन्हें शुद्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति होगी. मैगी में मिलावट का मामला तो एक छोटा-सा नमूना भर है. यदि गंभीरता से जांच की जाए, तो अधिकांश खाद्य पदार्थों में मिलावट देखने को मिल सकती है. कहीं बीपीएल कार्डधारकों को खराब-सड़ा गेहूं और चावल दिया जा रहा है, तो कहीं नौनिहालों को परोसे जाने वाले मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील) में मिलावट कर दी जाती है. यही है आज़ाद भारत की हक़ीक़त. नेता, अफसर, बिचौलिए, व्यापारी, खाकी वर्दी और काले कोट वाले सब आज़ाद हैं. गुलाम है तो सिर्फ़ इस देश का आम आदमी. आज़ादी के नाम पर आप दवा की जगह दारू बेच सकते हैं. खाद्य पदार्थों में मिलावट कर सकते हैं. नकली दवा, दूध, फल, मिठाई, तेल व घी बनाने की आपको पूरी छूट है. आपको दूध में शैंपू, डिटर्जेंट, यूरिया मिलाने की पूरी छूट है. सिर्फ़ नेताओं एवं अधिकारियों को अपनी कमाई का एक छोटा-सा हिस्सा देते रहिए और खुले बाज़ार में अपनी सहूलियत के हिसाब से बेरोक-टोक अपना धंधा करते रहिए. यही तो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का असल फ़साना.

सवाल यह उठता है कि हमारे प्रधानमंत्री किसके अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे और किसके अच्छे दिन आ गए. देश की जनता को खाद्य पदार्थों के बहाने ज़हर परोसा जा रहा है, ऐसे में उपभोक्ताओं के अच्छे दिन लाने की बात कहना बेमानी है. हां, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मोदी जी और उनकी पार्टी के अच्छे दिन आ गए, सत्ता मिल गई. अब जनता की किसे परवाह, खाना बेचो या ज़हर, कौन देखने वाला है! प्रधानमंत्री जी, हमारे देश में मिलावटखोरों का दुस्साहस इस हद तक बढ़ गया है कि उनका वश चले, तो आपकी थाली भी वे सुरक्षित न रहने दें. लेकिन, आप खुशनसीब हैं कि आपकी थाली एसपीजी की निगरानी में रहती है.एसपीजी प्रधानमंत्री के खाद्य-पेय पदार्थों की पहले ही प्रयोगशाला में जांच करा लेती है और देश की जनता को मिलावटखोरों के रहमो-करम पर छोड़ दिया जाता है. प्रधानमंत्री जी, आप आंखें खोलेंगे, तो पाएंगे कि देश के नौनिहालों को भी शुद्ध दूध या खाद्यान्न नसीब नहीं हो रहा है. सच मायने में देखा जाए, तो मिलावटी खाद्य पदार्थों से मां का दूध भी ज़हरीला हो चुका है.

आज दूध में पानी से लेकर जंतुनाशक, डीडीटी, सफेद रंग, हाइड्रोजन-पैराक्साइड आदि मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाया जाता है. देश में प्रतिदिन लगभग एक करोड़ लीटर से अधिक दूध की बिक्री होती है. जब दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में दूध के पंद्रह नमूने लिए गए और उन पर शोध किया गया, तो पता चला कि उसमें 0.22 से 0.166 माइक्रोग्राम जितना डीडीटी था. पंजाब में दूध में डीडीटी अन्य राज्यों की तुलना में चार से 12 गुना अधिक है. मिलावटखोरों की नज़र भारत में डेयरी प्रोजेक्ट के प्रति वर्ष 36,000 करोड़ रुपये के बाज़ार पर है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि देश में 68.4 फ़ीसद दूध मिलावटी बिकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह 31 फ़ीसद है. सरसों के तेल और दूसरे खाद्य तेलों में अर्जीमोन मेक्सिकाना का बीज मिलाया जाता है, जिससे लोग ड्रॉप्सी के शिकार हो जाते हैं. अर्जीमोन की मिलावट से सिर में दर्द, डायरिया, त्वचा पर धब्बे होने, बेहोशी, ग्लूकोमा और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत होती है. ड्रॉप्सी 1977 और 1999 में महामारी के रूप में सामने आई थी.

कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी ऑफ इंडिया ने एक बार कहा था कि मुंबई में बिक रहे खाद्य तेलों में 64 फ़ीसद मिलावट है. इसी तरह 2013 में बड़ौदा में 40 नमूनों का अध्ययन किया गया, जिनमें दाल, अनाज, सब्जी, कंद, जड़ों में आर्सेनिक की मात्रा मानकों से कहीं ज़्यादा थी. इसके अलावा अनाज, फल और दही में कैडमियम की मात्रा भी सामान्य स्तर से ज़्यादा थी. आर्सेनिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है. वहीं कैडमियम से दमा से लेकर कैंसर आदि होने का ख़तरा रहता है. 2013 में बरेली, देहरादून और इज्जत नगर में अंडों की जांच में पाया गया कि पांच फ़ीसद अंडों में शालमोनेला बैक्टीरिया है. इसी तरह 2011 में कोट्टयम में वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल होने वाली 1.33 फ़ीसद एवं दो फ़ीसद पालतू मुर्गियों और 51.33 फ़ीसद बत्तखों के अंडों में शालमोनेला बैक्टीरिया पाया गया. बत्तख के अंडे कोट्टयम में काफी लोकप्रिय हैं. सबसे अहम अध्ययन सामने आया कि 72,200 नमूनों में से 18 फ़ीसद यानी 13,571 मामले ही फूड सेफ्टी अथॉरिटी के मानकों पर खरे उतर सके, जिनका परीक्षण 2012-13 में किया गया था. वहीं मिलावट के 10,235 मामलों में से केवल 3,845 मामलों में ही दोषियों के ख़िलाफ़ आरोप तय हो सके.

दिसंबर, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध तैयार करने और उसे बेचने वालों को उम्रकैद की सजा देने की हिमायत करते हुए राज्य सरकारों से कहा था कि इस संबंध में क़ानून में उचित संशोधन किया जाए, लेकिन आज तक सरकारों के कानों पर जूं नहीं रेंगी. खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए एक क़ानून है और फूड एंड ड्रग कमीशन भी है. क़ानून शहरी एवं ग्रामीण, सभी क्षेत्रों में लागू है. शहरों में म्यूनिसिपल अधिकारी इसे लागू कराते हैं और ग्रामीण इलाकों में यह काम राज्य सरकार द्वारा नियुक्त फूड इंस्पेक्टर करते हैं. अभी मिलावट के मामलों में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत कार्रवाई होती है. इस क़ानून के तहत दोषी को अधिकतम छह माह की सजा हो सकती है. यह हास्यास्पद है, क्योंकि मिलावटखोरों को तो आजीवन कारावास या फांसी की सजा देनी चाहिए. अन्यथा वे मानवता से खिलवाड़ करते रहेंगे. समस्या की गंभीरता का पता इस बात से भी लगता है कि देश भर की उपभोक्ता अदालतों में मिलावट करने वालों के ख़िलाफ़ क़रीब चार लाख मामले लंबित हैं.

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान कहते हैं कि सरकार मिलावट के ख़िलाफ़ क़ानून और ज़्यादा अधिक सख्त बनाने का प्रयास करेगी. मगर ऐसा कब तक होगा और नया क़ानून सख्ती से लागू करने लायक कोई मशीनरी भी तैयार की जाएगी अथवा नहीं, यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होगा. चूंकि स्वास्थ्य एक राज्य सूची का विषय है, ऐसे में क़ानून लागू करने की ज़िम्मेदारी राज्य फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की है. कई मंत्रालयों को राज्य सरकारों से तालमेल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन चिंता की बात यह है कि फूड सेफ्टी को लेकर राज्यों में पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं हैं, जिसका असर भी रोकथाम पर पड़ता है. इसके लिए संबंधित महकमों में खाली पद शीघ्र भरने होंगे, उपभोक्ता अदालतों का विस्तार करना होगा, मिलावट के घिनौने खेल में लगे लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करना होगा. हम चीन से बराबरी के सपने देखते हैं. चीन में दूध में मिलावट पर हाल के वर्षों में मौत की सजा दी गई थी. चीन में मौत की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय ही अपने स्तर पर कर सकता है और हमारे यहां मिलावट की सज़ा सिर्फ़ छह महीने. क्या सिर्फ़ खिलौने बनाकर चीन की बराबरी संभव है?

फरवरी 2013 में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों पर ग्वालियर के तत्कालीन कलेक्टर श्री पी नरहरि ने राष्ट्रीय एवं राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. उत्तर प्रदेश में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के डिप्टी कमिश्नर विजय बहादुर ने आठ जनवरी, 2015 को मेरठ में 23,000 लीटर ग़ैर खाद्य तेल जब्त किया. वह कहते हैं कि व्यापारी मुनाफ़ा कमाने के लालच में न केवल ग़ैर-क़ानूनी काम कर रहे हैं, बल्कि निर्लज्जता की सारी हदें पार कर रहे हैं. बहादुर का कहना है कि मिलावट के काम में प्रतिष्ठित ब्रांड भी शामिल हैं. उनकी टीम ने प्रमुख मसाला ब्रांड महाराजा के प्रतिनिधि को मिलावट करते हुए पकड़ा था. दरअसल, व्यापारियों में क़ानून का डर नहीं है. उनका ज़ोर इस बात पर है कि कैसे वे क़ानून को दरकिनार करें और अथॉरिटी की आंखों में धूल झोंके. 1986 में केंद्र सरकार ने प्रीवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन क़ानून में संशोधन किया था, जिसके तहत सभी नागरिकों को यह अधिकार मिला कि वे खुद भी उत्पादों की जांच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जागरूकता की कमी के चलते संभव नहीं हो पाया. ऐसे में ग्राहक अभी भी फूड रेगुलेटर की दया पर ही निर्भर है.

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार, रोजाना इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों जैसे कि दूध से बने उत्पाद मावा, घी, मिठाई, अरहर की दाल, राजमा, सरसों व मूंगफली का तेल, पोल्ट्री-मांस, फल एवं सब्जियों में मिलावट का ज़्यादा ख़तरा रहता है. राष्ट्रीय ब्रांड जो पैकिंग में मिलते हैं, कहीं ज़्यादा सुरक्षित होते हैं. हमेशा पैक्ड और लेबल रहित उत्पाद खरीदने चाहिए. मानव शरीर पर मिलावट से होने वाले असर के प्रमुख लक्षण बुखार, उल्टी होना, डायरिया, पेट में दर्द, पक्षाघात, स्नायु में असहजता आदि हैं. लंबे समय से मिलावटी उत्पाद इस्तेमाल करने से कैंसर, हार्मोंस में असंतुलन, किडनी फेल होना, लीवर खराब होना या फिर विकास में रुकावट जैसे मामले भी हो सकते हैं. 2014 में रिसर्च पैसेफिक फॉर टेट्रापैक ने खाद्य सुरक्षा पर एक सर्वेक्षण देश के विभिन्न शहरों में किया, जिसमें यह पाया गया कि 70 फ़ीसद माताओं को गंभीर बीमारियां जैसे जॉन्डिस, कॉलरा एवं टायफायड होने के पीछे वजह यही है कि उन्हें उच्च मानक वाला भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता.■

पीएम की थाली में भी मिलावट!

वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पटना यात्रा पर थे. उन्हें परोसे जाने वाले खाद्य-पेय पदार्थों में से मिनरल वाटर नकली पाया गया था. 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को परोसी जाने वाली मूंग की दाल और खरबूजे के बीज अशुद्ध व मिलावटी पाए गए.

डॉक्टरों का कहना है...

डॉक्टर कहते हैं कि मैगी में पाए गए लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं. लेड की वजह से किडनी खराब हो सकती है और नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है. चिंता की बात यह है कि दिल्ली में मैगी के 13 में से 10 नमूनों की जांच में लेड ज़्यादा पाया गया और इसी वजह से सरकार ने मैगी की बिक्री पर रोक लगाई है. लेड टॉक्सिक सब्सटेंस है. दिल्ली में लेड की औसत मात्रा 3.5 पीपीएम तक पाई गई, जबकि तय मानक के अनुसार किसी फूड प्रॉडक्ट में लेड की मात्रा 0.01 पीपीएम से 2.5 पीपीएम के बीच होनी चाहिए. डॉक्टरों का कहना है कि लेड एक टॉक्सिक मेटल है और यह एमएसजी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है. शरीर में अधिक मात्रा में लेड ब्लड सप्लाई को प्रभावित करता है. मैगी मामले पर सुनीता नारायण की संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के फूड सेफ्टी एंड टॉक्सिन के हेड अमित खुराना से जब बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मैगी मसले में जो भी हुआ, उस पर सरकार गंभीर है, लेकिन फूड सेफ्टी के लिए लेबोरेट्री, मैन पावर बढ़ाने और रूटीन प्लान पर बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है, तभी हम फूड सेफ्टी को लेकर यूरोपीय यूनियन के देशों के समकक्ष खुद को पाएंगे.

बड़े ब्रैंड्स पर भी मिलावट का आरोप

- मशहूर कैडबरी कंपनी की डेयरी मिल्क चॉकलेट को लेकर 2003 में विवाद छिड़ा था, जब महाराष्ट्र में चॉकलेट में कीड़े पाए जाने का मामला सामने आया.
- मशहूर ब्रैंड मैकडोनल्ड्स के कोल्ड कॉफी में कनाडा में एक बार चूहा मिलने का मामला सामने आया था. इसके अलावा इंसान के दांत समेत कई चीजें बरामद की जा चुकी हैं. यही नहीं, चीन में मैकडोनल्ड्स की ओर से एक स्थानीय कंपनी के एक्सपायर मीट को दोबारा पैक कर बेचने का मामला सामने आया था. जापान में मीट में प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाने का मामला भी सामने आया था.
- दुनिया भर में अपने लजीज व्यंजनों के लिए मशहूर केएफसी की डिश पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की जांच में दिल्ली के कनॉट प्लेस के सिंधिया हाउस के एक आउटलेट से लिए गए चावल के नमूने में बनावटी रंग का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई थी. हालांकि कंपनी ने असली रंग के इस्तेमाल का ही दावा किया था.
- दुनिया भर में कोल्ड ड्रिंक्स के लिए मशहूर कोका कोला और पेप्सी भी विवादों में घिर चुके हैं. 2003 में पहली बार कोका कोला की ड्रिंक्स में कीटनाशक के इस्तेमाल का मामला सामने आया था. इसके बाद 2006 में एक एनजीओ ने पेप्सी और कोका कोला दोनों पर मिलावट का आरोप लगाया था. मध्य प्रदेश और गुजरात में दोनों के नमूनों की जांच में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक होने की बात सामने आई थी. यह तय सीमा से 24 गुना अधिक पाया गया था.
- 2011 में मुंबई की चर्चित कंपनी सबवे के चिकन टिक्का में कीड़े मिलने का मामला सामने आया था. ऐसा ही एक मामला हैदराबाद में सामने आया था, लेकिन कंपनी के मैनेजर ने यह कहते हुए मामले से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया था कि ऐसा सब्जी सप्लाई करने वाले की गलती की वजह से हुआ था. गौरतलब है कि सबवे सैंडविच के लिए ख़ासी मशहूर है।

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

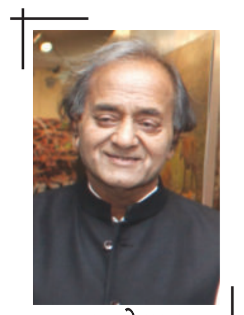

कमल मोरारका

समाजवादी एकता राजनीति के लिए बेहतर है

बिहार राजनीतिक रूप से देश के जागरूक राज्यों में से एक है. जयप्रकाश नारायण का आंदोलन यहीं पर हुआ था. बहुत सारे समाजवादी नेता इसी राज्य से संबंधित थे. यह भारतीय समाजवाद का गढ़ है. गया अधिवेशन में आचार्य नारायण देव ने पहली बार बोला कि लोगों की चिंता किए बिना कांग्रेस एक चुनाव जीतने वाली मशीन बनकर रह जाएगी. यह लगभग सच साबित हुआ. हालांकि, लोहिया जी फर्रुखाबाद से चुनाव लड़े थे, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार समाजवाद का वास्तविक गढ़ था. समाजवादी विचारधारा के भविष्य के लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है. हमारे कुछ मित्र इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे थे कि 2019 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे.

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री ने बहुत गर्व से कहा है कि भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा में कुछ किलोमीटर अंदर घुसकर एक अभियान को अंजाम दिया है. सेना ने जो भी किया, वह पहली बार नहीं हुआ है. कम से कम चार बार इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी अंजाम दी जा चुकी हैं. इसलिए इसमें सीना थपथपाने वाली कोई बात नहीं है. यह सेना का एक अभियान था. एक केंद्रीय मंत्री इन सब चीजों पर बढ़-चढ़कर बातें कर रहे थे. इससे किसी का भला नहीं होगा. न तो यह अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को सुधार सकता है और न सेना का मनोबल बढ़ा सकता है. हालांकि, ऐसा अक्सर अधिक वोट हासिल करने के लिए किया जाता है, लेकिन जनता बहुत ही तेज है और इस तरह के हथकंडों से दूर रहती है. इन चीजों को अपने विचार के तौर पर ही रखना चाहिए और इस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए. इसके पहले भी रक्षा मंत्री बहुत कुछ बोल चुके हैं, जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था. मैं नहीं जानता कि सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री को पीएमओ द्वारा इस बारे में बातें करने के लिए अधिकृत किया गया था या नहीं, लेकिन इन चीजों पर बोलने से बचा गया होता, तो वह ज़्यादा बेहतर होता.

इस सप्ताह की बड़ी ख़बर यह है कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर सभी लोग अंतत: राजी हो गए. यह अच्छी बात है. वह बिहार के एकमात्र चेहरे हैं, जिनकी साख है, जबकि भाजपा के पास इस तरह का कोई चेहरा नहीं है. भाजपा नेता सुशील मोदी, जो नीतीश सरकार में उप-मुख्यमंत्री थे, उनके पास न तो कोई जाति का समीकरण है (वह खुद बनिया जाति से हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है) और न उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि वह पूरे बिहार के नेता बन सकें. गिरिराज सिंह भूमिहार जाति के हैं और कुछ कर सकते हैं, लेकिन वह चरमपंथी विचारधारा के पोषक हैं और अल्पसंख्यकों एवं दूसरों के ख़िलाफ़ ग़लत भाषा का प्रयोग करते रहे हैं. यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन भाजपा को तो चुनाव लड़ना है.

यह अच्छी बात है, अगर धर्मनिरपेक्ष ताकतें एकजुट होकर लड़ें. चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन यह देश के राजनीतिक भविष्य और राजनीतिक आधार के लिए अच्छा होगा. इस देश में हर पांच साल पर चुनाव होता है और हमने 1977 के बाद हर तरह की सरकारों को देखा है. 1977 तक सिर्फ़ कांग्रेस ने देश पर शासन किया था, लेकिन 1977 के बाद विभिन्न तरह की सरकारें आईं. यह सिर्फ़ मेरी चिंता नहीं है. यह केवल राज्य का चुनाव है, लेकिन भाजपा एक साल पहले जिस तरह से व्यवहार कर रही थी कि वह अगले 10, 15 या 20 सालों तक इस देश पर राज करेगी, वह अरविंद केजरीवाल के दिल्ली विजय के बाद ध्वस्त हो चुका है. भाजपा के घमंडी स्वभाव को इस जीत ने नष्ट कर दिया है. एक बार फिर से बिहार में अमित शाह को भेजा गया है और एक बार फिर बर्मा सेना अभियान को इसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करके अपना सीना थपथपाया जा रहा है. इससे सफलता नहीं मिलेगी.

बिहार राजनीतिक रूप से देश के जागरूक राज्यों में से एक है. जयप्रकाश नारायण का आंदोलन यहीं पर हुआ था. बहुत सारे समाजवादी नेता इसी राज्य से संबंधित थे. यह भारतीय समाजवाद का गढ़ है. गया अधिवेशन में आचार्य नारायण देव ने पहली बार बोला कि लोगों की चिंता किए बिना कांग्रेस एक चुनाव जीतने वाली मशीन बनकर रह जाएगी. यह लगभग सच साबित हुआ. हालांकि, लोहिया जी फर्रुखाबाद से चुनाव लड़े थे, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार समाजवाद का वास्तविक गढ़ था. समाजवादी विचारधारा के भविष्य के लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है. हमारे कुछ मित्र इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे थे कि 2019 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. हमारे कुछ सहयोगियों के व्यवहार से इस विचार को धक्का लग सकता है, लेकिन हमें खुशी है कि आख़िरकार चीजों को सुलझा लिया गया. यहां तक कि लालू यादव भी आख़िरकार सहमत हो गए हैं. उनका बयान बहुत ही उत्साहजनक है. उन्होंने कहा, अगर मेरी वजह से यह टूट होती है और इसकी वजह से भाजपा को अगर फ़ायदा होता है, तो मैं कौन-सा मुंह लेकर लोगों के सामने जाऊंगा. यह अच्छी बात है कि उन्हें यह एहसास हुआ कि यह उद्देश्य व्यक्तिगत अहंकार से बड़ा है. अब तीन से चार महीनों तक सबकी निगाहें बिहार पर टिकी रहेंगी. पूरी कोशिश की जाएगी कि बिहार में एक अच्छी साख वाली सरकार आए, जो जनता के लिए काम करे और जनहितैषी कार्यक्रम चलाए. अगले पांच साल में बिहार अच्छा प्रदर्शन करेगा. पुरानी कहानी ख़त्म हो गई है. यहां की कृषि की स्थिति सुधर गई है. हालांकि, यह अभी भी मानसून पर निर्भर है. केंद्र ने राज्यों के फंड आवंटन की सीमा बढ़ा दी है. इसलिए किसी खास योजना का चुनाव करके राज्यों को खर्च करने की अधिक स्वतंत्रता है. आने वाले कुछ वर्षों के लिए यह अच्छा संदेश है. हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि सीटों का बंटवारा कोई समस्या नहीं बनेगा और वे जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देंगे.

मानसून की कमी एक चिंता का विषय है. दरअसल, हर साल इस तरह का पूर्वानुमान किया जाता है. कभी यह सही होता है और कभी ग़लत. देश की बेहतरी के लिए हम उम्मीद करते हैं कि मौसम का यह पूर्वानुमान ग़लत साबित हो जाए, लेकिन सरकार की तरफ़ से वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है. देश में खाद्यान्न का समुचित भंडार मौजूद है.

मानसून की कमी एक चिंता का विषय है. दरअसल, हर साल इस तरह का पूर्वानुमान किया जाता है. कभी यह सही होता है और कभी ग़लत. देश की बेहतरी के लिए हम उम्मीद करते हैं कि मौसम का यह पूर्वानुमान ग़लत साबित हो जाए, लेकिन सरकार की तरफ़ से वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है. देश में खाद्यान्न का समुचित भंडार मौजूद है. लेकिन यह खाद्यान्न के भंडार का सवाल नहीं है, क्योंकि जब बारिश कम होती है तो यह सच है कि इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं पड़ती, लेकिन सच्चाई यह भी है कि किसानों के बहुत सारे मवेशियों का नुक़सान होता है. जब बिहार, राजस्थान और दूसरे राज्यों में सूखा पड़ता है, तो वहां हालत दयनीय हो जाती है. सरकार को ऐसे हालात से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए. यह कैसे होगा? हमारे यहां राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण मौजूद है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि ऐसी आपदाओं से निपटना उसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं. लेकिन, उसे कम मानसून के कारण उत्पन्न होने वाले हालात से निपटने के लिए विशेष अधिकार देना चाहिए. बाढ़ एक दूसरी समस्या है. एलनीनो के प्रभाव के कारण कहा जाता है कि मानसून कम होता है या असमय और कम होता है. जलवायु परिवर्तन का भी अपना अलग प्रभाव है. इसलिए मैं यह समझता हूं कि सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि कृषि मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को इस बात की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए कि देश के अलग-अलग हिस्सों में अगर कुछ होता है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो सके.■

feedback@chauthiduniya.com

कुख्यात डाकू मुस्तकीम कैसे मारा गया-3

फर्जी मुठभेड़ की पुलिसिया कहानी

आसपास के गांवों से इकट्ठा हुए लोगों से मुस्तकीम ने पानी मांगा, लेकिन दारोगा ने उसे नहीं देने दिया. काफी हुज्जत के बाद उसे पानी दिया गया तथा बाद में एक लक्ष्मी नारायण ने उसे चाय भी पिलाई. इधर इमामुद्दीन लगातार रोए जा रहा था तथा कह रहा था कि हम ग़रीब घर के हैं, हमें छोड़ दीजिए. इसी बीच थाने से भेजे गए चार सिपाही वहां पहुंच गए. जब उन्हें भरोसा हो गया कि मुस्तकीम ही पकड़ा गया है, तो दो सिपाही फिर थाने गए. लेकिन जिस टैम्पो से वे आए थे, उसे छोड़ गए. उस टैम्पो में हाथ-पैर बंधे मुस्तकीम को दो सीटों के बीच में डाल दिया गया और उसके ऊपर इमामुद्दीन को लाद दिया गया. सिपाही उनके ऊपर पैर रखकर बैठ गए. जब टैम्पो दस्तमपुर से गलुआपुर पहुंचा, तो वहां एक चक्की पर उन्हें उतार दिया गया और वहीं मारने की योजना बनी, लेकिन गलुआपुर के लोगों ने भी नहीं मारने दिया. पुन: दोनों को टैम्पो में लादकर डेरापुर की ओर ले जाया गया. गलुआपुर से एक किलोमीटर दूर रतवाहा नाला पड़ता है. उससे पहले पड़ने वाली पुलिया पर टैम्पो रोककर हाथ-पैर पकड़ कर मुस्तकीम को उतारा गया तथा नीचे सूखे नाले में बाईं करवट लिटा दिया गया. तब तक थानाध्यक्ष भी वहां आ गए थे.

मुस्तकीम बोला, जल्दी गोली मारो, लेकिन वादा याद रखना, उस लड़के को मत मारना. थानाध्यक्ष से उसने कहा, आप मुझे मार रहे हैं, अब मेरे हाथ-पैर खोल दीजिए, पर उसकी बात सुनी नहीं गई. आसपास के काफी लोग आ गए थे, जिनमें गलुआपुर और दस्तमपुर के भी लोग थे. डेरापुर की तरफ़ से एक ट्रैक्टर भी आ गया था, जिसे दूर ही रुकवा दिया गया. इसके बाद पहले 12 बोर की बंदूक से गोली मारी गई, जो उसके पेट के दाहिने हिस्से में लगी. बाद में सिपाहियों और दारोगाओं ने राइफल से गोली मारी. मरते वक्त वह कुछ नहीं बोला. इसके पांच-सात मिनट बाद इमामुद्दीन को उतार कर गोली मार दी गई. दोनों लाशें चार घंटे तक वहीं पड़ी रहीं. गोली मारने के बाद अफसरों को सूचना दी गई, तो ग्रामीण क्षेत्र कानपुर के पुलिस अधीक्षक तथा बाद में दूसरे अधिकारी पहुंचे. अब मुठभेड़ की एक फर्जी कहानी गढ़ ली गई, लेकिन यह कहानी गढ़ते समय अधिकारी उन हज़ारों गांव वालों को भूल गए, जो इन घटनाओं को देख रहे थे. यह अजीब बात है कि मुस्तकीम की मौत का पांच ज़िलों के धनी वर्ग में खुशी के साथ स्वागत किया गया, पर ग़रीबों में कोई खुशी नहीं हुई. सबसे तकलीफदेह बात तो यह है कि पुलिस जान-बूझकर मुस्तकीम के साथी को कोई अज्ञात व्यक्ति बता रही है. उसका कारण यह है कि वह सचमुच निर्दोष था, उस पर कोई मुक़दमा नहीं था. यदि वह ज़िंदा रहता, तो उन अस्सी हज़ार रुपयों की बात अवश्य करता, जिन्हें मुस्तकीम के पास से बरामद किया गया था. पुलिस इतनी बड़ी रकम से इंकार करती है. वस्तुत: पुलिस रिकॉर्ड में शुरू में पांच सौ रुपया ही दिखाया गया, पर बाद में दो हज़ार और बढ़ा दिया गया. गांव वालों का कहना है कि यदि मुस्तकीम के पास पैसे नहीं होते, तो पुलिस उसे नहीं मारती या मारती भी, तो पहले वह अधिकारियों को ख़बर अवश्य दे देती.

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रकाशित विवरण के अनुसार: मुस्तकीम के गैंग में सक्रिय सदस्यों की संख्या 26 है. इस गैंग के पास देशी तमंचों और बंदूकों के अतिरिक्त एक स्टेनगन, 3 एसएलआर, 4 राइफलें, 12 एसबीबीएल गन होना बताया जाता है. गिरोह लीडर मुस्तकीम पर 10,000 रुपये नकद पुरस्कार घोषित था. डकैत विक्रम मल्लाह की रखैल विक्रम की मौत के बाद इसी गिरोह में शामिल हो गई. इस गैंग ने कानपुर, जालौन, हमीरपुर व झांसी जनपदों में 78 जघन्य अपराध किए हैं. ये अपराध डकैती, हत्या व अपहरण के हैं. इस गैंग के साथ वर्ष 1980 में जनपद जालौन पुलिस से 11 अवसरों पर, हमीरपुर पुलिस से 3 तथा झांसी एवं कानपुर पुलिस से एक-एक अवसर पर मुठभेड़ हुई. इस वर्ष अब तक इस गैंग से छह बार मुठभेड़ हुई. 24 फरवरी, 1981 को जालौन पुलिस से एक मुठभेड़ में इस गैंग के छह डकैत, जिनमें बलवान सिंह भी शामिल थे, मारे गए थे. उक्त मुठभेड़ में इंस्पेक्टर भोगनीपुर श्री मूलचंद्र की मृत्यु हुई थी. इससे पहले 25 जनवरी, 1981 की मुठभेड़ में, जो थाना चकर नगर, ज़िला इटावा में हुई थी, 11वीं वाहिनी पीएसी के कांस्टेबुल विष्णु की मृत्यु डकैतों के हाथों हुई थी. दो वर्ष पूर्व इसी गैंग के साथ कालपी में हुई एक मुठभेड़ में एसआई स्वामीदीन दिवंगत हुए थे. आज दिनांक 4 मार्च, 1981 की प्रात: जब यह गैंग कानपुर ज़िले के डेरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम दमतलपुर के निकट एक नाला पार कर रहा था, तब पुलिस ने इस गैंग को चैलेंज किया. इस पर दस्युओं ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गईं, जिसके फलस्वरूप इस गैंग का लीडर मुस्तकीम तथा उसका एक साथी मारा गया.

मुस्तकीम एक ग़रीब परिवार में पैदा हुआ था. उसके गांव मुलौली के पठान उसके परिवार से बेगार लेते थे. बचपन में वह भी काफी बेगार करता था तथा इस क्रम में भैसों को हांककर कई बार 60 किलोमीटर दूर कानपुर तक गया. बड़े होने पर उसने इसका विरोध किया, तो उसका घर उजाड़ दिया गया तथा उसके परिवार को भागकर चौरा तथा चांदापुर में शरण लेनी पड़ी. इसी बीच उसे जुए की लत लग गई और फिर धीरे-धीरे उसका संपर्क अपराधी तत्वों से होने लगा. अब वह पहलवानी भी करने लगा तथा अखाड़ों में कुश्ती लड़ने जाने लगा. मुस्तकीम के विरुद्ध सबसे पहला अपराध कानपुर की कर्नलगंज पुलिस ने अपराध संख्या 85, धारा 379 के अंतर्गत दर्ज किया तथा उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उस समय वह 17 वर्ष का था. जमानत पर छूटने पर जब मुस्तकीम को कोई काम नहीं मिला, तो वह छोटे-मोटे अपराध करने लगा. 1977 में औरय्या (इटावा) की पुलिस ने मुस्तकीम तथा उसके साथियों नसीम, फहीम तथा इब्राहिम को ट्रक लूटने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया. कहा तो यह जाता है कि पुलिस ने कुछ झूठी गवाहियां दिलवानी चाहीं, जो उसने नहीं दीं, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया. यहां से जमानत पर छूटने के बाद वह फरार हो गया और मरते दम तक फरार ही रहा. 9 जनवरी, 1979 को कालपी में उसने सब-इंस्पेक्टर स्वामीदीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि स्वामीदीन ने बलवान गड़रिया की बहन को उठाकर उससे बलात्कार किया था.■

क्रमश:

feedback@chauthiduniya.com

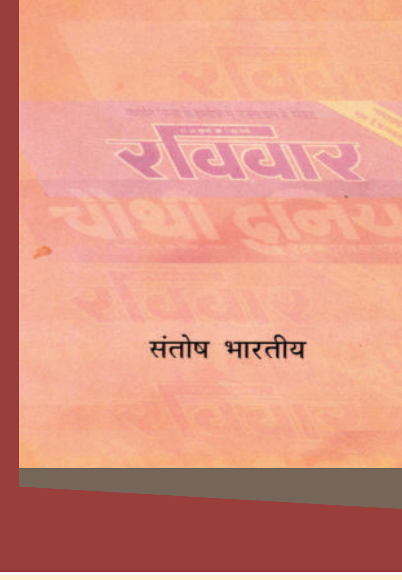

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

मुस्तकीम के विरुद्ध सबसे पहला अपराध कानपुर की कर्नलगंज पुलिस ने अपराध संख्या 85, धारा 379 के अंतर्गत दर्ज किया तथा उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उस समय वह 17 वर्ष का था. जमानत पर छूटने पर जब मुस्तकीम को कोई काम नहीं मिला, तो वह छोटे-मोटे अपराध करने लगा. 1977 में औरय्या (इटावा) की पुलिस ने मुस्तकीम तथा उसके साथियों नसीम, फहीम तथा इब्राहिम को ट्रक लूटने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया. कहा तो यह जाता है कि पुलिस ने कुछ झूठी गवाहियां दिलवानी चाहीं, जो उसने नहीं दीं, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

दिल्ली की लड़ाई देश हित में नहीं है

मेरा अपना यह मानना है कि नए सिरे से केंद्र सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री एवं उनके साथियों को किस तरीके से दिल्ली और केंद्र सरकार का रिश्ता व्यवहारिक रूप से न बिगड़े, इसके बारे में सोचना चाहिए. राजनीतिक तौर पर अक्सर अलग-अलग विचारधाराएं होती हैं, एक-दूसरे के ऊपर हमले भी होते हैं, लेकिन उसका असर सरकार चलाने की प्रक्रिया के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो उसका असर सीधा-सीधा जनता के ऊपर पड़ता है, जिसका कोई क़ुसूर नहीं होता. केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर कई सारे आयोगों ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी है. बहुत सारे सुझावों के ऊपर अमल भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे सुझावों के ऊपर अमल नहीं हुआ है.

दिल्ली राज्य और केंद्र सरकार का झगड़ा कुछ बुनियादी सवाल खड़े करता है. पहला सवाल यह कि राज्य और केंद्र का संबंध किस सीमा तक कड़वाहट से भरा हो सकता है और दूसरा यह कि क्या राजनीतिक मतभेद शासन चलाने की पद्धति को प्रभावित कर सकता है? दिल्ली सरकार के बारे में कहा जाता है कि यह पूर्ण सरकार नहीं है. यह बुनियादी तौर पर बड़े पैमाने पर किसी भी नगरपालिका का स्वरूप है. बुनियादी सुविधाओं का कैसे सुचारू रूप से संचालन हो सके, सिर्फ़ उतना ही इसका काम है. उसमें भी जब परेशानी आती है, तब जनता को दिक्कत होने लगती है.

इस समय दिल्ली गंदगी से परेशान है, क्योंकि जितने भी निगम हैं, जिनके ऊपर सफाई और पानी का ज़िम्मा है, उनके कर्मचारी नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है. यह वेतन केंद्र से दिल्ली सरकार को मिलता है, क्योंकि दिल्ली सरकार का बजट बुनियादी तौर केंद्र सरकार तय करती है. दिल्ली सरकार का कहना है कि उसके पास पैसा नहीं है. केंद्र सरकार कह रही है कि जितना बजट आवश्यक है, उसे वह दिल्ली सरकार को दे रही है, लेकिन पैसा कर्मचारियों के पास नहीं जा रहा है. उधर जनता, जो लोकतंत्र को पसंद करती है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की हो, चाहे कांग्रेस के पक्ष की हो या आम आदमी पार्टी के पक्ष की, यानी दिल्ली में रहने वाले हर आदमी को एक जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

मेरा अपना यह मानना है कि नए सिरे से केंद्र सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री एवं उनके साथियों को किस तरीके से दिल्ली और केंद्र सरकार का रिश्ता व्यवहारिक रूप से न बिगड़े, इसके बारे में सोचना चाहिए. राजनीतिक तौर पर अक्सर अलग-अलग विचारधाराएं होती हैं, एक-दूसरे के ऊपर हमले भी होते हैं, लेकिन उसका असर सरकार चलाने की प्रक्रिया के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो उसका असर सीधा-सीधा जनता के ऊपर पड़ता है, जिसका कोई कुसूर नहीं होता. केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर कई सारे आयोगों ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी है. बहुत सारे सुझावों के ऊपर अमल भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे सुझावों के ऊपर अमल नहीं हुआ है. मुझे लगता है कि एक बार सचमुच दिल्ली के मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद बातचीत करके कुछ सीमा रेखाएं तय करनी चाहिए. इसका सीधा मतलब है कि कुछ बिंदु तय करने चाहिए, जिनके ऊपर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को मदद करेगी. और, दिल्ली सरकार को भी यह तय करना चाहिए कि इन बिंदुओं पर वह केंद्र सरकार से नहीं लड़ेगी.

दिल्ली में राजनीतिक लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है. राजनीतिक मांग है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जब यह फ़ैसला हुआ था कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, तब उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण था कि दिल्ली में विदेशी दूतावास हैं, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में प्रधानमंत्री का घर है, राष्ट्रपति यहां रहते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल यहां पर है, बहुत सारे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संगठन यहां से काम करते हैं. अगर यहां कोई ऐसा नेतृत्व आ गया, दिल्ली सरकार ऐसे लोगों के पास चली गई, जो केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले इन सारे लोगों पर हमला कर दें और कहें कि प्रधानमंत्री बहुत बड़े घर में रहते हैं, यह घर उन्हें नहीं मिलना चाहिए या राष्ट्रपति का घर बहुत बड़ा है, यहां पर हमें बहुत बड़े दस-बीस विद्यालय खोल देने चाहिए. तो अगर इस तरीके का फ़ैसला पूर्ण राज्य की सरकार कर लेती है, तो यह देश के लिए ख़तरनाक बात साबित होगी.

शायद इसीलिए यह फ़ैसला लिया गया कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश रहे और दिल्ली में जो सरकार हो, उसके सीमित अधिकार हों. बहुत दिनों तक तो दिल्ली में सरकार थी ही नहीं, एक काउंसिल के ज़रिये यहां की शासन व्यवस्था चलती थी. पर जब सरकार हुई, तब भी यह तय किया गया कि उस सरकार की सीमित ज़िम्मेदारियां हों और वह केंद्र सरकार की निगरानी में चले. भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, तो वह पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करती थी. जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, तो उसने भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की, लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा किसी भी सरकार ने दिया नहीं. दरअसल, ये संसद का क़ानून है, जिसके तहत दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन है.

मैं ये सारी बातें इसलिए लिख रहा हूं, क्योंकि दिल्ली सारी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का चेहरा है. विदेशी जब यहां आते हैं, चाहे वे राष्ट्राध्यक्ष हों या सामान्य पर्यटक, उन्हें दिल्ली का चेहरा दिखाई देता है और बहुत सारे लोग दिल्ली से आगे कहीं जा नहीं पाते. वे दिल्ली ही आकर लौट जाते हैं. उनके सामने हिंदुस्तान का चेहरा दिल्ली है. इसलिए ज़रूरी ही नहीं, बहुत ज़रूरी है कि तत्काल दिल्ली की सरकार चलाने के तरीके के बारे में प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर कोई रास्ता निकालें और उन बुनियादी चीजों के ऊपर, जिनमें सफाई, पेयजल और बिजली प्रमुख हैं, बिना दलगत सीमा या विचारधारा लाए हुए दिल्ली को पूरी मदद करें, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है. वह आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा शासित राज्य नहीं है. वह केंद्र शासित राज्य है, जहां जनता बुनियादी चीजें ठीक करने के लिए किसी एक पार्टी की सरकार बना देती है. पहले उसने भाजपा की सरकार बनाई, फिर कांग्रेस की बनाई और अब आम आदमी पार्टी की बनाई. दिल्ली का इतना ही मतलब है.

अगर प्रधानमंत्री इस बारे में जल्दी कोई फ़ैसला नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि दिल्ली के लोगों में एक नई नफरत केंद्र सरकार के प्रति पैदा हो जाए. दिल्ली राज्य की सरकार चलाने वालों के प्रति गुस्सा आने से पांच साल के बाद दिल्ली की सरकार बदल जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार के प्रति अगर गुस्सा पैदा होता है, तो वह सिर्फ़ दिल्ली में सीमित नहीं रहता है, वह फिर पूरे देश में घूमता है. इसलिए मैं यह अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री तत्काल दिल्ली सरकार के साथ बैठकर सरकार चलाने के निम्नतम या न्यूनतम बिंदु तय करें और उनके ऊपर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को लगातार सहयोग करे. केंद्र-राज्य संबंधों को सुधारने के लिए सरकारिया आयोग की सिफारिशें लागू करना शायद एक शुरुआती बिंदु हो सकता है.■

विदेशी जब यहां आते हैं, चाहे वे राष्ट्राध्यक्ष हों या सामान्य पर्यटक, उन्हें दिल्ली का चेहरा दिखाई देता है और बहुत सारे लोग दिल्ली से आगे कहीं जा नहीं पाते. वे दिल्ली ही आकर लौट जाते हैं. उनके सामने हिंदुस्तान का चेहरा दिल्ली है. इसलिए ज़रूरी ही नहीं, बहुत ज़रूरी है कि तत्काल दिल्ली की सरकार चलाने के तरीके के बारे में प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर कोई रास्ता निकालें और उन बुनियादी चीजों के ऊपर, जिनमें सफाई, पेयजल और बिजली प्रमुख हैं, बिना दलगत सीमा या विचारधारा लाए हुए दिल्ली को पूरी मदद करें, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है. वह आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा शासित राज्य नहीं है.

editor@chauthiduniya.com

ग्लोबलाइजेशन ज़िंदाबाद!

एक-एक करके उनके सारे प्रतिद्वंद्वी मैदान छोड़ते गए. यहां तक कि उनके ख़िलाफ़ सिर्फ़ जॉर्डन के प्रिंस बाकी बचे थे. उसके बाद चमत्कारिक तौर पर स्विट्ज़रलैंड, जहां फीफा का दफ्तर है, के अधिकारियों ने एफबीआई के आगाह करने पर फीफा के 10 अधिकारियों को हिरासत में ले लिया. इसके बावजूद ब्लैटर खुद को निर्दोष बताते रहे. उनकी मदद के लिए उनके मित्र सामने आए. यूरोपीय लोग भ्रष्टाचार को नापसंद करते हैं.

मेघनाद देसाई

ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर खेलों की व्यवस्था इतनी ख़राब है? भारत में खेल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के अनुचित एवं ग़ैर-क़ानूनी व्यवहार के प्रति खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की शिकायतों की कोई सीमा नहीं होती. उक्त अधिकारी एक विशिष्ट मंडली द्वारा चुने जाते हैं, उनके चुनाव में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता. उक्त अधिकारी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते. अगर आईपीएल के मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है. खेल से संबंधित ताज़ा घपला सेप ब्लैटर का चौथी बार फीफा का अध्यक्ष चुना जाना और उसके बाद अचानक उनके त्याग-पत्र से जुड़ा हुआ है. जिस तरह से फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए रूस (2018) और क़तर (2022) को चुना गया था, उसे लेकर बहुत सारी शिकायतें थीं. ब्रिटेन के कुछ अख़बारों की खोजी पत्रकारिता ने इस सिलसिले में उल्लेखनीय काम किया है. चूंकि इंग्लैंड भी मेजबानी की दौड़ में शामिल था, इसलिए इसे लोग अंगूर खट्टे हैं की संज्ञा दे रहे हैं. वे यह भी कह रहे हैं कि घपले की ये बातें इसलिए हो रही हैं, क्योंकि फुटबॉल पर अब यूरोप का एकाधिकार ख़त्म हो गया है. अब एशियाई एवं अफ्रीकी देश बहुमत में हैं और वे सेप ब्लैटर को पसंद करते हैं. यूरोपीय देश अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता दिखा रहे हैं. वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि एशिया और अफ्रीका में उनका व्यापार बढ़ा है. वे इन देशों पर अपना यूरोपीय मानक लागू कर रहे हैं.

फीफा ने एक घोटाला उजागर करने के लिए एक रिपोर्ट असाइन की थी, लेकिन वह रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई, जिसे लेकर यह अफ़वाह उड़ रही थी कि क़तर और रूस की तरफ़ से वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए फीफा के सदस्यों को रिश्वत दी गई थी. लेकिन, इससे ब्लैटर ज़रा भी विचलित नहीं हुए. वह फीफा के अध्यक्ष पद के लिए पांचवीं बार खड़े हुए. एक-एक करके उनके सारे प्रतिद्वंद्वी मैदान छोड़ते गए. यहां तक कि उनके ख़िलाफ़ सिर्फ़ जॉर्डन के प्रिंस बाकी बचे थे. उसके बाद चमत्कारिक तौर पर स्विट्ज़रलैंड, जहां फीफा का दफ्तर है, के अधिकारियों ने एफबीआई के आगाह करने पर फीफा के 10 अधिकारियों को हिरासत में ले लिया. इसके बावजूद ब्लैटर खुद को निर्दोष बताते रहे. उनकी मदद के लिए उनके मित्र सामने आए. यूरोपीय लोग भ्रष्टाचार को नापसंद करते हैं. ब्लैटर चुन लिए गए. यूरोप हार गया. उसे मालूम नहीं था कि आगे क्या करना चाहिए. उसके बाद घपलों की जांच कर रही एफबीआई ब्लैटर के और क़रीब पहुंच गई. इस बात के संकेत आ रहे थे कि ब्लैटर का खेल अब ख़त्म हो गया. उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया. अब नया चुनाव होगा और 2018 और 2022 के विश्व कप की मेजबानी पर भी पुनर्विचार हो सकता है. फीफा के अंदर चल रही सफाई का असर अब नज़र आने लगा है. इस घटनाक्रम की सबसे उल्लेखनीय बात है कि यह ग्लोबलाइजेशन के अंतर्विरोधों को सुंदरता से रेखांकित करता है. जब इंग्लैंड ने 1966 में विश्वकप जीता था, तो उस समय तक फुटबॉल बहुत हद तक यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी खेल था. फुटबॉल क्लब में खेलने वाले अधिकतर खिलाड़ी और ठंडे व आरामदायक स्टेडियम में खेल का लुत्फ़ उठाने वाले दर्शक स्थानीय होते थे. 2014 तक, जब वर्ल्ड कप ब्राज़ील में आयोजित हुआ, सब कुछ बदल चुका था. यूरोप की फुटबॉल टीमें बहुजातीय और बहुराष्ट्रीय टीमें बन गई थीं. टेलीविज़न ने दर्शकों की संख्या कई गुना कर दी थी, जिसके कारण इस खेल में बहुत सारा पैसा भी आया था. खिलाड़ियों की कमाई में बेतहाशा इजाफा हुआ था, उनकी ट्रांसफर फीस भी शानदार हो गई थी. अब न तो राष्ट्रीयता का कोई मतलब है और न ही नस्ल का कोई असर. अगर आप उच्च स्तर पर खेलने के काबिल हैं, तो दुनिया आपके क़दमों के नीचे है.

लिहाज़ा जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो उसका इलाज भी ग्लोबल स्तर पर होगा. यूरोप को यह शिकायत है कि उनका खूबसूरत खेल फीफा में नवागंतुकों की वजह से बर्बाद हो रहा है, लेकिन हकीक़त यह है कि एक नवागंतुक अमेरिका ने भ्रष्टाचार के दोषियों तक पहुंचने की पहल की है. इसका कारण यह भी हो सकता है कि डॉलर लेन-देन की अंतराष्ट्रीय मुद्रा है. रिश्वत के बड़े-बड़े लेन-देन चेक के ज़रिये हो रहे थे (भारत में इस काम में लोग माहिर हैं, इसलिए गांधी नोट इस्तेमाल करते हैं). ये चेक एक बैंक से दूसरे बैंक में जाते हैं और ये बैंक अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में व्यापार करते हैं. फुटबॉल का ग्लोबलाइजेशन और वित्त का ग्लोबलाइजेशन इसके लिए एक फंदा साबित हुआ. अमेरिका एक ऐसा देश था, जो मजबूती के साथ इस धोखाधड़ी से निपटता रहा. अमेरिका ने स्विट्ज़रलैंड को आगाह किया कि फीफा की बैठक के दौरान दोषियों को धर दबोचने का सही समय है.

यहां अहम यह है कि विकसित देशों और बाकी दुनिया के लिए अलग मापदंड नहीं होना चाहिए. जो लोग भ्रष्टाचार को यूरोपीय साम्राज्यवाद पर हमला करके छिपाना चाहते हैं, वे दरअसल बिना निवेश के धन जमा करने की इच्छा की पैरवी करते हैं. इससे न तो नागरिकों का भला होगा और न दर्शकों का. दुनिया का कोई भी देश भ्रष्टाचार को वैधानिक करार नहीं देता. जिस देश में प्रेस और सिविल सोसायटी का लोकतांत्रिक दबाव कम होता है, वहां के संभ्रांत वर्ग के लोग भ्रष्टाचार करके बच निकलते हैं, लेकिन ग्लोबल पुलिसिंग ताक़तवर स्थानीय लोगों के ख़िलाफ़ कमज़ोर लोगों के अधिकारों की हिफाज़त करती है. ग्लोबलाइजेशन ज़िंदाबाद!■

feedback@chauthiduniya.com

टैटू बनाने में इस्तेमाल हुई इंक से भी त्वचा में एलर्जी हो जाये. अगर त्वचा बहुत सेंसिटिव है तो टैटू पार्लर जाने से पहले किसी स्किन के डॉक्टर को दिखा लें. स्किन पर किसी अगर किसी तरह की चोट या खरोंच आयी है तो बेहतर यही है कि थोड़ा इंतज़ार करें. साथ ही टैटू बनवाने से पहले बहुत ज़्यादा धूप में नहीं घूमना चाहिए और किसी तरह की एलर्जी होने पर उसका पूरी तरह से ठीक होने का इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि त्वचा को भी टैटू के लिए तैयार होने के लिए समय चाहिए होता है. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शरीर के कुछ हिस्से टैटू बनवाने के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं.

सावधानी से बनवाएं टैटू

कई चिकित्सकों का कहना है कि टैटू बनवाने से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. उनके अनुसार टैटू बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली स्याही में आर्सेनिक जैसे विषैले तत्व होते हैं जिसकी वजह से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.

मोनिशा भटनागर

टैटू कहें बॉडी इंक या पुराने ज़माने में बोला जाने वाला नाम गुदना, आजकल ये एक फैशन ट्रेंड बन गया है. टैटू आजकल के युवाओं का एक तरह से स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है. शरीर पर तरह-तरह के टैटू बनवाने का चलन युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है.

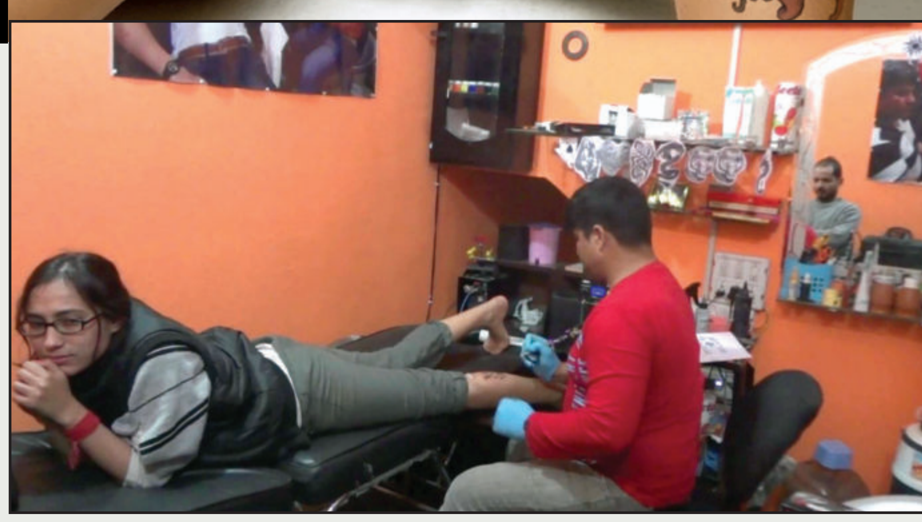

टैटू बनवाने से पहले बरतें यह सावधानियां

अगर आपकी त्वचा कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स से एलर्जिक है तो संभव है कि टैटू बनाने में इस्तेमाल हुई इंक से भी त्वचा में एलर्जी हो जाये. अगर त्वचा बहुत सेंसिटिव है तो टैटू पार्लर जाने से पहले किसी स्किन के डॉक्टर को दिखा लें. स्किन पर किसी अगर किसी तरह की चोट या खरोंच आयी है तो बेहतर यही है कि थोड़ा इंतज़ार करें. साथ ही टैटू बनवाने से पहले बहुत ज़्यादा धूप में नहीं घूमना चाहिए और किसी तरह की एलर्जी होने पर उसका पूरी तरह से ठीक होने का इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि त्वचा को भी टैटू के लिए तैयार होने के लिए समय चाहिए होता है. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शरीर के कुछ हिस्से टैटू बनवाने के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं. टैटू बनवाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां अनुभवी और प्रशिक्षित स्टाफ हो. टैटू बनवाने से पहले हाइजीन और साफ-सफाई की जांच करें. जांच लें कि टूल्स या इक्विपमेंट स्टेरिलाईज किये गये हैं. अच्छे और साफ-सुथरी जगह से ही टैटू बनवाएं और देख लें कि सुई डिस्पोजेबल है या नहीं. न सिर्फ सुई बल्कि इंक भी डिस्पोजेबल हो, यह पुख्ता कर लें. टैटू बनवाने के पहले उसकी पूरी प्रक्रिया का पता करें और एक्सपर्ट को कहें कि वह दस्ताने पहनकर ही टैटू बनाए. हमेशा टैटू वाले हिस्से को साफ करके रखें जिससे वहां किसी भी प्रकार का संक्रमण न हो सके. टैटू बनवाने से पहले यह ज़रूर याद रखें कि परमानेंट टैटू को हटाना कठिन होता है और इसे मिटाने वाली कोई भी प्रक्रिया पूरी तरह कामयाब नहीं होती और इसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं.

टैटू बनवाने के बाद इन बातों का ध्यान रखें

टैटू पर दो हफ्तों तक पानी नहीं लगना चाहिए और टैटू को धूप भी नहीं लगनी चाहिए. सूरज की यूवी किरणें त्वचा को जला देती हैं जो इसे बहुत नुकसान पहुंचाती हैं. टैटू वाली जगह को कम से कम दो हफ्तों तक के लिए ढक कर रखें. टैटू से एक परत जैसी निकलेगी और इसमें हल्की खुजली भी होगी लेकिन इसे खुजलाने से बचें. हर रोज़ इस पर थोड़ा-थोड़ा मॉश्चराइज़र या फिर ओलिव ऑयल लगाएं. टैटू बनवाने के बाद किसी भी प्रकार का संक्रमण या परेशानी लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं क्योंकि इसकी अनदेखी महंगी पड़ सकती है. इसके अलावा यह भी जान लें कि स्थायी टैटू के बाद करीब एक साल तक आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं.

टैटू बनवाने के खतरे

कई चिकित्सकों का कहना है कि टैटू बनवाने से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. उनके अनुसार टैटू बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली स्याही में आर्सेनिक जैसे विषैले तत्व होते हैं जिसकी वजह से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. खासतौर से टैटू बनाने वालों द्वारा प्रयोग की जाने वाली नीले रंग की स्याही में कोबाल्ट और एल्युमिनियम होता है. जबकि लाल रंग की स्याही में मरक्युरियल सल्फाइड और दूसरे रंगों की स्याहियों में शीशा, कैडियम, क्रोमियम, निकिल, टाइटेनियम और कई तरह की दूसरी धातुएं मिली होती हैं. टैटू की जहरीली स्याही लोगों के शरीर में पहुंचकर कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती है. ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने खोज में पाया कि स्याही के छोटे-छोटे जहरीले कण शरीर के बड़े अंगों में प्रवेश कर सकते हैं.जानकार मानते है कि शरीर पर तिल वाले स्थान पर टैटू नहीं बनवाना चाहिए. तिल के आस-पास या तिल पर टैटू बनवाने से तिल में आ रहे बदलावों पर ध्यान नहीं जा पाता जो बाद में त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है.

इसके अलावा टैटू बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार में यदि संक्रमित खून लगा हो तो इससे खून के द्वारा संक्रमित होने वाली बीमारियां जैसे एचआईवी और हेपेटाइटिस बी एवं सी के विषाणु भी एक से दूसरे शरीर में फैल सकते हैं. मेडिकल जर्नल हैपेटोलाजी में छपे एक शोध के अनुसार हैपेटाइटिस का विषाणु खून के जरिए अधिक फैलता है और टैटू गुदवाने से यह खतरा काफी बढ़ जाता है. बहुत से युवा त्वचा को टैटू से होने वाले नुकसान को नज़रंदाज़ कर देतें हैं. गंभीर बिमारियों की आशंका के अलावा त्वचा पर लालिमा, सूजन, मवाद आने के साथ दर्द होना आदि लक्षणों वाले त्वचा इंफेक्शन जैसे बैक्टीरिया स्टाफ या स्ट्रेप के कारण बैक्टीरियल इंफेक्शन होने का भी डर होता है. पर्मानेंट टैटू बनवाने में होने वाले दर्द से बचने के लिए अगर कोई नकली टैटू बनवाने की सोच रहा है तो भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इससे भी त्वचा पर एजर्लिक हो सकती है. अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) की एक रिपोर्ट में नकली टैटू को लेकर सचेत किया गया है. इसमें कहा गया कि अस्थाई टैटू से त्वचा पर फफोले और चकत्ते पड़ सकते हैं इसके साथ ही त्वचा में बदलाव, धूप में संवेदनशीलता बढ़ने जैसे दीर्घकालिक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं. रिपोर्ट में पर्मानेंट टैटू में भी दूषित स्याही के प्रयोग के खतरा के बारे में कहा गया है, जिससे संक्रमण हो सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

पूर्व की माता हारी थीं योशिको

अरुण तिवारी

योशिको कावाशिमा चीन के एक राजघराने की राजकुमारी थीं. उनका जन्म 24 मई 1907 को बीजिंग में हुआ था लेकिन वे पली-बढ़ी जापान में थीं. उन्हें पूर्व की माता हारी के नाम से भी जाना जाता है. दूसरे चीन-जापान युद्ध के बाद उन्हें मौत की सजा दे दी गई थी.

वे अपने पिता की दसवीं औलाद थीं. जन्म के कुछ ही दिनों बाद योशिको को उनके पिता ने अपने जापानी मित्र नानिवा कावाशिमा को सौंप दिया था. नानिवा के परिवार में योशिको का बचपन बहुत ही बुरा बीता. उन्हें वह प्रेम नहीं मिल सका जिसका कोई भी एक आम बच्चा हकदार होता है. जब वे किशोर थीं तभी नानिवा के पिता ने योशिको के साथ दुष्कर्म किया था. इस दौरान योशिको के पिता की चीन में मौत हो गई थी.

योशिको को अपनी किशोरावस्था में कुछ दिनों तक टोक्यो में रहने का अवसर मिला. यहां उन्होंने जूडो की ट्रेनिंग ली. इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र जिंदगी जिया. इस दौरान उनके अमीर लोगों के साथ कई अफेयर हुए, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल थे.

1927 में योशिको ने मंगोलियाई आर्मी जनरल के पुत्र जेंगजुराब से विवाह कर लिया. लेकिन विवाह के दो साल के भीतर ही दोनों में तलाक हो गया. इसके बाद वह शंघाई चली गईं जहां उनकी मुलाकात जापानी जासूस और मिलिट्री अधिकारी यूकिची तनाका से हुई. तनाका ने योशिको के अमीर और रसूखदार लोगों से संबंध को भुनाने की सोची. तनाका ये बात जानता था कि एक खूबसूरत महिला के जरिये रसूखदार लोगों से गोपनीय सूचनाएं निकलवाई जा सकती हैं. जब 1932 में चीन और जापान की सेनाएं शंघाई में आपस में लड़ रही थीं तो योशिको वहीं मौजूद थीं. तनाका और योशिको ने साथ रहना शुरू कर दिया था.

तनाका को जापान बुला लिया गया लेकिन इसके बाद भी योशिको चीन में जासूसी का काम करती रहीं. वह रूप बदलने में माहिर थीं. चीन में विरोधी गुट में आसानी के साथ वे शामिल हो जाया करती थीं. वे कभी टॉम बॉय का रूप लिया करती थीं तो कभी हिरोइन का.

वे चीन के क्विंग राजवंश का हिस्सा हुआ करती थीं. इस वजह से इस राजवंश के आखिरी राजा पू यी के पास वे मिलने पहुंची. राजा ने उन्हें परिवार का सदस्य होने के कारण काफी सम्मान दिया. अपने संबंधों को भुनाने का काम योशिको ने शुरू कर दिया था. अपने इन्हीं संबंधों के कारण उस राजा को योशिको ने हाल ही में जापान द्वारा बनाए गए मंचूको राज्य का प्रमुख बनवा दि या.

जब मंचूको राज्य पर पू यी काबिज हो गए तो उस इलाके में योशिको का रहना आसान हो गया. यहां पर रहते हुए वे आसानी से जापान को चीन की गोपनीय सूचनाएं पहुंचा दिया करती थीं. मंचूको राज्य में रहने वाले लोगों के बीच भी योशिको का बहुत सम्मान था. उन्होंने में राज्य में महिलाओं की ही एक गुरिल्ला सेना भी तैयार की थी जिसकी वह हेड थीं. यह सेना चीनी सेना को जापानी सेना पर आक्रमण करने से रोकने के लिए बनाई गई थी. इसके लिए योशिको को जापानी अखबारों में जॉन ऑफ आर्क की उपाधि से भी नवाजा गया था. इन सारी चीजों के बीच जो एक बात योशिको के विरोध में जा रही थी वह थी कि वह लगातार चीन की निगाहों में बनी हुई थीं. हालांकि योशिको चीन में पैदा हुई थीं लेकिन बचपन से ही जापान में रहने के कारण उनकी पूरी वफादारी जापानी सेना की तरफ थी और वह अपनी पूरी क्षमता के साथ उसका साथ भी निभा रही थीं. इस बीच जापानी सेना ने मंचूको के लोगों को भी परेशान करना शुरू कर दिया था. मंचूको जापान के लिए एक महत्वपूर्ण बेस था जिसके जरिये वे आसानी के साथ चीन के साथ लड़ाई लड़ रहा था. लेकिन अगर किसी भी आदमी पर शक होता तो जापानी सैनिक उसे मौत के घाट उतारने में जरा भी समय नहीं लगाते थे. योशिको ने इसकी शिकायत बड़े जापानी अधिकारियों से ही नहीं बल्कि जापानी राजवंश तक भी इस बात को पहुंचाया. योशिको की इस शिकायत को जापान की तरफ से ठीक तरीके से नहीं लिया गया. जापान को यह लगने लगा कि योशिको पूरी तरीके से जापान का साथ नहीं दे रही हैं. धीरे-धीरे योशिको लाइम लाइट से बाहर होने लगीं. जापानी अखबारों में उनके बारे में खबरें प्रकाशित होना बंद हो गईं.

11 नवंबर 1945 को जब युद्ध समाप्त हुआ तो जापानी रेडियो पर एक खबर प्रसारित की गई कि पुरुषों के वेश में एक स्त्री को पेकिंग में गिरफ्तार किया गया है. योशिको को चीन की नेशनलिस्ट पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया था. उन पर षड्यंत्र रचने का केस चलाया गया. 1948 में उनकी सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई.

1932 के बाद योशिको के किरदार को लेकर कई फिल्में बनाई गईं जिनमें उनकी जांबाजी के किस्से दिखाए गए. ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म द लास्ट इंपरर में उनका किरदार ईस्टर्न जेवेल के नाम से दिखाया गया है. इसके अलावा उन पर कई किताबें भी लिखी गई हैं. हालांकि इस सब के बीच योशिको अंत दुखद हुआ. वे पूरे जीवन जापान की सेवा करती रहीं लेकिन सही बात के लिए आवाज उठाने के कारण भी उनके साथ गलत बर्ताव किया गया.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

मोदी का बांग्लादेश दौरा

रिश्तों का नया अध्याय

नवीन चौहान

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय बांग्लादेश यात्रा ने दोनों देशों के बीच परस्पर संबंधों में एक नया अध्याय शुरू किया है. सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने ही पिछले साल अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों को आमंत्रित कर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की थी. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक भूमि समझौता किया गया. मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना का व्यवहार करने की एक बार फिर पुष्टि की है. नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 22 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग, मानव तस्करी और जाली भारतीय करेंसी के प्रसार को रोकने जैसे कई मसलों पर सहमति हुई, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह हुई कि 41 साल से चल रहे सीमा विवाद का आखिरकार अंत हो गया. यह दोनों देशों के बीच रिश्तों में प्रगाढ़ता का एक ऐतिहासिक पल था. इस भूमि समझौते को भारतीय संसद में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. इस विवाद का खत्म होना इस बात का साफ संकेत है कि दोनों देश भाईचारे और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं. भारतीय मालवाहक जहाजों के लिए चीन द्वारा निर्मित चिटगांव और मोंगला बंदरगाहों को खोलने का निर्णय भी सहयोग की इसी दिशा की ओर इशारा करता है. अब तक भारतीय जहाजों को अपना माल सिंगापुर के बंदरगाहों में उतारना पड़ता था. इस प्रकार माल को बांग्लादेश पहुंचाने में 42 दिन लग जाते थे, लेकिन इस समझौते के बाद केवल एक सप्ताह लगेगा.

1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 16 मई, 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्ररहमान कि अगुवाई में भूमि–सीमा समझौता हुआ था. 41 साल पहले शुरू हुए इस समझौते को अंतिम वैधानिक रूप देना न सिर्फ दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक जगत की एक अहम घटना के तौर पर देखा जा रहा है. दोनों देश अब चाहते हैं कि विवादों को दूर रखकर एक दूसरे के विकास में सहयोग किया जाये. दोनों देशों के बीच हुए इस भू–समझौते में 1947 में देश के विभाजन के बाद उपजी इस दु:खती रग का न सिर्फ इलाज किया गया है, बल्कि एक बड़ी मानवीय समस्या का भी निवारण किया गया है. भू–सीमा समझौते के तहत अब भारत बांग्लादेश को 111 बस्तियों सौंपेगा. गौरतलब है कि बांग्लादेश में 111 भारतीय बस्तियों में कुरीग्राम जिले में 12, नीलफामरी में 59 और पन्हागर में 36 शामिल हैं. इन कॉलोनियों की कुल जमीन 17,160 एकड़ के करीब है. वहीं बांग्लादेश भी 51 कॉलोनियां इस समझौते के तहत भारत को सौंपेगा. इन कॉलोनियों की कुल जमीन 7,110 एकड़ के करीब है. गौरतलब है कि बांग्लादेश की कॉलोनियों में अभी 14 हज़ार लोग रहते है, वहीं भारत की कॉलोनियों में भी अभी 37 हज़ार लोग गुज़र–बसर कर रहे हैं. समझौते के मुताबिक अब इन कॉलोनियों के लोगों को नागरिकता चुनने का विकल्प होगा. वे चाहें तो दोनों में से किसी एक देश की नागरिकता ले सकते हैं. इसके अलावा भी 6.1 किलोमीटर अनिश्चित सीमा का सीमांकन इस समझौते के बाद अब पूर्ण हो जाएगा. इससे पूर्व इस जमीन पर किसी तरह की सीमा निर्धारित नहीं थी. दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा का निपटारा इस समझौते से पहले हो चुका है. हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने सात जुलाई, 2014 को दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा की रूपरेखा पेश कर दी थी. इस समझौते के तहत भारत को जो 51 बस्तियां मिलने वाली हैं, उनमें 4 जलाईपाईगुड़ी और 47 कूच बिहार में हैं. वहीं, भारत की जो 111 बस्तियां बांग्लादेश को मिलेंगी, उनमें 36 पंचागढ़, चार निलफमडी, 59 लालमोनिरहट और 12 कुरीग्राम में हैं. हाल में की गई जनगणना में पता चला कि इन 162 बस्तियों में कुल 51,549 लोग रहते हैं. भारत में मौजूद 111 बस्तियों में करीब 37,334 लोग रहते हैं, जबकि 51 बांग्लादेशी बस्तियों में 14,215 लोग रहते हैं. इस समझौते के बाद दो देशों की राजनीति के बीच पिस रहे लोगों को राहत मिली है.

इन बस्तियों में रह रहे लोगों को अबतक मूलभूत सुविधायें भी नहीं मिल पा रही थीं. उनकी नागरिकता के बारे में हर कदम पर विवाद रहा है, लेकिन इस समझौते के बाद यहां रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है. जब 1971 में पाकिस्तान से जंग के बाद बांग्लादेश आजाद हुआ तो दोनों देशों के बीच सीमाएं साफ तौर पर तय नहीं हो सकी थीं. तीन साल बाद यानी 1974 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर्रहमान के बीच सीमा समझौता हुआ था. इसके तहत भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश को सौंपा जाना है. बदले में बांग्लादेश से कुछ हिस्से भारत में शामिल होने वाले हैं. हाल ही में संसद के दोनों सदनों में यह 100वां संविधान संशोधन बिल पास किया गया. चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को मंजूरी की जरूरत होगी. चूंकि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को इस पर आपत्ति नहीं है, इसलिए बिल को अमल में लाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. भारत ने बांग्लादेश को दो अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने का भी ऐलान किया. साथ ही दोनों देश के बीच व्यापार घाटे को कम करने के लिए दो विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) बनाने पर भी बातें हुईं. यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, सुरक्षा, विज्ञान एवं तकनीक, शांतिपूर्ण संबंध जैसे विषयों पर भी समझौते हुए हैं. दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने का वादा किया है.

इस यात्रा के दौरान भारत को चीन द्वारा निर्मित चिटगांव और मोंगला बंदरगाहों को भारत के लिए खोलने के लिए समझौता हो गया है. रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश की भूमि का इस्तेमाल कर भारत अपने उत्तर पूर्व के इलाके में विकास का काम तेजी से कर सकता है. बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट के जरिए उत्तर पूर्व के राज्यों को मदद मिल सकती है और इन इलाकों में सामान आसानी से भेजे जा सकते हैं. इस क्षेत्र के विकास से इम्फाल–तामू–यंगुन–सिंगापुर पैसेज का तेजी से विकास हो सकता है.

मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच बस सर्विस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह बस सर्विस कोलकाता–ढाका–अगरतला, ढाका–शिलांग–गुवाहाटी के बीच होगी. अगर किसी को कोलकाता से सीधे अगरतला जाना हो तो फिलहाल यह दूरी 1650 किलोमीटर की होती है, जो समझौते के बाद घटकर 500 किलोमीटर रह जाएगी. लिहाजा, नई बस लिंक के चलते ज्यादा फायदा भारतीयों को है. वहीं, ढाका–शिलॉन्ग–गुवाहाटी के बीच बस सेवा शुरू होने से दोनों देशों के लोगों को फायदा मिलेगा.

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने कॉर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान को लागू करने पर जोर दिया, जिससे की दोनों देशों के बॉर्डर पर होने वाली आपराधिक और गैर–कानूनी गतिविधियों, हिसांत्मक गतिविधियों और जानमाल की हानि पर रोक लगाई जा सके. दोनों देशों की अक्षय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की. दोनों प्रधानमंत्रियों ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में खासकर तकनीकी प्रशिक्षण की दिशा काम करने पर सहमति जताई है.

क्या है तीस्ता विवाद

दोनों देशों के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का मुद्दा अहम है. इस मुद्दे पर 18 साल से बातचीत जारी है. दिसंबर से मार्च के बीच इस नदी में पानी का बहाव कम हो जाता है. इस वजह से बांग्लादेश में मछुआरों और किसानों को कुछ महीनों तक रोजगार के दूसरे विकल्प तलाशने पड़ते हैं. बांग्लादेश दोनों देशों के बीच नदी के पानी का 50–50 प्रतिशत बंटवारा चाहता है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार अपने बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ने को राजी नहीं हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

समझौतों पर हस्ताक्षर

1. 1974 के भूमि सीमा समझौते के उपकरणों और 2011 के प्रोटोकॉल की अदला बदली.
2. 1974 के सीमा समझौते के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर पत्रों और अपने 2011 के प्रोटोकॉल की अदला बदली.
3. द्विपक्षीय व्यापार समझौते का नवीनीकरण
4. भारत-बांग्लादेश के बीच समुद्री यातायात
5. अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल
6. स्टैंडराइजेशन के क्षेत्र में सहयोग के लिए लिए भारत के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) और बांग्लादेश स्टैंडर्ड एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूशन (बीएसटीआई) के बीच सहयोग समझौता.
7. कोलकाता-ढाका-अगरतला बस सेवा के लिए समझौता
8. ढाका-शिलांग-गोवाहाटी बस सेवा के लिए समझौता
9. दोनों देशों के कोस्ट गार्ड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर
10. मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर
11. जाली भारतीय करेंसी की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर
12. भारत बांग्लादेश को दो अरब डॉलर की ऋण सहायता देगा.
13. बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में नीली क्रांति(मत्स्य क्रांति) और समुद्री सहयोग समझौता
14. चिटगांव और मोंगला बंदरगाहों को भारत के लिए खोलने का समझौता.
15. सार्क के आईईसीसी (जलवायु परिवर्तन के लिए भारत बंदोबस्ती) के तहत एक परियोजना के लिए समझौता.
16. भारतीय आर्थिक क्षेत्र पर समझौता.
17. साल 2015-17 के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के लिए समझौता.
18. बांग्लादेश-भारत शिक्षा सहयोग पर समझौता (गोद लेने पर)
19. अखौरा में इंटरनेट के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ लीज पर देने के लिए बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड (बीएससीसीएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के बीच समझौता.
20. बंगाल की खाड़ी में मरीन साइंस के क्षेत्र में साझा रिसर्च के लिए के ढाका विश्वविद्यालय, बांग्लादेश विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारत के बीच समझौता.
21. बांग्लादेश के राजशाही विश्वविद्यालय और भारत के जामिया मिलिया इस्लामिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर.
22. बांग्लादेश बीमा विकास एवं नियामक प्राधिकरण (आईआरडीए) और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बीच बांग्लादेश में शुरुआत करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर.

1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 16 मई, 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्रहमान कि अगुवाई में भूमि-सीमा समझौता हुआ था. 41 साल पहले शुरू हुए इस समझौते को अंतिम वैधानिक रूप देना न सिर्फ दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक जगत की एक अहम घटना के तौर पर देखा जा रहा है.

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

रंग-बिरंगे काग़ज़ की लैसें, एक लक्ष्मी की तस्वीर, थोड़ी-सी मिठाई और पूजा का सामान! किसी दुकान में दाख़िल होने से पहले उसने जेब में हाथ डाल कर पचास के नोट को टटोल कर निश्चित कर लिया था कि उसकी जेब में नोट है. फिर एक के बाद एक सामान ख़रीदता रहा, सब कुछ बजट में हो गया था. सैंतालीस रुपये में सब कुछ ले लिया था उसने. वो प्रसन्नचित घर की ओर चल दिया पर अचानक रास्ते में बैठे एक बूढ़े कुम्हार को देख उसे याद आया कि वो दीये खरीदने तो भूल ही गया था. दीये क्या भाव हैं बाबा?

सबूरी को मन में कैसे बसाए रखें

चौथी दुनिया ब्यूरो

सबूरी रखना कठिन है. फिर भी अपने जीवनकाल में हर इंसान कभी न कभी सबूरी अवश्य रखता है. प्रश्न तो सबूरी के स्तर का है. सबूरी की शक्ति को स्वयं ही बढ़ाना पड़ता है, जिससे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इंसान की सहनशीलता

गुरु के प्रति आस्था हर परिस्थिति में बनाए रखना ही एक मात्र मार्ग है, उन लोगों के लिए जो उनके समीप आना चाहते हैं. पर कुछ लोग जो सांसारिक वस्तुओं को पाने की इच्छा से सद्गुरु के पास आते हैं या इस आशा को मन में रखकर भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, कभी न कभी अपनी इच्छा-पूर्ति न होने पर या अपने कर्मफल भोगने के समय विश्वास खो देते हैं. किसी भी अवतार या सद्गुरु के समय में हर व्यक्ति की हर इच्छा पूरी नहीं हुई.

बढ़ सके. जब इंसान का अहंकार घटता है, तो सबूरी बढ़ती है, क्योंकि इंसान जीवन के हर पहलू को अहंकार से जोड़कर लेता है और इसलिए अधीर हो जाता है. इंसान जो कुछ भी कर रहा है, उसका कारक नहीं है और न ही वह उसके अंतिम परिणाम को नियंत्रित कर सकता है. सब कुछ किसी ईश्वरीय शक्ति, किसी सद्गुरु द्वारा संचालित होता है, इसका बोध होने पर इंसान कठिन क्षणों में प्रतिक्रियात्मक न होकर धीरे-धीरे सहनशीलता बनता जाएगा. सहनशीलता बढ़ाने के लिए सदैव गुरु के वचन याद रखने चाहिए तथा कठिनाई के क्षणों में गुरु को याद करना चाहिए.

श्रद्धा

श्रद्धा की ज्योति आत्मा में कैसे जगाए रखें? श्रद्धा की ज्योति सदैव आत्मा में प्रज्वलित रहती है, परन्तु उस पर माया का परदा पड़ा रहता है. ज्योति तो प्रज्वलित है ही, प्रश्न उठता है-परदा हटाने का. परदा हटाने के लिए मन को गुरु के प्रति केन्द्रित करें. आत्मा गुरु के प्रति समर्पित हो तो हर समय गुरु के विषय में ही सोचेगी और सदैव ही हर कर्म में गुरु की महानता, विशालता एवं कृपा का अनुभव होगा. इसी अनुभव के सहारे धीरे-धीरे स्वयं ही माया का परदा हटता जाएगा और श्रद्धा की ज्योति अवश्य प्रज्वलित होगी.

विश्वास और तार्किक बुद्धि

अध्यात्म में प्राय: दृढ़ निष्ठा या विश्वास एवं तार्किक बुद्धि की अलग-अलग दिशाएं निर्धारित की गई हैं. आपकी इस संबंध में क्या मान्यता है?

reasoning का मूल अर्थ तर्क, युक्ति या विचारणा मात्र नहीं है. उसका वास्तविक अर्थ है-किसी भी घटना या स्थिति के कारण को समंजित रूप में समझने का प्रयत्न करना. अर्थात हमारे भीतर, आस-पास या व्यापक रूप में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह क्यों हो रहा है, इसे तत्त्वत: जानने का प्रयत्न करना. मेरी दृष्टि में इसी समझ का चरम रूप दृढ़ निष्ठा या विश्वास है. दृढ़ निष्ठा-भाव या विश्वास इस समझ के बिना कायम नहीं रह सकता और बिना दृढ़ निष्ठा या विश्वास के यह समझ नहीं हो सकती. अत: ये दोनों वस्तुत: एक-दूसरे पर आश्रित हैं.

हमारा विश्वास एक हवा का झोंका आने पर अविश्वास में बदल जाता है. इसको हम कैसे रोक पाएं?

गुरु के प्रति आस्था हर परिस्थिति में बनाए रखना ही एक मात्र मार्ग है, उन लोगों के लिए जो उनके समीप आना चाहते हैं. पर कुछ लोग जो सांसारिक वस्तुओं को पाने की इच्छा से सद्गुरु के पास आते हैं या इस आशा को मन में रखकर भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, कभी न कभी अपनी इच्छा-पूर्ति न होने पर या अपने कर्मफल भोगने के समय विश्वास खो देते हैं. किसी भी अवतार या सद्गुरु के समय में हर व्यक्ति की हर इच्छा पूरी नहीं हुई. सद्गुरु उन इच्छाओं को कभी पूर्ण नहीं करते, जो उन्हें ईश्वर के समीप लाने के लिए बाधक होंगी. इस इच्छापूर्ति न करने के पीछे उनका ही हाथ रहता है. इसलिए जो व्यक्ति सुख और दु:ख दोनों में बाबा को देख सकता है, वह बाबा का असली भक्त होगा.

समर्पण क्या होता है

समर्पण का अर्थ होता है-सम रूप में अर्पण. हम ईश्वर को समरूप से जितना अर्पण करेंगे, ईश्वर भी उसी के अनुरूप देंगे. इस प्रकार इसका तात्पर्य है-ईश्वर अथवा गुरु के प्रति समान रूप से अर्पणता और यह अर्पण भावात्मक है. भावात्मक समर्पण का अर्थ यह है कि जब हमारे गुरु सब कष्टों को दूर करने का प्रयास करते-करते भी शुद्ध भाव अर्पण करने का प्रयास करते हैं, तो क्या हम गुरु कार्य करते-करते सब कुछ सहते हुए भी शुद्ध भाव अर्पित करते हैं? ईश्वर शुद्ध भाव देते हैं और शुद्ध भाव चाहते हैं. यदि वह नहीं है तो वह प्राथना है-कुछ मांगों की पुर्ति के लिए बाबा की आरती में है.

जया मनी जैसा भाव. तया तैसा अनुभव.

जिसके मन में जैसा भाव होता है, उसको उसी के अनुरूप अनुभव होता है. जिन भावनाओं से उन्हें अर्पण किया जाए, उसी शुद्धता से उनको ग्रहण किया भी किया जाए. कुछ लोग समझते हैं कि नारियल, कपड़ा आदि चढ़ाना भी भावार्पण है, ऐसा नहीं है. क्योंकि गुरु उसे नहीं बल्कि जिस भाव से दिया गया है, उसे ग्रहण करते हैं. यदि प्रयास करते हुए भाव बिगड़ गया तो वह अग्राह्य हो जाता है.■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

योग दिवस पर विवाद गलत है

अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कुछ मुस्लिम धर्मगुरू, मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड और कुछ नेता मोदी सरकार पर हमलावार हैं. मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड तो खुलकर अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के विरोध में खड़ा हो गया है. कांग्रेस का कहना है कि मोदी को योग की जगह काम करने की जरूरत है. अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा. संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया 150 देश से ज्यादा देश इस अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के मुहिम मोदी के साथ हैं, जिनमें 40 से अधिक इस्लामिक देश भी शामिल हैं. विरोध कर रहे मुस्लिम नेताओं का कहना है कि योग इस्लाम के खिलाफ है. योग से धर्म का क्या लेना-देना है. अगर ऐसा होता तो जो इस्लामिक देश इसमें शामिल हो रहे हैं, वे कभी शामिल नहीं होते. योग से शरीर के स्वास्थ्य को सही रखा जा सकता, कई ऐसी बीमारियां हैं जो योग करने से दूर हो सकती है. योग करने से अगर किसी का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो वो योग मत करे. योग दिवस को लेकर केवल राजनीति चमकाने के लिए विवाद खड़ा किया जा रहा है.

-कमला सक्सेना, *पालम, दिल्ली.*

काम कम बातें अधिक

कवर स्टोरी-मोदी सरकार का एक साल, काम कम बातें ज़्यादा (08 जून -14 जून 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. मैं कमल मोरारका से सहमत हूं कि मोदी सरकार काम कम बातें ज्यादा कर रही है. मोदी सरकार की एक साल के काम की समीक्षा की जाए, तो पाया जाएगा की मोदी सरकार ने एक साल में जितनी बड़ी-बड़ी बातें की उसका 20 प्रतिशत भी काम नहीं किया. अगर देखें तो स्वच्छता अभियान, नमामि गंगे, आदर्श गांव, जिसका मोदी ने बाजे-गांजे के साथ शुरूआत की थी उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ. मोदी सरकार ने लोगों से वादा किया था कि उनकी सरकार बनती है, तो महंगाई 100 दिन कम कर देंगे, लेकिन आज तक महंगाई कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ी है, जो अरहर की दाल 70 से 80 रुपये किलो तक मिलती थी, वो अब 100 से 120 रूपये किलो मिली रही है. मोदी के मंत्री की बात करें, तो सरकार के अधिकतर मंत्री केवल गलत बयानबाजी में लगे हुए हैं. इसलिए मोदी सरकार को ऐसे मंत्रियों पर लगाम लगाने की जरूरत है. मोदी सरकार को बात छोड़कर काम पर ध्यान चाहिए. उन्होंने जो जनता से वादे किए हैं. उसे पूरा करने और देश के विकास लिए काम करना चाहिए.

-पशुपति नाथ तिवारी, *बक्सर, बिहार.*

बिल न अदा करने वालों का कटे बिजली कनेक्शन

बिजली चोरों और बकाएदारों ने पावर कारपोरेशन को गर्त में पहुंचा दिया है. सपा सरकार की शह पर उसका लाडला वोटर कटिया डालकर घरेलू उपकरण ही नहीं उद्योग भी चला रहा है. कानपुर, मुरादाबाद, लखनऊ और रामपुर के घने मोहल्लों में बिजली विभाग का मीटर रीडर, मीटर तक जाने की हिम्मत नहीं करता. प्रदेश में अमूमन 400 से 600 करोड़ की बिजली हर महीने चोरी हो रही है. राज्य सरकार अविलंब उन उपभोक्ताओं की बिजली काटे, जिन्होंने तीन महीने से बिल का भुगतान नहीं किया है. बकाएदारों के विरुद्ध आर सी जारी कर उनकी सम्पत्ति कुर्क की जाए.

-राजकिशोर पाण्डेय, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र

चौथी दुनिया समाचार पत्र एक ऐसा समाचार पत्र है, जिसे हर उम्र के लोग पढ़ना पसंद करते हैं. इसमें प्रकाशित खबरें हर बार जानकारी प्रदान करती हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित सभी खबरें प्रभावित करने वाली होती हैं. इसमें विशेषकर संपादकीय और कवर स्टोरी पढ़कर बहुत खुशी होती है कि यह समाचार पत्र जनता की आवाज बनकर उसके हितों की आवाज उठाता है. चौथी दुनिया समाचार पत्र एक सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र है

-आलोक रंजन, *बेगूसराय, बिहार.*

विवादों का मंत्रालय

आलेख-मानव संसाधन विकास या विवाद मंत्रालय(08 जून -14 जून 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तजेक है. मोनिशा भटनागर ने सही सवाल किया है कि मानव संसाधन विकास या विवाद मंत्रालय. अगर देखा जाए, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी दोनों एक साल में काम से अधिक विवादों में रहे हैं. कभी स्मृति ईरानी की डिग्री और उनकी पढ़ाई को लेकर विवाद खड़ा होता है, तो कभी किसी और विषय पर. उन पर विपक्ष यह आरोप लगाता है कि वह आरएसएस के एजेंडा को लागू कर रही हैं और शिक्षा का भगवाकरण कर रही हैं. अभी हाल में देखें तो आईआईटी मद्रास के एक छात्र संगठन द्वारा मोदी के कार्यों को लेकर किए गए आलोचना पर उस छात्र संगठन को बैन कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद आईआईटी मद्रास ने अंबेडकर पेरियार नामक छात्र संगठन से बैन हटा लिया. मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने कामों के लिए कम विवादों के लिए अधिक चर्चा में रहता है. ■

-शिव शंकर अग्रवाल, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

दीपावली

चौथी दुनिया ब्यूरो

एक लड़का था. पखवाड़े बाद दीवाली थी, सारा शहर दीवाली के स्वागत में रोशनी से झिलमिला रहा था. कहीं चीनी मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे तो कहीं मिठाई की दुकानों से आने वाली मन-भावन सुगंध लालायित कर रही थी. उसका दिल दुकानों में घुसने को कर रहा था और मस्तिष्क तंग जेब के यथार्थ का बोध करवा रहा था. दिल की छोड़, दिमाग की सुन, उसको किसी बुजुर्ग का दिया मंत्र अच्छी तरह याद था. दीवाली मनाने को जो-जो जरूरी सामान चाहिए, उसे याद था. रंग-बिरंगे काग़ज़ की लैसें, एक लक्ष्मी की तस्वीर, थोड़ी-सी मिठाई और पूजा का सामान! किसी दुकान में दाष्हि ल होने से पहले उसने जेब में हाथ डाल कर पचास के नोट को टटोल कर निश्चित कर लिया था कि उसकी जेब में नोट है. फिर एक के बाद एक सामान ष्ठ रीदता रहा, सब कुछ बजट में हो गया था. सैंतालीस रुपये में सब कुछ ले लिया था उसने. वो प्रसन्नचित घर की ओर चल दिया पर अचानक रास्ते में बैठे एक बूढ़े कुम्हार को देख उसे याद आया कि वो दीये खरीदने तो भूल ही गया था. दीये क्या भाव हैं बाबा? तीन रूपए के छह. उसने जेब में हाथ डाल सिक्कों को टटोला. कुछ पैसे दे दो बाबू जी, सुबह से कुछ नहीं खाया. एक बच्चे ने हाथ फैलाते हुए अपनी नीरस आंखें उसपर जमा दी. सिक्के जेब से हाथ में आ चुके थे.

कितने दीये दूं, साब? मैं फिर आऊँगा' कहते हुए उसने दोनो सिक्के बच्चे की हथेली पर धर दिए और आगे बढ़ गया. बच्चा प्रसन्नता से खिलखिला उठा, उसे लगा जैसे एक साथ हज़ारों दीये जगमगा उठे हों. फिर कोई स्वरचित गीत गुनगुनाते हुए वो अपने घर की राह हो लिया.

वो एक लेखक था! अगले पखवाड़े आने वाली दीवाली दुनिया के लिए थी, लोग घी के दीये जलाएंगे. लेखक ने बच्चे को मुसकान देकर पखवाड़े पहले आज ही दीवाली का आनन्द महसूस कर लिया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

दिल्ली हिंदी अकादमी का क्या होगा?

अनंत विजय

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हर दिन एक नए विवाद में फंसती नज़र आती है. उप-राज्यपाल के साथ अफसरों की तैनाती को लेकर विवाद चल ही रहा है. इस विवाद के शोरगुल में दिल्ली की भाषाई अकादमियों में हुई नियुक्तियों का मामला कहीं खो-सा गया है. हाल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी और मैथिली-भोजपुरी अकादमी के उपाध्यक्षों की नियुक्तियां कीं. इन नियुक्तियों पर कोई सवाल खड़े नहीं हुए. हिंदी अकादमी में वरिष्ठ लेखिका मैत्रेयी पुष्पा की उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति का स्वागत ही हुआ, लेकिन साहित्यिक हलके में यह चर्चा तेज है कि मैत्रेयी के स्वागत में एक बात दबकर रह गई. चर्चा यह है कि मैत्रेयी पुष्पा की नियुक्ति के साथ-साथ हिंदी अकादमी की संचालन समिति के पच्चीस में से इक्कीस सदस्यों का मनोनयन भी कर दिया गया. ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा क्या रही, यह बात साफ़ होनी चाहिए. साहित्य से जुड़े कुछ लोगों का दावा है कि अब तक की परंपरा के मुताबिक, उपाध्यक्ष अपनी नियुक्ति के बाद सचिव के साथ मिलकर संचालन समिति के लिए मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के नाम अकादमी के

हर महीने पांच हज़ार रुपये के मानदेय का प्रावधान है. इन सारी बातों को देखते हुए हिंदी के वरिष्ठ लेखक उपेंद्र नाथ अश्क से जुड़ा एक वाकया याद आ रहा है. अश्क जी को एक पत्रिका से समीक्षा के लिए कुछ पुस्तकें प्राप्त हुईं. अश्क जी ने संपादक को लिखा कि समीक्षा के लिए पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं और वह यथा समय उनकी समीक्षा लिखकर भेज देंगे. इसके साथ ही अश्क जी ने यह भी लिखा कि अगर समीक्षा लिखने का मानदेय अग्रिम मिल जाता, तो समीक्षा हुलस कर लिखता. अगर दिल्ली सरकार सचमुच भाषाई अकादमियों को लेकर गंभीर है, तो उसे उनके उपाध्यक्षों के लिए बेहतर सुविधाओं का इंतजाम करना होगा, ताकि वे हुलस कर काम कर सकें.

पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री के पास भेजते रहे हैं. उन्हीं नामों में से मुख्यमंत्री संचालन समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं. इन आरोपों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी ने हिंदी अकादमी के गठन के वक्त से चली आ रही परंपरा तोड़ दी.

अब उपाध्यक्ष के ज़िम्मे संचालन समिति के सिर्फ़ चार सदस्यों के मनोनयन का अधिकार है, जो किया जा रहा है. इस परंपरा के समर्थन के पीछे दलील यह है कि उपाध्यक्ष और सचिव अपनी मर्जी से टीम का गठन करते हैं, लेकिन तथ्य यह भी है कि इस बारे में कोई लिखित नियम नहीं है. कई बार सरकार की तरफ़ से नाम आते हैं और कई बार अकादमी अपने नाम भेजती है, लेकिन संचालन समिति का सदस्य मनोनीत करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखा जाता रहा है कि जो भी सदस्य बने, उसका दिल्ली से सरोकार हो. कहने का मतलब यह है कि मनोनीत सदस्य दिल्ली का रहने वाला हो या फिर रोज़गार के लिए दिल्ली आता हो. बाद में एनसीआर को भी इसमें शामिल कर लिया गया. इस बार संचालन समिति में ऐसे लोग भी रखे गए हैं, जिनका दिल्ली से कोई संबंध नहीं है. दरअसल, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद साहित्य-संस्कृति उस पार्टी से जुड़े एक कवि के ज़िम्मे है. दिल्ली के साहित्यिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी है कि संचालन समिति में सदस्यों के मनोनयन में उन्हीं की चली है. सदस्यों के नाम देखकर प्रतीत भी ऐसा होता है, क्योंकि कई सदस्यों की उनसे क़रीबी सार्वजनिक मंचों पर देखी गई है. इस चर्चा की पुष्टि इस बात से भी होती है कि अभी हाल में अकादमियों के नवनियुक्त उपाध्यक्षों एवं संचालन समिति के सदस्यों की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विधि मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के साथ एक बैठक हुई. उक्त बैठक में कवि जी भी मौजूद थे.

सवाल यह उठता है कि बगैर किसी अकादमी की संचालन समिति के सदस्य होने के, बगैर सरकार में किसी पद पर होने के कवि महोदय उस सरकारी बैठक में किस हैसियत से उपस्थित थे? क्या कोई भी व्यक्ति अगर सत्ताधारी दल का सदस्य है, तो वह सरकारी बैठकों में भाग लेने के लिए योग्य हो जाता है? हैरत की बात यह है कि इस सरकारी बैठक में कवि महोदय की मौजूदगी पर किसी ने सवाल नहीं उठाए, न तो किसी उपाध्यक्ष ने और न किसी संचालन समिति के सदस्य ने? यह तो भला हो सोशल मीडिया का कि उस बैठक के बारे में जानकारी और उसकी तस्वीरें सार्वजनिक हो गईं. सरकारी बैठक में ग़ैर सरकारी शख्स की उपस्थिति से क्या संदेश निकलता है? क्या यह मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने साहित्य एवं संस्कृति का महकमा बगैर कोई पद दिए उनके हवाले कर दिया है? अब तक के संकेत तो यही मानने को कह रहे हैं. दरअसल, सरकारी भाषाई अकादमियों का हर जगह बुरा हाल है. साहित्य एवं संस्कृति को किसी भी सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखा ही नहीं. दिल्ली सरकार ने जब मैत्रेयी पुष्पा को हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया, तो साहित्य जगत में एक उम्मीद जगी थी, लेकिन जब संचालन समिति की बात सामने आई, तो उस उम्मीद पर आशंका के काले बादल मंडराते नज़र आने लगे. अब मैत्रेयी पुष्पा के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी और की बनाई टीम के साथ काम करने की है.

दिल्ली की हिंदी अकादमी का एक और दुर्भाग्य है कि वर्ष 2009 से वहां कोई नियमित सचिव नहीं है. ज्योतिष जोशी के हिंदी अकादमी के सचिव का पद छोड़ने के बाद से अब तक नियमित सचिव की नियुक्ति नहीं हो पाई है. एक बार जब अशोक चक्रधर हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष थे, तो उस वक्त सचिव के पद के लिए आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई. उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने इस पद को विज्ञापित किया और लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया. इस विज्ञापन के आधार पर लोगों को दो बार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और आख़िरी इंटरव्यू 14 अक्टूबर, 2014 को हुआ. उसके बाद विशेषज्ञों के पैनल ने तीन नामों की सूची तैयार कर संबंधित विभाग को भेज दी. उस वक्त दिल्ली में चुनी हुई सरकार नहीं थी और प्रशासन उप-राज्यपाल के हाथ में था, लेकिन तब भी किसी ने विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई सूची राज्यपाल की मंजूरी के लिए नहीं भेजी या अगर भेजी गई, तो उप-राज्यपाल सचिवालय से उसे मंजूर कर नोटिफाई नहीं किया गया.

दिल्ली की हिंदी अकादमी का एक और दुर्भाग्य है कि वर्ष 2009 से वहां कोई नियमित सचिव नहीं है. ज्योतिष जोशी के हिंदी अकादमी के सचिव का पद छोड़ने के बाद से अब तक नियमित सचिव की नियुक्ति नहीं हो पाई है. एक बार जब अशोक चक्रधर हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष थे, तो उस वक्त सचिव के पद के लिए आ-वेदन मंगाए गए थे, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई. उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने इस पद को विज्ञापित किया और लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया. इस विज्ञापन के आधार पर लोगों को दो बार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और आख़िरी इंटरव्यू 14 अक्टूबर, 2014 को हुआ. उसके बाद विशेषज्ञों के पैनल ने तीन नामों की सूची तैयार कर संबंधित विभाग को भेज दी. उस वक्त दिल्ली में चुनी हुई सरकार नहीं थी और प्रशासन उप-राज्यपाल के हाथ में था, लेकिन तब भी किसी ने विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई सूची राज्यपाल की मंजूरी के लिए नहीं भेजी या अगर भेजी गई, तो उप-राज्यपाल सचिवालय से उसे मंजूर कर नोटिफाई नहीं किया गया. अब ख़बर आ रही है कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई सूची केजरीवाल सरकार ने रद्द कर दी है और फिर नए सिरे से सचिव की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया चलेगी. यहां यह जानना दिलचस्प होगा कि सचिव का पैनल रद्द करने का आधार क्या रहा? क्या केजरीवाल सरकार सचिव पद पर भी अपने किसी मनचाहे अफसर को बैठाना चाहती है?

दरअसल, हिंदी अकादमी के सचिव का पद प्रतिनियुक्ति का पद है और उस पर खास योग्यता वाले शख्स की ही नियुक्ति हो सकती है. जिस पैनल को सरकार ने रद्द किया, उसमें हिंदी के एक दलित लेखक का भी नाम था. यह पैनल रद्द करने के बाद केजरीवाल सरकार ने एक दलित को हिंदी अकादमी का सचिव बनाने का अवसर भी गंवा दिया. हिंदी अकादमी के गठन के बाद से अब तक उसके सचिव पद पर किसी दलित की नियुक्ति नहीं हुई है. रही बात उपाध्यक्ष की, तो जनार्दन द्विवेदी के बाद दिल्ली हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष सिर्फ़ शोभा के तौर पर काम करते रहे हैं. हिंदी अकादमी में उनके बैठने के लिए एक कमरा ज़रूर है, लेकिन उनके लिए और कोई सुख-सुविधा नहीं है. हर महीने पांच हज़ार रुपये के मानदेय का प्रावधान है. इन सारी बातों को देखते हुए हिंदी के वरिष्ठ लेखक उपेंद्र नाथ अश्क से जुड़ा एक वाकया याद आ रहा है. अश्क जी को एक पत्रिका से समीक्षा के लिए कुछ पुस्तकें प्राप्त हुईं. अश्क जी ने संपादक को लिखा कि समीक्षा के लिए पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं और वह यथा समय उनकी समीक्षा लिखकर भेज देंगे. इसके साथ ही अश्क जी ने यह भी लिखा कि अगर समीक्षा लिखने का मानदेय अग्रिम मिल जाता, तो समीक्षा हुलस कर लिखता. अगर दिल्ली सरकार सचमुच भाषाई अकादमियों को लेकर गंभीर है, तो उसे उनके उपाध्यक्षों के लिए बेहतर सुविधाओं का इंतजाम करना होगा, ताकि वे हुलस कर काम कर सकें.

दूसरी बात यह कि दिल्ली सरकार को इन भाषाई अकादमियों को एक छत के नीचे लाना चाहिए. इस वक्त हिंदी अकादमी दिल्ली के किशनगंज इलाके के एक सामुदायिक केंद्र से चल रही है, जहां आधारभूत सुविधाएं भी नहीं हैं. हिंदी से जुड़े लोगों का वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है. दिल्ली सरकार को चाहिए कि वह इन अकादमियों को ऐसी जगह पर ले जाए, जहां वे आम आदमी की पहुंच में हों. एक ऐसे परिसर का निर्माण हो, जहां भाषा, संस्कृति एवं कला पर बात हो सके, किताबों पर चर्चा हो सके. दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं. ऐसी ही उम्मीद साहित्य, संस्कृति एवं कला जगत के लोगों को भी है. दिल्ली की हालत तो यह है कि यहां कोई भी एक किताब या पत्रिका खरीदने के लिए आपको कई किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. वर्ल्ड सिटी का सपना देख रहे दिल्लीवासियों के लिए यह भी आवश्यक है.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

चिकित्सा की पुरातन और शाश्वत पद्धति

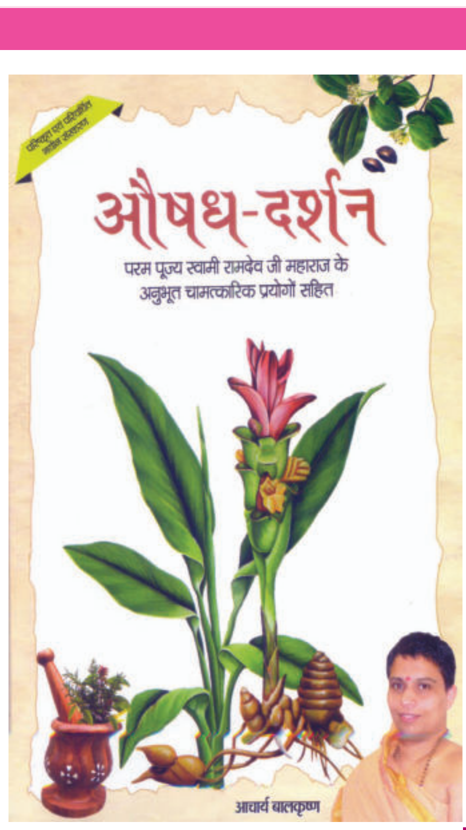

समीक्ष्य पुस्तक: औषध-दर्शन
लेखक: आचार्य बालकृष्ण
प्रकाशक: दिव्य प्रकाशन, कनखल, हरिद्वार
मूल्य: 60 रुप

चौथी दुनिया ब्यूरो

आयुर्वेद की अति प्राचीन एवं शाश्वत परंपरा से जन-सामान्य को परिचित कराने और उसका महत्व समझाने के लिए दिव्य प्रकाशन, हरिद्वार ने अपनी लोकप्रिय पुस्तक औषध-दर्शन का नवीन संस्करण बाज़ार में उतारा है. रोजमर्रा की ज़िंदगी में हमारे-आपके घरों में आज भी किसी रोग-विकार से पीड़ित होने पर सबसे पहले अजवायन, हींग, अदरक, काली मिर्च, तुलसी की पत्तियों, शहद, आंवला और हल्दी आदि का विभिन्न रूपों में सेवन किया जाता है. लोग डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों के पास तभी जाते हैं, जब उनके इस तरह के नुस्खे कारगर साबित नहीं होते या उन्हें अपेक्षित आराम नहीं मिल पाता. औषध-दर्शन नामक यह पुस्तक हिंदी के अलावा अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़ एवं नेपाली आदि भाषाओं में भी अपने पाठकों तक पहुंचती है.एक सौ अस्सी पृष्ठीय इस अनमोल पुस्तक औषध-दर्शन की भूमिका में संकल्प शीर्षक तले कहा गया है कि स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति पर हमारे देश की अधिकांश आबादी आश्रित है. आज दिन-प्रतिदिन छोटी-छोटी बीमारियों में भी एलोपैथी का प्रभाव बढ़ रहा है. ऐसे में परंपरागत एवं नैसर्गिक चिकित्सा विधा की स्वीकार्यता आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के समक्ष जन-सामान्य में व्यापकता के साथ बढ़े, यह एक कठिन एवं चुनौती पूर्ण कार्य है. पुस्तक में आयुर्वेद क्या है, जीवन में आहार का महत्व, आयुर्वेदीय पंचकर्म चिकित्सा, योगाभ्यास एवं षट्कर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य रक्षक आरोग्य सूत्र, चमत्कारी घरेलू उपचार, प्राथमिक चिकित्सालय यानी रसोईघर, पतंजलि योग पीठ द्वारा निर्मित मुख्य शास्त्रीय एवं स्वानुभूत योग, विभिन्न औषधियां आदि अध्यायों के तहत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं.

अपने जीवन में हमें किन चीजों से बचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज का सेवन किसी चीज के साथ निषेध है और किस चीज का सेवन किस चीज के साथ लाभकारी है आदि जानकारियों से अधिकतर लोग नावाकिफ रहते हैं. पुस्तक ऐसी तमाम जानकारियां उनसे साझा करती है, उनका ज्ञानवर्द्धन करती है. इस लिहाज से यह पुस्तक हर घर के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. पतंजलि योग पीठ और दिव्य प्रकाशन ने लोक हित में यह पुस्तक प्रकाशित करके बहुत सराहनीय कार्य किया है. लेखक आचार्य बालकृष्ण ने अपने अनुभव एवं प्रयोगों के आधार पर जो कुछ अर्जित किया, उसे उन्होंने अत्यंत सरल शब्दों में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
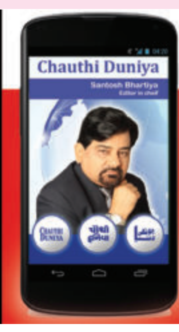
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

> इस अल्टीमेट 200 सीसी मशीन में न्यू फायरिंग, फ्यूल इंजेक्शन, एबीएस यूनिट, न्यू एक्जॉस्ट, अलग तरह का टेल लैम्प पल्सर के प्रदर्शन को बेहतरीन बनाते हैं और 141 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त स्पीड 11,000 आरपीएम पर 24.5 पीएस पावर के साथ देता है. इसका एबीएस फीचर फ्रंट और रियर व्हील के बीच उत्तम संतुलन बनाए रखता है और अल्टीमेट सुरक्षा मुहैया कराता है.

ह्युंदै की एसयूवी क्रेटा

क्रेटा पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में उपलब्ध होगी और साथ ही यह ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी. इसके साथ ही इस सेगमेंट में ऑटोमैटिक विकल्प के साथ आने वाली यह पहली कार होगी. इस कार की लंबाई 4.2 मीटर होगी.

ह्युंदै मोटर्स इंडिया अपनी बहुप्रतीक्षित एसयूवी क्रेटा को तय समय से पहले लॉन्च करेगी. कंपनी ने सीजन का फायदा उठाने के मकसद से ऐसा किया है. नई एसयूवी को लॉन्च करने के मकसद से कंपनी ने अपने प्रोडक्शन में भी जरूरी बदलाव किया है. क्रेटा पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में उपलब्ध होगी और साथ ही यह ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी. इसके साथ ही इस सेगमेंट में ऑटोमैटिक विकल्प के साथ आने वाली यह पहली कार होगी. इस कार की लंबाई 4.2 मीटर होगी. 2015 वर्ष में कॉम्पेक्ट मिड–साइज एसयूवी में छह फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि क्रेटा मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में बेहतर परफॉर्म करेगी. माना जा रहा है कि कंपनी का इरादा हर महीने 4 से 5 हजार यूनिट बेचकर एसयूवी बाजार के दस फीसदी हिस्से पर कब्जा करने की होगी. इसके साथ ही कंपनी को उम्मीद है कि क्रेटा की बिक्री का कम से कम दस फीसदी हिस्सा ऑटोमैटिक वर्जन से आए. कंपनी का मानना है कि 12 लाख रुपये में ऑटोमैटिक एसयूवी का उसका दांव गेमचेंजर हो सकता है. इस कार की कीमत 8 से 12 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

श्याओमी का कैमरा अंधेरे में भी करता है काम

श्याओमी कंपनी ने चीन में यी (Yi) कैमरा नाइट विजन एडिशन लॉन्च किया है. गौरतलब है कि श्याओमी की तरफ से यह तीसरा कैमरा प्रोडक्ट है और यह पहला नाइट विजन कैमरा है. श्याओमी के यी कैमरा नाइट विजन एडिशन में 940 एमएम का इंफ्रारेड कैमरा सेंसर दिया गया है. इसकी मदद से डिवाइस बिना किसी आर्टिफीशियल लाइट के भी काम कर सकता है. इसका व्यू बिना लाइट के भी 5 मीटर तक रहेगा. श्याओमी का यह कैमरा 4के ऑप्टिकल जूम फीचर के साथ आता है. जहां तक व्यूइंग एंगल की बात की जाए, तो यह कैमरा 92.7 डिग्री हॉरिजॉन्टल, 48.7 डिग्री वर्टिकल और 111.2 डिग्री डायगोनल व्यूइंग एंगल देता है. नए सेंसर के साथ कैमरा में कई स्टैंडर्ड फीचर्स भी दिए गए हैं. इनमें इमेज स्नैपशॉट्स जैसे फीचर हैं. यह एचडी(720 x1280 पिक्सल का रेजोल्यूशन) वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. इसके अलावा, वाई–फाई की मदद से लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा सकती है. यह डिवाइस माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट के साथ आता है, जिसकी मदद से 32 जीबी तक मेमोरी बढ़ाई जा सकती है. इसके अलावा, ये कैमरा टू वे वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकता है. इस कैमरा के साथ आने वाला ऐप एंड्रॉयड 2.3 जिंजरब्रेड और उससे ऊपर के वर्जन और आईओएस 7.0 और उससे ऊपर के वर्जन के साथ काम कर सकता है. इस कैमरे की कीमत लगभग 1500 रुपये है. ■

माइक्रोमैक्स का कैनवास टैब पी 690

माइक्रोमैक्स ने 3जी वॉइस कॉलिंग वाला पी690 टैबलेट लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि भारतीय बाजार में टैब की बड़ी मांग है और इसके मद्देनजर अच्छी टेक्नॉलजी के इस्तेमाल से किफायती दाम पर यह टैब लॉन्च किया है. इसमें 1.3 गीगाहर्ट्ज इंटेल क्वॉड कोर प्रोसेसर है. इसका डिस्प्ले 8 इंच का है, जो 1280 x 800 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है. इसमें 1 जीबी की रैम है. इसकी इंटरनल मेमोरी 8 जीबी की है, जिसे 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. यह टैबलेट एंड्रायड 4.4 किटकैट पर आधारित है. इसमें 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. इसमें 3 जी, वाई–फाई, ब्लूटुथ, जीपीएस, और फ्लैश की सुविधा है. इसकी बैटरी 4,000 एमएएच की है. इस टैब की कीमत 8,999 रुपये है. ■

पल्सर आरएस 200 लॉन्च

बजाज ऑटो ने पल्सर आरएस (रेस स्पोर्ट्स) 200 को लॉन्च किया है. यह बाइक युवाओं को पसंद में रखकर बनाएगी. चाहे इसकी शानदार लुक हो या मजबूत फिनिशिंग या फिर इसकी तेज रफ्तार, सब कुछ इसे अन्य बाइकों से अलग करती है. अभी बाजार में इसे दो रंग पीला व लाल में पेश किया गया है. इंजन और प्रदर्शन के लिहाज से भी यह बजाज की सबसे बेहतरीन बाइक है. इसका ट्रिपल स्पार्क 4 वाल्व डीटीएसआई इंजन फ्यूल इंजेक्शन और लिक्विड कूलिंग सिस्टम इसे अन्य बाइक से जुदा करती है. इस अल्टीमेट 200 सीसी मशीन में न्यू फायरिंग, फ्यूल इंजेक्शन, एबीएस यूनिट, न्यू एक्जॉस्ट, अलग तरह का टेल लैम्प पल्सर के प्रदर्शन को बेहतरीन बनाते हैं और 141 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त स्पीड 11,000 आरपीएम पर 24.5 पीएस पावर के साथ देता है. इसका एबीएस फीचर फ्रंट और रियर व्हील के बीच उत्तम संतुलन बनाए रखता है और अल्टीमेट सुरक्षा मुहैया कराता है. पल्सर आरएस 200 दिखने में बहुत ही आकर्षक है. न्यू फायरिंग, फ्यूल इंजेक्शन, एबीएस यूनिट न्यू एक्जॉस्ट, अलग तरह का टेल लैम्प पल्सर के प्रदर्शन को बेहतरीन बनाते हैं. आरएस 200 एबीएस की कीमत 1.30 लाख रुपये (दिल्ली एक्स शो रूम) तय की गई है तो नॉन एबीएस की 1.18 लाख रुपये है. ■

आ रहे हैं लेनेवो के मल्टी फीचर्स लैपटॉप

लेनोवो ने अपनी योगा सीरीज के लैपटॉप लॉन्च किए हैं. इस सीरीज के कुल चार मॉडल योगा 3 14, योगा 3 प्रो, योगा 300 और योगा 500 को लॉन्च किया गया है. इस लैपटॉप की खास बात यह है कि इन्हें 360 डिग्री तक रोटेड किया जा सकता है. इतना ही नहीं, भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज की शुरूआत मिड रेंज से शुरू की गई है. लेनोवो ने अपनी इस सीरीज के जो चार मॉडल लॉन्च किए हैं, उनकी शुरुआत 30,490 रुपये से शुरू होकर 1,14,990 रुपये तक है. कंपनी ने चारों मॉडल के फीचर्स अलग–अलग रखे हैं. साथ ही, कीमत भी अलग–अलग है.

योगा 300

योगा 300 में कंपनी ने इंटेल बेट्रायल (Baytrail) प्रोसेसर दिया है. ये लैपटॉप विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इस लैपटॉप में 11.6 इंच एचडी है, जो 1366x768 पिक्सल रेजोल्यूशन देता है. इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्जन दिया गया है.

योगा 500

योगा 500 14 इंच फुल एचडी 1920 x 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है. ये पांचवीं जनरेशन लैपटॉप है, जिसमें इंटेल का आई7 प्रोसेसर दिया गया है. यह भी विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. योगा 300 की तरह इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्जन दिया गया है.

योगा 3 प्रो

योगा 3 में 14 इंच फुल एचडी 1920 x 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन दी गई है. ये पांचवीं जनरेशन लैपटॉप है, जिसमें इंटेल का आई7 प्रोसेसर दिया गया है. यह भी विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. लैपटॉप में एनवीडिया जीफोर्स 940एम ग्राफिक्स कार्ड भी दिया गया है. इसका मॉडल काफी पतला है. यह गेमिंग के लिए काफी अच्छा डिवाइस है. इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्जन दिया गया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर

चीन के वुहान शहर में 3–7 जून के बीच आयोजित 21 वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 4 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा. पदक तालिका में पहला स्थान मेजबान चीन ने हासिल किया. चीन ने 15

पदक	खिलाड़ी	प्रतियोगिता	रिकॉर्ड
स्वर्ण	इंद्रजीत सिंह	शार्टपुट	20.41 मीटर
स्वर्ण	विकास गौड़ा	डिस्कस थ्रो	62.03 मीटर
स्वर्ण	टिंटू लूका	800 मीटर दौड़	02:01:53 मिनट
स्वर्ण	ललिता बाबर	3000 मी स्टिपल चेज	09:34:13 मिनट
रजत	जिनसन जॉनसन	800 मीटर दौड़	01:49:69 मिनट
रजत	लक्ष्मनन गोविंदन	10000 मीटर दौड़	29:42:81 मिनट
रजत.	एम आर पुवम्मा	400 मीटर दौड़	53.07 सेकेंड
रजत	जेस्ना मैथ्यू	4 गुणा 400 रिले(महिला)	03:33:81 मिनट
	टिंटू लुका		
	देबश्री मजूमदार		
	एम आर पुवम्मा		
कांस्य	धर्मवीर सिंह	200 मीटर दौड़	20.66 सेकेंड
कांस्य	लक्ष्मनन गोविंदन	5000 मीटर दौड़	13:36: 62 मिनट
कांस्य	श्रावणी नंदा	200 मीटर दौड़	23.54 सेकेंड
कांस्य	पूर्णिमा हेमब्रम	हैप्थेलॉन	5511 प्वांइट

पदक तालिका

स्थान	देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	चीन	15	13	13	41
2	कतर	07	02	01	10
3	भारत	04	05	04	13
4	जापान	04	03	11	18
5	बहरीन	03	03	02	08

स्वर्ण पदक सहित कुल 41 पदकों पर कब्जा किया. वहीं कतर 7 स्वर्ण पदक के साथ कुल 10 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा. भारत की ओर से इंद्रजीत सिंह ने शार्टपुट(गोलाफेंक) में 20.41 मीटर दूरी तक गोला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया. वहीं डिस्कस थ्रो में विकास गौड़ा ने 62.03 मीटर तक चक्का फेंककर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया. पीटी ऊषा की शिष्या टिंटू लूका ने महिलाओं की 800 मीटर दौड़ 02: 01:53 मिनट में पूरी करके स्वर्ण पदक हासिल किया. इसके साथ ही उन्होंने अगस्त, 2015 में बीजिंग में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है. हालांकि वे रियो ओलिंपिक का टिकट पाने से चूक गईं. अगर उन्होंने ये दौड़ 2 मिनट 1 सेकेंड में पूरी की होती तो उन्हें रियो ओलिंपिक का टिकट भी मिल जाता.3000 मीटर स्टीपल चेज में ललिता बाबर ने दौड़ 09:34: 13 मिनट में पूरी करके स्वर्ण पदक हासिल किया. पुरुष वर्ग में भारत के जिनसन जॉनसन ने 800 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया. जॉनसन के अलावा महिला टीम 4 गुणा 400 मीटर रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने में कामयाब रही. हरियाणा के धर्मवीर सिंह ने अनिल कुमार के 200 मीटर के 15 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को जरूर तोड़ा, लेकिन 20.66 सेकेंड के साथ वे कांस्य पदक ही जीत सके. उनके अलावा महिलाओं की 200 मीटर रेस में श्रावणी नंदा ने 23.54 सेकेंड के साथ कांस्य पदक हासिल किया.■

कोहली को अभी बेहतर कप्तान बनने में वक्त लगेगा: द्रविड़

महेंद्र सिंह धोनी की जगह टीम इंडिया की टेस्ट कप्तानी संभालने वाले विराट कोहली की कप्तानी के बारे में इंडिया-ए के कोच राहुल द्रविड़ का कहना है कि समय के साथ कोहली एक बेहतर कप्तान साबित होंगे. द्रविड़ ने कहा कि टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में स्थापित होने के लिए विराट कोहली को अभी समय देने की जरूरत है. द्रविड़ के अनुसार आगामी घरेलू दौरे उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं. द्रविड़ ने कहा कि भारत अगले ढाई सालों में कई घरेलू श्रृंखलायें खेलेगा. ये श्रृंखलायें कई लोगों को स्थापित होने में मददगार साबित होगी. यह विराट के लिए एक कप्तान के रूप में जमने का बेहतरीन अवसर होगा. राहुल ने कहा कि हमें विराट को लेकर अभी धैर्य बरतना चाहिए. उसे इस नई भूमिका के लिए तैयार होने के लिए समय देना होगा. हाल ही में इंडिया-ए और अंडर 19 टीम के कोच नियुक्त किए गए द्रविड़ ने कहा कि युवा खिलाड़ियों के पास आगामी श्रृंखला में चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का मौका रहेगा. भारत-ए की टीम आस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ जुलाई में और दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ अगस्त में घरेलू श्रृंखला की तैयारियों में जुटी है. उन्होंने कहा कि कोच की भूमिका उन्हें युवा खिलाड़ियों को मदद करने का अवसर देंगी. भारत ए और अंडर -19 टीमों के लिए हालांकि आईपीएल के ठीक बाद या घरेलू सत्र शुरू होने से ठीक पहले खेलना आदर्श समय होगा.■

राहुल ने कहा कि हमें विराट को लेकर अभी धैर्य बरतना चाहिए. उसे इस नई भूमिका केलिए तैयार होने केलिए समय देना होगा. हाल ही में इंडिया-ए और अंडर 19 टीम केकोच नियुक्त किए गए द्रविड़ ने कहा कि युवा खिलाड़ियों केपास आगामी श्रृंखला में चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का मौका रहेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फ्रेंच ओपन: वावरिंका और सेरेना के सिर सजा ताज

स्विटजरलैंड के स्टान वावरिंका ने इस साल के फ्रेच ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच का करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने का सपना तोड़ दिया और लाल बजरी के नए बादशाह बन गए. फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम करने वाले पिछले 25 सालों में सबसे उम्रदराज खिलाडी बन गए. 30 वर्षीय वावरिंका ने चार सेट कर चले मुक़ाबले में 4–6, 6–4, 6–3,6–4 से जीत दर्ज की. इससे पहले वावरिका ने साल 2014 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था. यह उनके करियर का दूसरा ग्रैंडस्लैम खिताब है. करियर स्लैम पूरा करने वाले आठवें खिलाडी बनने का जोकोविच का सपना भी टूट गया. पिछले चार साल में रोला गैरो में यह उनकी तीसरी हार है. वहीं दूसरी तरफ दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने अपनी बादशाहत बरकरार रखते हुए फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम कर लिया. सेरेना ने फाइनल में चेक गणराज्य की लूसिया साफारोवा को 6–3, 7–6, 6–2 से हराया. साफारोवा पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची थीं. सेरेना ने तीसरी बार फ्रेंच ओपन पर कब्जा किया है. इससे पहले उन्होंने वर्ष 2002 और 2013 में फ्रेंच ओपन खिताब जीता था. यह उनके करियर का 20 वां ग्रैडस्लैम खिताब है. इनमें तीन फ्रेंच ओपन, छह आस्ट्रेलियन ओपन, पांच विंबलडन और छह अमेरिकी ओपन खिताब शामिल हैं. पहले सेट में हरने के बाद साफारोवा ने दूसरे सेट में वापसी की लेकिन तीसरे सेट में सेरेना ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और खिताब अपने नाम कर लिया.■

दिसंबर में होगा फीफा अध्यक्ष का चुनाव

FIFA
For the Good of the Game

फीफा को नया अध्यक्ष 16 दिसंबर को मिल सकता है. फीफा के हवाले से ख़बर है कि सेप ब्लैटर के उत्तराधिकारी का चुनाव 16 दिसंबर को किया जा सकता है. हालांकि, चुनाव के लिए 16 दिसंबर की तारीख़ पर बात चल रही है, लेकिन इस पर आख़िरी फ़ैसला जुलाई में फीफा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया जाएगा. फीफ़ा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कार्यकारिणी समिति की बैठक जुलाई में होना तय हुआ है, लेकिन बैठक की तारीख़ फिलहाल तय नहीं है. फीफा में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी ब्लैटर ने लगातार पांचवीं बार अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए थे, लेकिन उन्होंने केवल चार दिन बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया था. इस वजह से फीफा मुश्किल में आ गई और फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी को लेकर नए-नए ख़ुलासे आए दिन होने लगे. नए अध्यक्ष चुने जाने तक 79 साल के ब्लाटर ही फीफा का काम देख रहे हैं. इस दौरान 2018 में रूस में होने वाली फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारी भी जारी है, जिसकी देखरेख महासचिव जेरोम वाल्के कर रहे हैं.

फीफ़ा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कार्यकारिणी समिति की बैठक जुलाई में होना तय हुआ है, लेकिन बैठक की तारीख़ फिलहाल तय नहीं है.

महासचिव वाल्के पर एक करोड़ डॉलर यानि क़रीब 64 करोड़ रुपये के भुगतान में शामिल होने का आरोप है, जो दक्षिण अफ्रीका ने मेज़बानी हासिल करने के लिए उन्हें दिए थे. हालांकि, जेरोम वाल्के ने अपने ऊपर लगे आरोप से इंकार किया था.■

बार्सिलोना ने जीता चैंपियंस लीग ख़िताब

क्लब फुटबॉल में खेले गए सबसे बड़े मुकाबले में स्पेन के क्लब बार्सिलोना ने यूवेंटस को 3-1 के अंतर से हराकर पांचवी बार चैंपियस लीग का खिताब जीत लिया है. बार्सिलोना ने मैच के पांचवे मिनट में ही बढ़त हासिल कर ली और उसके बाद विरोधियों पर जमकर हमले किए. यूवेंट्स के मशहूर गोलकीपर ग्यानलुगी बुफॉन कई बार नेयमार, मेस्सी और सुआरेज़ के वार को नाकाम किया लेकिन दूसरे हाफ़ में इस तिकड़ी को रोकना नामुमकिन हो गया. बार्सिलोना ने 3-1 से बाज़ी मार ही ली. बार्सिलोना की तरफ़ से इवान रैकिटि, लुईस सुआरेज़ और नेमार ने 1-1 गोल लिया. बार्सिलोना ने पांचवी बार चैंपियस लीग के ख़िताब पर कब्ज़ा किया है. इस साल बार्सिलोना ने ला लीगा, किंग्स कप और चैंपियंस लीग तीनों ख़िताब जीत लिए हैं. पिछले साल में यह तीसरा मौका है जब बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग का खिताब जीता है. बार्सिलोना को कप्तान 35 साल के ज़ावी हर्नांडिस का बार्सिलोना के लिए ये आखिरी मैच था और उन्हें शानदार विदाई मिली. इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 10 सालों में बार्सिलोना यूरोप का सबसे उम्दा क्लब रहा है.■

आईफा अवॉर्ड

द अवॉर्ड गोज टू...

मलेशिया में आयाजित 16 वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी (आइफा) में धूम मचाते हुए कंगना ने एक बार फिर बाजी मारी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपने नाम किया. वहीं शाहिद कपूर ने भी फिल्म हैदर के लिए बेस्टर एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया. इसके साथ ही अवॉर्ड विजेता कुछ इस प्रकार रहे...

बेस्ट पिक्चर : क्वीन
बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल (मेल)–शाहिद कपूर (हैदर)
बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल (फीमेल)–कंगना रनौत (क्वीन)
लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड– सुभाष घई
बेस्ट डायरेक्टर: राजकुमार हीरानी(पीके)
सपोर्टिंग एक्टर : रीतेश देशमुख (एक विलेन)
सपोर्टिंग एक्ट्रेस : तब्बू (हैदर)
स्टोरी : विकास बहल, चैताली परमार, परवेज शेख (क्वीन)
लिरिक्स : मनोज मुंतशिर (तेरी गलियां... एक विलेन)
सिंगर (मेल) : अंकित तिवारी (तेरी गलियां... एक विलेन)
सिंगर (फीमेल) : कनिका कपूर (बेबी डॉल... रागिनी एमएमए–2)
म्यूजिक डायरेक्शन: शंकर–एहसान–लॉय (2 स्टेट्स)
डेब्यू एक्टर : टाइगर श्रॉफ (हीरोपंती)
डेब्यू एक्ट्रेस : कृति सनोन (हीरोपंती)
डेब्यू डायरेक्टर : ओमंग कुमार (मैरी कोम), साजिद नडियादवाला (किक)
कॉमिक रोल : वरूण धवन (मैं तेरा हीरो)
नेगेटिव रोल : केके मेनन (हैदर)
आउट स्टैंडिंग परफॉमेंस फॉर रीजनल फिल्मस : लय भारी (मराठी)
आईफा वुमन ऑफ द ईयर अवॉर्ड– दीपिका पादुकोण

सरबजीत की बहन के किरदार में नज़र आएंगी ऐश्वर्या

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में दम तोड़ने वाले भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर बनने वाली फिल्म में उनकी बहन दलबीर कौर सिंह की भूमिका निभाएंगी. वह संभवत: इसमें बिना मेकअप के नजर आयेंगी. फिल्म के निर्माता जीशान कादरी ने बताया, उनके लुक को लेकर फिलहाल फैसला नहीं लिया है. हम किरदार की जरूरत के मुताबिक इसे तय करेंगे. रिसर्च डिपार्टमेंट इस पर बैठकर फैसला लेगा, लेकिन यह एक सच्ची कहानी है, इसलिए यह एक बिना मेकअप वाला लुक होगा. ऐश्वर्या फिल्म के लिए लुक टेस्ट जुलाई में देंगी. उमंग कुमार निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर महीने में पंजाब में शुरू होगी. जीशान ने कहा कि हम फिल्म के कलाकारों से बहुत खुश हैं. इस भूमिका के साथ ऐश्वर्या से बेहतर और कौन न्याय कर सकता है? ■

"फिल्म के निर्माता जीशान कादरी ने बताया, उनके लुक को लेकर फिलहाल फैसला नहीं लिया है. हम किरदार की जरूरत के मुताबिक इसे तय करेंगे. रिसर्च डिपार्टमेंट इस पर बैठकर फैसला लेगा, लेकिन यह एक सच्ची कहानी है."

कंगना ने किया सलमान संग काम करने से इंकार

यदि ऐसा होता तो यह दोनों स्टार्स के एक साथ काम करने का पहला मौका होता, लेकिन बात नहीं बन सकी.

अपने संजीदा अभिनय के लिए जाने जानी वाली मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के साथ काम करने से इंकार कर दिया है. पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि कंगना फिल्म सुल्तान में सलमान खान के साथ काम करती नजर आ सकती हैं. यदि ऐसा होता तो यह दोनों स्टार्स के एक साथ काम करने का पहला मौका होता, लेकिन बात नहीं बन सकी. बताया जा रहा है कि कंगना रनौत ने इस फिल्म में काम करने से इंकार कर दिया है. क्योंकि इस फिल्म की और विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून की डेट्स क्लैश कर रही हैं. कंगना ने विशाल भारद्वाज की फिल्म काफी पहले ही साइन कर ली थी. इसमें उनके साथ शाहिद कपूर और सैफ अली खान अभिनय करते नज़र आयेंगे.■

माधुरी दीक्षित को लेकर रेमो की बड़ी डांस फिल्म

रेमो डिसूज़ा ने बताया है कि वे माधुरी दीक्षित को लेकर एक फिल्म बनाएंगे. उन्होंने कहा कि ये एक डांस फिल्म होगी और इसमें माधुरी दीक्षित लीड रोल में होंगी. चूंकि वे इसे बड़े पैमाने पर पूरी भव्यता के साथ बनाना चाहते हैं इसलिए अभी कहानी, स्क्रिप्ट में काफी समय लगेगा.

एबीसीडी–2 के निर्देशक और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने कहा है कि यह फिल्म पूरी तरह माधुरी पर ही केंद्रित होगी. वरुण धवन और श्रद्धा कपूर स्टारर उनकी फिल्म एबीसीडी–2 19 जून को रिलीज हो चुकी है. इसकी तैयारियों में जुटे रेमो डिसूजा ने बताया है कि वे माधुरी दीक्षित को लेकर एक फिल्म बनाएंगे. उन्होंने कहा कि ये एक डांस फिल्म होगी और इसमें माधुरी दीक्षित लीड रोल में होंगी. चूंकि वे इसे बड़े पैमाने पर पूरी भव्यता के साथ बनाना चाहते हैं इसलिए अभी कहानी, स्क्रिप्ट में काफी समय लगेगा. डांस रिएलिटी शो झलक दिखला जा में माधुरी के साथ जज रहे कोरियोग्राफर–डायरेक्टर रेमो ने कहा कि वे पिछले चार साल से उनके करीब बैठे हैं और इस फिल्म पर बात करते रहे हैं. माधुरी ने कहा है कि वे जब भी तैयार हों, बता दें. उनके दिमाग में फिल्म की कहानी को लेकर कई आइडिया हैं और कुछ समय बाद ही पता लग पाएगा कि कौन सा आइडिया अंतिम रूप लेता है. ■

फिल्मों में नहीं आना चाहते थे टाइगर

हाल ही में एक्टर टाइगर श्रॉफ को आइफा में बेस्ट डेब्यू हीरो के अवॉर्ड से नवाजा गया है. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि लोग मुझे पसंद करेंगे. यह सम्मान मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है. टाइगर ने कहा, मैं शुरू से ही रितिक रोशन के डांस मूव्स से बहुत प्रभावित था. लेकिन कुछ और एक्टर्स भी हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं. शाहिद कपूर के डांस मूव्स बहुत ही क्लीन होते हैं. गोविंदा बड़ी सहजता से डांस करते हैं. मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उनके जैसा डांस कर भी पाऊंगा. उन्होंने बताया कि मेरे पिता अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गए थे. मैं जब फिल्मों में आने की तैयारियां कर रहा था तो इसी बात को लेकर नर्वस था कि मैं यहां टिक भी पाऊंगा या नहीं. मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था. उन्होंने कहा कि मैं फिल्मों में आना ही नहीं चाहता था. मुझे डर यह था कि मेरी पहली फिल्म चलेगी भी या नहीं. लेकिन फिल्म के डायरेक्टर–प्रोड्यूसर ने मुझ पर भरोसा जताया. मैं इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं. टाइगर ने यह भी बताया कि उनके पिता उनके काम में किसी भी तरह का दखल नहीं देते हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार-झारखंड

22 जून -28 जून 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

यादवी महासंग्राम की मोर्चाबंदी

इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने वाला है और उस रोचकता में जबरदस्त छौंक डालने का काम करेगा बिहार का यादववंशी मतदाता. सभी दलों की यादव मतदाताओं पर नजर है, इसीलिए राजनीति के दिग्गजों ने यादवों को अभी से ही लुभाने के लिए जाल बिछाने का काम शुरू कर दिया है. हालांकि इस चुनाव में मुस्लिम और महादलित मतदाताओं पर भी राजनीतिज्ञों की नजर है, क्योंकि यादवों से कमतर ही सही, लेकिन चुनाव में किसी पार्टी या उम्मीदवार को निर्णायक जीत दिलाने में इनकी भी भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता. निर्णय चाहे जो भी हो, लेकिन उस पर दिलचस्पी पूरे देश की बनी हुई है.

सरोज सिंह

लोहा ही लोहे को काटता है. कहावत पुरानी है और फिल्मों से लेकर सियासी दंगलों में भी यह कहावत अक्सर कही जाती है. इस बार बिहार के चुनावी जंग में भी लाहे को लोहे से काटने की बिसात बिछाने की मोर्चाबंदी तेज हो गई है. गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ होने के साथ ही अब चुनाव में फतह करने के लिए कील-कांटा दुरुस्त करने का काम दोनों खेमों में हो रहा है. नीतीश और लालू के साथ आ जाने के बाद से ही एनडीए खेमे में यह मंथन तेज है कि अब लड़ाई पहले से काफी कठिन हो गई है. मौटे तौर पर देखा जाए तो जदयू व राजद का खेमा यह मान कर चल रहा है कि यादवों और मुसलमानों के वोटों में अब बिखराव की कोई गुंजाइश नहीं रही है. इसमें अति पिछड़ा और महादलित वोट का छौंक भी लग जाए तो फिर नरेंद्र मोदी का विजय अभियान पाटलिपुत्र में रुकने से कोई नहीं रोक सकता है. लालू प्रसाद ने जिस तरह से सबको चौंकाते हुए नीतीश कुमार को नेता मान लिया, इसका भी अंदाजा एनडीए के नेताओं को नहीं था. यही वजह रही कि लालू के इस कदम के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक इसकी काट खोजने का काम शुरू हो गया. मौटे तौर पर यह राय बनी कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है. अगर यादव वोटों का मैनेजमेंट ठीक ढंग से कर लिया तो नीतीश और लालू की युगलबंदी की हवा निकल जाएगी. भाजपा के थिंकटैंक का मानना है कि मुसलमान वोटों में वह चाहकर भी ज्यादा सेंधमारी नहीं कर सकते हैं. जीतनराम मांझी के साथ आ जाने के बाद महादलित वोटों को लेकर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. विरोधी की सबसे बड़ी ताकत यादव वोट का धूव्रीकरण ही है और इसी में सेंधमारी के सारे जतन करने की जरूरत है. इसके बाद से ही भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए यादव बिरादरी को अपने पाले में करने के लिए पहले से चल रहे प्रयासों को और भी तेज कर दिया है. गौरतलब है कि भाजपा ने मिशन 2015 के लिए पहले से ही यह तय कर रखा है कि बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाली यादव बिरादरी को अपने साथ जोड़ा जाए. गांधी मैदान के ऐतिहासिक रैली में खुद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह संकेत दे दिया था कि यदुवंशियों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं भगवान कृष्ण की धरती से आया हूं और आपको अपने दिल के करीब लाना चाहता हूं. नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर लोकसभा के चुनाव में दिखा और भाजपा के चार यादव प्रत्याशी जीतकर लोकसभा में पहुंचे. इसके अलावा दूसरी सीटों में 15 से लेकर 20 फीसदी यादवों ने भी एनडीए के पक्ष में वोट किया. भाजपा की रणनीति विधानसभा चुनाव में इस 20 फीसदी वोटों को दोगुना से अधिक करने की है. भाजपाई मानते हैं कि अगर यह अभियान सफल रहा तो सूबे में भाजपा की सरकार दो तिहाई बहुमत से बनने से कोई नहीं रोक सकता है. ऐसा इसलिए कि यादव वोटों की ताकत ही नीतीश और लालू को आगे ले जाने की हैसियत रखती है.

जदयू के वरिष्ठ नेता प्रो निहोरा यादव कहते हैं कि बिहार के मान-सम्मान के लिए यदुवंशी सदा आगे बढ़कर रहे हैं और इस बार भी वह इस सूबे को सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए हमारे गठबंधन का साथ देंगे. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी ही बिहार को आगे ले जाएगी. अब तो कांग्रेस और एनसीपी भी हमारे साथ हैं, तो नरेंद्र मोदी के विजय रथ का चक्का यहा पंक्चर होना तय है.

अगर इस बड़ी ताकत में ढंग की सेंधमारी हो गई तो इसका असर बाकी के वोटों पर भी पड़ेगा और माहौल पूरी तरह भाजपा के पक्ष में दिखेगा. जानकार बताते हैं कि इसलिए यह तय किया गया कि एनडीए की ओर से कम से कम पचास उम्मीदवार यादव बिरादरी से उतारा जाएगा. इसमें यह ख्याल रखा जाएगा कि ऐसे ज्यादतर उम्मीदवार यादव बहुल सीटों से ही लड़ें. इतनी बड़ी संख्या में यादव उम्मीदवारों को लड़ाने का मकसद सूबे की यादव बिरादरी को यह संदेश देना है कि अब केवल और केवल लालू प्रसाद की तरफ आप नहीं नीहारिये, बल्कि भाजपा और इसके सहयोगी दल भी आपको दिलों में बैठाना चाहते हैं. कोशिश यह होगी कि नीतीश और लालू प्रसाद जितने यादव को टिकट दें, इससे ज्यादा टिकट एनडीए के खेमे से मिले और चुनाव प्रचार में यह बात प्रचारित किया जाए कि हमने तो लालू प्रसाद से ज्यादा सीटें आपको चुनाव लड़ने के लिए दिया है. भाजपा के नवल किशोर यादव और लोजपा नेता उपेंद्र यादव का आरोप है कि लालू और नीतीश यादव विरोधी हैं. जदयू के वरिष्ठ नेता प्रो निहोरा यादव कहते हैं कि बिहार के मान-सम्मान के लिए यदुवंशी सदा आगे बढ़कर रहे हैं और इस बार भी वह इस सूबे को सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए हमारे गठबंधन का साथ देंगे. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी ही बिहार को आगे ले जाएगी. अब तो कांग्रेस और एनसीपी भी हमारे साथ हैं, तो नरेंद्र मोदी के विजय रथ का चक्का यहा पंक्चर होना तय है. देखा जाए तो भाजपा की इस बदली हुई रणनीति का एहसास लालू प्रसाद को भी है, इसलिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि बिहार का चुनाव महादंगल है. यह देव और दानवों की लड़ाई है. यादव कभी भी भाजपा के जाल में नहीं फंसेंगे. आखिरकार भाजपा को यादवों की शक्ति का अंदाजा लग ही गया. यादवों ने लोगों को सत्ता में लाया, खुद राजपाट नहीं किया. लालू प्रसाद इस बात से आश्वस्त हैं कि यादव कभी भी भाजपा के बहकावे में नहीं आएंगे. पप्पू यादव अगर यादव बहुल इलाकों में जमकर अकेले चुनाव लड़ जाते हैं तो लालू प्रसाद की ताकत पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है. कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार के लगभग सवा सौ सीटों पर यदुवंशियों का संग्राम निर्णायक भूमिका निभाएगा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद की इस इलाके में ताकत को भाजपा और उसके सहयोगी दलों के साथ पप्पू यादव कितना कम कर पाते हैं, क्योंकि यहां जो तस्वीर बनेगी, वही नई विधानसभा में चमकेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

नेताजी कहिन

यह देव और दानवों की लड़ाई है. यादव कभी भी भाजपा के जाल में नहीं फंसेंगे. आखिरकार भाजपा को यादवों की शक्ति का अंदाजा लग ही गया. यादवों ने लोगों को सत्ता में लाया, खुद राजपाट नहीं किया.

-लालू यादव, राजद

बिहार के मान-सम्मान के लिए यदुवंशी सदा आगे बढ़कर रहे हैं. यदुवंशी सूबे को सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए हमारे गठबंधन का साथ देंगे. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी ही बिहार को आगे ले जाएगी.

- निहोरा यादव, जदयू

यादवों का इतिहास रहा है कि उसने कभी भी पिछलग्गू को अपना नेता नहीं माना है. नीतीश कुमार तो पिछलग्गू हैं. भला बिहार के यादव कैसे उन्हें अपना नेता मान सकते हैं.

- नवल यादव, भाजपा

2010 के चुनाव में यादवों का वोट लालू प्रसाद लोजपा को नहीं दिलवा पाए, जिसके कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. इस समय तो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे. रामविलास पासवान ने तो पासवान वोट राजद को 2010 में दिलवा दिया, पर लालू अपना वोट दिलवाने में फेल हो गए. इस बार भी यही होगा.

- उपेंद्र यादव, लोजपा

एक नज़र

उपेन्द्र ने की वादाखिलाफी

जदयू के वरिष्ठ नेता निरंजन कुशवाहा 'पप्पू' ने केन्द्रीय राज्यमंत्री उपेन्द्र कुशवाहा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है. पप्पू ने एक बयान जारी कर कहा है कि केन्द्रीय राज्यमंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने शहीद जगदेव प्रसाद के हत्यारों को सजा दिलाने का वादा किया था लेकिन अब तक इसपर कोई पहल नहीं की गई है. उन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि केन्द्रीय राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा इस महीने के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे राज्य में कुशवाहा समाज और युवा वर्ग के लोग महापंचायत और आन्दोलन कर केन्द्रीय राज्यमंत्री उपेन्द्र कुशवाहा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे. निरंजन ने बताया की 17 मार्च 2007 को गांधी मैदान में आयोजित कुशवाहा समाज और समान विचार वाली जातियों की सामाजिक एकता रैली के दौरान उपेन्द्र कुशवाहा ने जगदेव बाबू के हत्यारों को सजा दिलाने का वादा किया था .

साह की स्मृति मे स्वास्थ्य शिविर

समाज सेविका स्वर्गिया कृष्णा साह की तीसरी पुण्यतिथि पर अनीसाबाद स्थित साई मंदिर में, कृष्णा शिल्पालय एवं इंडियन इंस्टिच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऐंड रिसर्च, बेउर के संयुक्त तत्त्वावधान में, नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया. शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव प्रदीप कुमार तथा संस्थान के निदेशक–प्रमुख और बिहार प्रदेश कांग्रेस के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुलभ ने किया. शिविर में ढाई सौ से अधिक रोगियों की जांच वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा की गयी एवं दवाइयों का भी वितरण किया गया. शिविर में स्त्री–रोग, हृदय रोग, नेत्र रोग, विकलांगता आदि समस्याओं की जांच एवं पचार सहित, सुनने और बोलने, फिजियोथेरपी, स्पीच थेरपी तथा पैथोलॉजिकल जांच की भी व्यवस्था की गयी थी. प्रसिद्ध स्त्री–रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुराधा, डॉ. विमल कुमार, डॉ. विकास कुमार, डॉ. सीमा कुमारी, डॉ. पी कुमार, डॉ. असगर अली खान, डॉ. प्रभात कुमार, डॉ उपेन्द्र कुमार, डॉ. राजेश झा तथा डॉ. मुकेश कुमार ने अपनी सेवाएं दीं.अतिथियों का स्वागत शिविर के संयोजक राजेश्वर गुप्ता ने किया. इस अवसर पर समाजसेवी अरविन्द कुमार, विजय शंकर, कृष्ण कन्हैया, डॉ. तपसी ढेंक, संजय कुमार, विनय कुमार, बब्लू खान आदि समाजसेवी उपस्थित थे.

– रजनीकांत पांडेय

परचाधरियों ने किया हंगामा

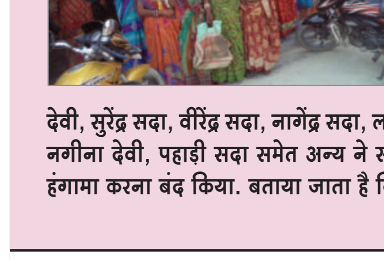

सीतामढ़ी जिले के पुपरी प्रखंड के बलहा मकसूदन पंचायत के नारायणपुर गांव निवासी महादलित परिवार के दर्जनों लोगों ने हंगामा किया. पानो देवी, संतोषी देवी, सकल सदा, सुनीता देवी, सुरेंद्र सदा, वीरेंद्र सदा, नागेंद्र सदा, लालपरी देवी, सुकेश्वरी देवी, नगीना देवी, पहाड़ी सदा समेत अन्य ने सीओ के आश्वासन के बाद हंगामा करना बंद किया. बताया जाता है कि 2012 – 13 में वास की भूमि के लिए सरकार द्वारा बासगीत परचा दिया गया. परंतु अब तक कब्जा नहीं दिलाया जा सका है.■

– गोविंद

खगड़िया

स्थानीय निकाय चुनाव

खगड़िया में जोर लगा रहे हैं सारे सूरमा

मनेन्द्र कुमार

राजेश कुमार | डॉ. संजीव कुमार | डॉ. उर्मिला ठाकुर | प्रमोद कुमार सिंह

खगड़िया–बेगूसराय स्थानीय निकाय क्षेत्र के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है. वहीं जनता परिवार के विलय के बाद होने वाले प्रत्याशी के घोषणा नहीं होने से जदयू व राजद अपना सुर अलग–अलग अलाप रहे हैं. जहां पटना में बैठे शीर्ष नेताओं के द्वारा दल को मिलाया जा रहा है ताकि भाजपा से मुकाबला आसानी से कर सके. लेकिन स्थानीय स्तर पर दल तो मिल रहे हैं लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिल रहे हैं. इस एमएलसी चुनाव के राजनीतिक परिपेक्ष्य की बात करें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों के द्वारा वर्तमान पार्षद तथा भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री रजनीश कुमार की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है तथा उनके द्वारा प्रखंड स्तर पर सम्मान समारोह सहित व्यापक पैमाने पर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है. इतना ही नहीं उन्होंने दूसरे दलों के जनप्रतिनिधियों को भी रिझाना शुरू कर दिया है. प्रखंड स्तरीय सम्मान समारोह का बड़े स्तर से आयोजन करना एक तरह से चुनावी लॉबिंग मानी जा रहा है. इस संबंध में भाजपा के जिलाध्यक्ष रामानुज चौधरी का कहना है कि रजनीश कुमार की जीत पक्की है. क्योंकि उन्होंने व्यापक पैमाने पर विकास कार्य किया है तथा जनप्रतिनिधियों को हक दिलाने के लिए सदन में बार–बार आवाज उठाई हैं.

प्रखंड स्तरीय सम्मान समारोह का बड़े स्तर से आयोजन करना एक तरह से चुनावी लॉबिंग मानी जा रहा है. इस संबंध में भाजपा के जिलाध्यक्ष रामानुज चौधरी का कहना है कि रजनीश कुमार की जीत पक्की है. क्योंकि उन्होंने व्यापक पैमाने पर विकास कार्य किया है तथा जनप्रतिनिधियों को हक दिलाने के लिए सदन में बार–बार आवाज उठाई हैं.

वहीं राजद तथा जदयू की बात करें तो बीते चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाली राजद नेत्री डॉ. उर्मिला ठाकुर भी अपने को उम्मीदवार मान कर जनप्रतिनिधियों से जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुकी हैं. उम्मीदवारी को लेकर डॉ. उर्मिला ठाकुर का कहना है कि माननीय लालू यादव का आर्शीवाद प्राप्त है, इसलिए इस बार भी टिकट मिलना तय है इसलिए मैंने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है. लेकिन संशय की स्थिति तब पैदा हो गई जब जदयू विधायक तथा पूर्व मंत्री आरएन सिंह के पुत्र डॉ. संजीव कुमार ने खगड़िया–बेगूसराय के सभी प्रखंड मुख्यालयों के सम्मान समारोह का आयोजन कर अपनी उम्मीदवारी जता दी है. डॉ. संजीव जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी है. गौरतलब बात है कि उनकी पक्की उम्मीदवारी मानकर पूरे जदयू कार्यकर्ताओं ने गांव–गांव सम्पर्क अभियान की शुरुआत कर दी है तथा जनप्रतिनिधियों के रिझाने में लगे हैं. वहीं इस राजद–जदयू के द्वंद्व को लेकर मतदाताओं में संशय की स्थिति बनी हुई है तथा राजनीतिक गलियारों में तरह–तरह की चर्चा हो रही है. वहीं वाम मोर्चा के द्वारा पूर्व विधान पार्षद ऊषा सहनी को प्रत्याशी घोषित किया है तथा बिना ताम–झाम के प्रचार का कार्य हो रहा है. यदि इस चुनाव में लड़ाई की बात की जाय तो यदि अगड़ी–पिछड़ी का माहौल बना तो भाजपा प्रत्याशी रजनीश कुमार कड़े मुकाबले में फंस सकते हैं. उधर मुखिया संघ ने बेगूसराय के मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह को प्रत्याशी घोषित कर सबको सकते में डाल दिया है. कांग्रेस पार्टी की बात की जाय तो उसने चुनावी समर में मूक दर्शक की स्थिति में अभी तक अपना पत्ते नहीं खोले हैं. लेकिन यदि जीत हार की बात की जाय तो कई प्रत्याशियों के बीच टक्कर होने की प्रबल संभावना है. जबकि आमलोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि चुनाव का समय आता है तो उम्मीदवारों का तांता तो लग जाता है तथा तरह–तरह के वायदों के बीच विकास का मुद्दा गौण कर दिया जाता है. इस संबंध में खगड़िया जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिह का कहना है कि जो जनप्रतिनिधि जनता के हित–हक तथा वाजिव हिस्सा दिलाने की बात सदन तक उठायेगा, उस पर खगड़िया का भरोसा जरूर होगा. लेकिन 25 मई को हुई बैठक में प्रमोद सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिये जाने से मुकाबला बेहद रोचक हो गया है. अब देखना है कि इस बार किसके सिर पर एमएलसी का ताज होगा. इसको लेकर चौक–चौराहों पर राजनीतिक चर्चायें शुरू हो गई है.■

feedback@chauthiduniya.com

खेल बिगाड़ सकती है एनपीपी

रजनीकांत पांडेय

भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन बिहार में इन दोनों दलों में तनाव है. दोनों राजनीतिक दल भले ही लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर के मित्र रहे हों लेकिन दोनों में तलवारें खिंचना कोई नई बात नहीं. अनेक प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों पर असहमति नजर आती रही है. अब शायद समय आ चुका है कि इन सब बातों को भुला कर बिहार में दोनों पार्टी को आगे चलना चाहिए. दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की यही आम राय है. एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी ए संगमा के नेतृत्व में फरवरी में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के विकास के हित में एनडीए के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला लिया गया था. एनपीपी के कार्यकर्ता तो एनडीए के दलों को बडा भाई मान कर साथ चलने को तैयार हैं.

दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की यही आम राय है. एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी ए संगमा के नेतृत्व में फरवरी में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के विकास के हित में एनडीए के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला लिया गया था.

गौरतलब है कि बिहार में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सवर्ण और पिछड़े समाज के राजनीतिक कार्यकर्ताओं व नेताओं ने संगठित किया है. एनपीपी के प्रवक्ता रोशन पाठक कहते हैं कि काफी कम समय में एनपीपी ने बिहार के लोगों के दिलों में मजबूत जगह बना ली है.

जनकार बताते हैं कि एनपीपी अगर बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बिहार बीजेपी को होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

अन्य ख़बरें

चला जागरूकता अभियान

सुगौली को अनुमंडल एवं करमवा रघुनाथपुर को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर जनजागरण मंच के सचिव मधुरेन कुमार के नेतृत्व में करमवा रघुनाथ पुर बाजार पर जागरूकता अभियान चलाया गया. इस अभियान के तहत प्रखंड व अनुमंडल बनाने के साथ ही पानी टंकी, डीग्री कॉलेज, छपवा मे पुलिस आउट पोस्ट बनाने की मांग भी की गयी. ज्ञात हो कि सुगौली को अनुमंडल व करमवा रघुनाथपुर को प्रखंड बननने की मांग लंबे समय से चल रही है और इसको लेकर जनजागरण मंच के सदस्यों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था. पूर्व में भी इस मांग को लेकर हजारों लोगों के हस्ताक्षर युक्त मांगपत्र मुख्यमंत्री सहित कई वरीय अधिकारियों के पास भेजा गया है. मौके पर पाण्डेय विनोद कुमार,अमित सिंह,मनोज सिंह,विजय जयसवाल,मो.ऐनुल,गुडु कुमार,मुना मोबाईल सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे.

– इन्तेजारुल हक

प्यार में गई जान

गोगरी अनुमंडल क्षेत्राधीन राटन गांव में एक लड़की ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली. लड़की की शादी सात जून को होनी थी. पर लड़की के प्रेमी ने वर पक्ष को चिट्ठी लिख कर अपने और लड़की के प्रेम प्रसंग का खुलासा कर दिया. जिससे वर पक्ष ने शादी से इन्कार कर दिया. लड़की की शादी साहेबपुर कमाल में तय हुई थी. पुलिस के अनुसार लड़की का गांव के ही राजेन्द्र मंडल के पुत्र प्रह्लाद कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इधर लड़की की शादी बेगूसराय जिले साहेबपुर कमाल में तय हो गयी थी. इससे खफा होकर इसके प्रेमी ने वर पक्ष को चिट्ठी लिखकर अपने व लड़की के बारे में सबकुछ बता दिया. लड़की के पिता ने बताया कि इस वजह से शादी करने से वर पक्ष मना कर दिया. जिस कारण इनकी लड़की ने आत्महत्या कर ली. इस संदर्भ में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. गोगरी थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है.

– गीता कुमार

जल समस्या पर विचार गोष्ठी

नगर विकास परिषद, गया की ओर से हादी हाशमी स्कूल में जल समस्या और समाधान विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया. वक्ताओं ने कहा कि गया शहर में फलगू जैसी नदी है, जिससे जल की आपूर्ति गया शहर में अच्छे ढंग से हो सकती है. लेकिन प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव तथा भ्रष्टाचार के कारण शहर वासियों को गर्मी के मौसम में पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है. अब भी शहर वासी नहीं चेते तो जल संकट की समस्या स्थाई रहेगी. गोष्ठी में गया शहर की पानी की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार 25 वर्षो से गया शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक प्रेम कुमार को ठहराया गया. गोष्ठी में 450 करोड़ की एडीबी योजना की मॉनिटरिंग करने रामशिला, ब्रहमयोनी पहाड़ पर वाटर रिचार्ज स्टेशन बनाने, सभी वार्डो में वर्षा जल संग्रहण कमेटी गठन करने, फलगू पर वीयर बांध का निर्माण करने, तलाबों पोखरों को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की गयी. पूर्व सांसद रणजीत सिंह, इन्दू सहाय, राजेन्द्र प्रसाद, हरि केजरीवाल, कौशलेन्द्र प्रताप, शिववचन सिंह, राजन सिजुआर समेत अनेक गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये.

दूषित पानी की जांच

गया शहर में नगर निगम की ओर से आपूर्ति होने वाले पाइप लाइन से दूषित पानी की शिकायत की जांच शुरू की गयी है. गया शहर के विभिन्न स्थानों पर जलापूर्ति के मेन पाइप लाइन तथा ब्रांच लाइनों की जांच की जा रही है. नगमतिया रोड, बनिया पोखर, मारूफगंज , नाला रोड, पिता महेश्वर, रमणा समेत अन्य कई मोहल्ले में नगर निगम की आपूर्ति पाइप लाइन से दूषित पानी आने की शिकायत आ रही थी. इसका मुख्य कारण शहर के नई गोदाम, मुरली हिल, बागेश्वरी, कोयरीबारी आदि इलाके में पाइप लाइन में अवैध तरीके से टुलु पंप लगाकर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है. अब गया नगर निगम ने अवैध कनेक्शन लेने वालों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है.■

–सुनील सौरभ

सीतामढी

जिला जदयू का अगला सारथी कौन बनेगा

11 अगस्त 1998 सीतामढ़ी समाहरणालय गोली कांड मामले में पूर्व सांसद नवल किशोर राय समेत अन्य को सजा होने के साथ ही सीतामढ़ी जिले में जदयू नाजुक स्थिति में पहुंच गयी है. अब इस दल में नया प्राण फूंकने को लेकर पार्टी संगठन को एक मजबूत व जनधार वाले सारथी की दरकार है. वैसे पार्टी के एक पूर्व सांसद व एक विधान पार्षद समेत तीन विधायक अब भी जिला में पार्टी की चुनावी नैया पार लगाने को प्रयासरत हैं, मगर एक जाति विशेष के मजबूत जनाधार वाले स्थानीय नेता की कमी न्यायालय के फैसले के बाद महसूस की जाने लगी है. जिले की राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अब पार्टी के अगले सारथी की कमान कौन संभालेगा ...

वाल्मीकि कुमार

डॉ. अर्जुन राय | डॉ. रंजू गीता | गुड्डी देवी | राजकिशोर कुशवाहा | राजेश चौधरी | राणा रणधीर सिंह चौहान | सुनीता सिंह चौहान

सीतामढ़ी जिले की राजनीति में अब तक सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं में दो लोगों का नाम शामिल है. इनमें पहला तो कांग्रेस के पूर्व सांसद स्व. नागेंद्र प्रसाद यादव है, जबकि दूसरे नंबर पर जदयू के पूर्व सांसद नवल किशोर राय का नाम शामिल है. यादव बिरादरी की उक्त दो राजनीतिक हस्तियों का राजनीतिक जीवन जिले के जन मानस में आज भी चर्चा का केंद्र बना है. बताया जाता है कि वर्ष 1965 से लेकर 1977 तक स्व. नागेंद्र प्रसाद यादव कांग्रेस के टिकट पर सीतामढ़ी से बतौर सांसद प्रतिनिधित्व करते रहे. वहीं नवल किशोर राय साल 1991 एवं 1996 में जनता दल की टिकट पर सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए थे. 1998 में पुपरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद साल 1999 में वे पुन: जनता दल के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए थे. दोनों ही का संसदीय कार्यकाल जिले की जनता में अब भी चर्चित है. पूर्व सांसद स्व. यादव ने आजादी के बाद विकास का जहां ढांचा तैयार कर लोगों की समस्याओं के निदान का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं पूर्व सांसद नवल ने सडड़क, रेल, आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष समेत अन्य क्षेत्रों में विकास का जाल बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. जानकारों की मानें तो अब तक जिले में सड़क व रेल समेत अन्य क्षेत्र में कराये जा रहे विकास कार्यों की नींव में पूर्व सांसद नवल किशोर राय के अथक परिश्रम का अंश निहित है. जहां तक राजनीतिक दल में पकड़ की बात है तो इस संबंध में यही चर्चा है कि यादव बिरादरी के अलावा अन्य तबकों में भी गहरी पैठ रखने वाले नेताओं में फिलहाल नवल किशोर राय के अलावा कोई नहीं रहा है. जब सूबे बिहार में जनता दलयू अस्तित्व में आया तब से लेकर अब तक नवल सीतामढ़ी जिले में पार्टी के विकास व मजबूती की कमान संभाल रहे थे. पिछले दिनों 11 अगस्त 1998 गोली कांड मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद सजा मिलते ही उन्हें सीतामढ़ी जिले से बाहर मुजफ्फरपुर स्थित सेंट्रल जेल भेज दिया गया, तब से ही समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नेतृत्व विहीनता की स्थिति बन गयी है.

सूबे बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के करीबी लोगों में एक पूर्व सांसद नवल के जेल जाने के बाद अब जिले में चल रही राजनीतिक चर्चाओं पर नजर डालना आवश्यक है. चर्चा चल रही है कि लंबे अंतराल के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में नवल किशोर राय को जदयू की टिकट पर चुनावी समर में उतारा जाना था, परंतु कतिपय कारणों से टिकट डॉ. अर्जुन राय को दे दिया गया. नतीजतन पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक सिरे से नेतृत्व को नकारते हुए जातिगत आधार पर मतदान का निर्णय चोरी–छिपे ले लिया. नतीजा हुआ कि जदयू प्रत्याशी डॉ. अर्जुन राय एक लाख मत भी नहीं ला सके, वहीं राजद की टिकट पर चुनावी समर में उतरे पूर्व सांसद सीतामराम यादव को तकरीबन सवा दो लाख मत प्राप्त हुआ और वे दूसरे नंबर पर आकर अटक गये. जानकारों की मानें तो देश में चली नमो आंधी का अगर असर नहीं होता तो राजद प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करा सकते थे. उक्त चुनाव के दौरान पूर्व सांसद नवल किशोर राय ने भी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कार्यकर्ताओं से की थी, परंतु कार्यकर्ताओं ने उनकी बातों को अनसुना कर राजद अथवा रालोसपा प्रत्याशी राम कुमार शर्मा के पक्ष में मतदान करने से परहेज नहीं किया. बताया जाता है कि कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की कार्य प्रणाली व निर्णय को लेकर आक्रोश व्याप्त था.

अब जिले में पार्टी की स्थिति से अवगत होना जरूरी है. फिलहाल सीतामढ़ी जिले में जदयू के एक पूर्व सांसद डॉ अर्जुन राय व विधान पार्षद राज किशोर कुशवाहा ही हैं. जबकि क्रमश रुन्नीसैदपुर से गुड्डी देवी, बाजपट्टी से डॉ रंजूगीता व बेलसंड से सुनीता सिंह चौहान बतौर विधायक सरकार की विकास योजनाओं के बारे में बताने को मौजूद हैं. इसके अलावा बेलसंड विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति राणा रंधीर सिंह चौहान व रुन्नीसैदपुर विधायक गुड्डी देवी के पति राजेश चौधरी जिले में पार्टी संगठन की मजबूती के साथ ही सरकार का पक्ष मजबूत करने में लगे है. बताया जाता है कि जिले में फिलहाल कोई ऐसा पार्टी नेता नहीं है जो व्यक्तिगत राजनीति के अलावा पार्टी संगठन के हित में कार्य करने वाला हो. जिलाध्यक्ष राम जीवन प्रसाद भी लंबे अर्से से असहाय की तरह अनेकों मौके पर पार्टी के कार्यक्रमों की सफलता की खातिर नेताओं के दरवाजे पर दस्तक देते रहे हैं. मगर भरपूर मदद की कमी उन्हें भी खलती रही है. शहर में पार्टी के जिला कार्यालय की कमी की भरपायी अधिकांश कार्यकर्ता पूर्व सांसद नवल किशोर राय के डुमरा रोड स्थित आवास पहुंच कर करते रहे है. अक्सर कार्यकर्ताओं की बैठक समेत अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं का लगाव रहा है. परंतु अब यह भी एक गंभीर समस्या बन गयी है कि गांवों से चल कर आने वाले कार्यकर्ता अब कहा जायेंगे ? सीधी सी बात है कि जब नेता ही नहीं है तो कार्यकर्ताओं की सुनेगा कौन? जहां तक दूसरे पूर्व सांसद का सवाल है तो उनके रहने अथवा आने–जाने की जानकारी महज चंद करीबी समर्थकों के अलावा किसी को नहीं होती. विधान पार्षद राज किशोर कुशवाहा चूंकि राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा मनोनीत हैं, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है. मामला विकास योजना का हो अथवा पार्टी के कार्यक्रम का, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता रहा है. शेष बचे विधायकों के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वे अपने क्षेत्र को छोड़कर जिला संगठन के लिए वक्त निकाल सकें. कुल मिला कर देखा जाये तो सीतामढ़ी जिले में सत्ताधरी जदयू फिलहाल असहाय की अवस्था में प्रतीत होने लगी है. जानकारों की मानें तो अब एक बार फिर जिले में पार्टी के अंदर वर्चस्व को लेकर नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है. माना जाता रहा है कि जिलाध्यक्ष राम जीवन प्रसाद से लेकर युवा जदयू तक में शामिल कार्यकर्ता पूर्व सांसद नवल किशोर राय खेमे के ही हैं. जबकि कुछ पूर्व से लेकर वर्तमान तक के सक्रिय कार्यकर्ता पूर्व सांसद डॉ अर्जुन राय की सत्कार में रहते आये हैं. ऐसी स्थिति में जिले में पार्टी संगठन के हालात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है. अब सूबे बिहार सरकार के मुखिया जिला में पार्टी संगठन की मजबूती के लिए किस को सारथी बनाते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं. चर्चा है कि खास कर ऐसे समय में जिला में पार्टी संगठन को झटका लगा है, जब सामने विधान परिषद व विधानसभा का चुनाव चौखट पर दस्तक दे रहा है. वैसे विधान परिषद चुनाव पर कम मगर विधानसभा चुनाव पर इसका व्यापक असर पड़ने की आशंका व्यक्त की जाने लगी है. समय रहते पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहा तक अपनी चुनावी राह आसान कर पाने में सफल होता है. इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है. वैसे पार्टी कार्यकर्ता भी फिलहाल आराम की मुद्रा में तमाशबीन बने हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

अन्य ख़बरें

नीतीश-लालू को अब मौका नहीं

जदयू और राजद के बीच गठबंधन होने और नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने पर वरिष्ठ भाजपा नेता वरुण सिंह ने प्रतिक्रिया दी और बताया कि जदयू–राजद बेमेल गठबंधन है. दोनों दल चुनावी तैयारियों में भले ही जुट गए हैं लेकिन एनडीए के समक्ष यह गठबंधन नहीं चल पाएगा क्योंकि बिहार की जनता इनकी चाल बखूबी समझ चुकी है. वरुण सिंह ने आगे कहा कि सुशासन बाबू का सुशासन जनता देख चुकी है, भाजपा का दामन छोड़ते और जंगल राज का दामन थामते ही बिहार की धरती कांप उठी. जनता अब इनको मौका नहीं देगी. नरेन्द्र मोदी के एक साल में किये गए विकास कार्यो को याद कर जनता भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ मौका देगी. बिहार में जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार में तेजी आई है.बिहार के विकास का सपना अधूरा है जिसे एनडीए सरकार ही पूरा कर सकती है.

– भारती

कुव्यवस्था से उपभोक्ता सड़क पर

ढाका नगर के पंचायतवासियों ने बिजली विभाग की लचर व्यवस्था के खिलाफ जम कर हंगामा किया और घंटों सड़क को जाम किया. ढाका गांधी चौक, अजाद चौक,ढाका–मोतिहारी, ढाका– पचपकड़ी पथ, ढाका–फुलवरिया पथ, ढाका– घोड़ासहन पथ को आंदोलनकारी घंटों जाम किये रहे और नारेबाजी करते रहे. चक्का जाम का नेतृत्व अनवर फारूकी कर रहे थे जब कि मौके पर पप्पू चौधरी, महफूज आलम, राजेश कुमार, आसिम सलिम, इम्तेयाज आलम, गुड, शबिर, अतिक, अब्दुल रहमान, चन्दन सर्राफ, मोहसिन कमाल आदि उपस्थित थे. लोगो का आरोप था कि बिजली विभाग बिजली की आपूर्ति कम मात्रा में करती है और शिकायतों का निपटारा नहीं करती. सूचना पर सिकरहना एसडीओ मनोज कुमार रजक, नगर कार्यपालक पदाधिकारी व डीसीए–लआर विरेन्द्र कुमार जाम स्थल पर पहुंच कर आंदोलनकारियों से वार्ता कर जाम को समाप्त कराया. एसडीओ रजक ने जाम करने वालों को अश्वासन दिया कि 15 दिनो के अंदर बिजली आपूर्ति सूचारू रूप से चालू हो जाएगी. एसडीओ ने बिजली आपूर्ति विभाग के कनीय अंभियता धीरज सती को भी लोगो की समस्या के निदान करने का निर्देश दिया.■

– इन्तेजारूल हक

एक नज़र

मदरसा में स्वागत

सीतामढ़ी के मदरसा रहमानिया मेहसौल में पिछले दिनों किशनगंज के सांसद मौलाना इसरारूल हक का स्वागत किया गया. मौके पर सांसद ने अल्पसंख्यकों से बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने की अपील की. कार्यक्रम में मदरसा के अध्यक्ष मो अरमान अली, सचिव मो जफर अल्वी, प्राचार्य मौलाना अब्दूल बदूद, मो हासिम, हबीब राईन, मो राजा समेत अन्य थे.

–विकास

बिहार बंद का ऐलान

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जनता से धोखा किए जाने के खिलाफ वाम दलों द्वारा संयुक्त आंदोलन की घोषणा की गयी है. सीपीआईएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने पिछले दिनों सीतामढ़ी में उक्त बातें कही. भाकपा के जिला सचिव जय प्रकाश राय, राम बाबू सिंह व केदार शर्मा समेत अन्य की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि आगामी 23 से 30 जून तक राज्य के प्रखंड मुख्यालयों पर वाम दलों का संयुक्त प्रदर्शन व घेराव होगा. 21 जुलाई को बिहार बंद करने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि 1998 में सीतामढ़ी में बाढ़ राहत के सवाल पर आंदोलन के नेताओं को दोषी ठहराया गया है, जबकि निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने व हत्या करने वाले प्रशासन को क्लीन चिट दिया गया है. उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार न्याय का संहार जारी है.

–ब्रिजेश

सर्वदलीय बैठक का आयोजन

सीतामढ़ी परिसदन में 1998 गोली कांड मामले में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को सजा होने के बाद स्थानीय परिसदन में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया. डॉ. रामचंद्र पूर्वे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से मामले को पटना उच्च न्यायालय में पहुंचा कर न्याय की गुहार लगाने का निर्णय लिया गया. बैठक में सांसद राम कुमार शर्मा, पूर्व सांसद सीताराम यादव, विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर, वैद्यनाथ प्रसाद, पूर्व विधायक जयनंदन प्रसाद यादव, विधायक डॉ. रंजूगीता, मोतिलाल प्रसाद, सुनील कुमार पिंटू, दिनकर राम, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला, जदयू नेता राणा रंधीर सिंह चौहान, राजेश चौधरी, दिनेश प्रसाद यादव, राजद जिलाध्यक्ष मो शफीक खां, गणेश गुप्ता समेत अन्य थे.

– विकास

चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का चुनाव संपन्न

संथाल परगना चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, देवघर का चुनाव संपन्न हो गया. सर्वसम्मति से विनोद कुमार सुलतानिया को अध्यक्ष, महासचिव आलोक कुमार मलिक एवं कोषाध्यक्ष राजन झा चुने गए. 13 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति में तीन उपाध्यक्षों में प्रमोद कुमार छावछरिया, धनंजय सिंघानिया एवं पंकज कुमार का चयन किया गया तथा संयुक्त सचिव पर पीयूष जायसवाल को रखा गया. इसके अलावा कार्यकारिणी समिति में अशोक कुमार अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, अरुण साह, अशोक मोदी, देवेन्द्र कुमार, पवन कुमार टमकोरिया, संजीव झा, उमेश राजपाल को रखा गया है. साथ ही बजरंग बथवाल, अलख निरंजन शर्मा, गोपाल कृष्णा शर्मा एवं विभूति ठाकुर को कॉरपोरेट सदस्य मनोनीत किया गया है.

– रणजीत झा

आशा कार्यकर्ताओं का हंगामा

पूर्वी चम्पारण जिले के बंजरिया प्रखण्ड के चुरिहरवा टोला में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर व्याप्त कुव्यवस्था व भ्रष्टाचार के खिलाफ आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की. उनका आरोप था कि उनसे खुलेआम रिश्वत ली जाती है और नहीं देने पर उन्हें तरह–तरह से परेशान किया जाता है. चेक देने के लिए भी सौ रुपये की मांग की जाती है. गृह भ्रमण कार्य में हो रही चुनौतियों से भी अवगत कराते हुए प्रत्येक से पचास रुपये का रिश्वत मांगने का आरोप लगाया. मौके पर मधुबाला देवी, राजकुमारी देवी, ध्यन्ती देवी, निर्मला कुमारी, रेणु श्रीवास्तव, आशा रानी, पूर्णिमा देवी, मीना देवी, मीना कुमारी, सीमा पाठक, शारदा देवी समेत बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता उपस्थित थीं. बाद में बंजरिया बीडीओ की सार्थक पहल के बाद मामला शांत हुआ.

स्पेन की कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा

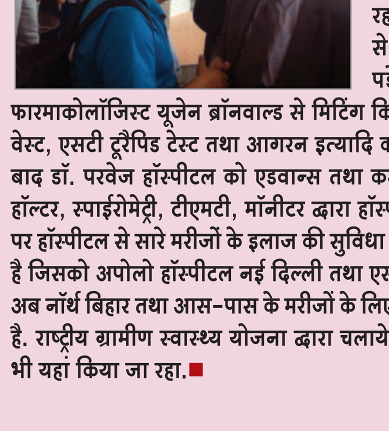

डॉ. परवेज हॉस्पीटल के चेयरमैन व वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. परवेज स्पेन में आयोजित द्वितीय विश्व कांग्रेस ऑफ एक्यूट हार्ट फेलियोर कॉन्फ्रेंन्स 2015 से लौटकर आ गए. उन्होंने बताया कि लोगों को अपने हार्ट के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है. अपने दैनिक खान पान से वसा युक्त खाने तथा मांस को कम करना पड़ेगा. कॉन्फ्रेन्स के दौरान विश्व प्रसिद्ध फारमाकोलॉजिस्ट यूजेन ब्रॉनवाल्ड से मिटिंग किया. एक्यूट हॉर्ट के फेलियर से बचाव में लाइफ वेस्ट, एसटी टूरैपिड टेस्ट तथा आगरन इत्यादि का अहम भूमिका है. इस कॉन्फ्रेन्स से लौटने के बाद डॉ. परवेज हास्पीटल को एडवान्स तथा कम्मयूटराईज्ड मशीन जैसे हाईपर वाच, ईसीजी हॉल्टर, स्पाईरोमेट्री, टीएमटी, मॉनीटर द्वारा हॉस्पीटल को अपग्रेड किया गया है. अब सस्ते दर पर हॉस्पीटल से सारे मरीजों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है. नॉर्थ बिहार का यह पहला हॉस्पीटल है जिसको अपोलो हॉस्पीटल नई दिल्ली तथा एस्कार्ट हॉस्पीटल नई दिल्ली से संबंद्धता प्राप्त है. अब नॉर्थ बिहार तथा आस–पास के मरीजों के लिए सभी प्रकार के इलाज की सुविधा यहां उपलब्ध है. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना द्वारा चलाये जा रहे बीपीएल स्मार्ट कार्डधारियों का इलाज भी यहां किया जा रहा.■

– इन्तेजारुल हक

रामनगर विधानसभा क्षेत्र

दिलचस्प मुकाबले के आसार

आसन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से पूर्णमासी राम की दावेदारी के बाद यह सीट भाजपा के लिये काटों का ताज साबित हो सकती है. बकौल पूर्णमासी राम रामनगर विधानसभा क्षेत्र का काफी हिस्सा दोन क्षेत्र है. जिसके विकास के लिये स्थानीय विधायक ने आज तक कुछ भी नहीं किया है. जिसको लेकर दोन क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है. इसका खामियाजा उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा. यहां की जनता को एक अदद सड़क तक मयस्सर नहीं है. जिसके सहारे वह प्रखंड समेत जिला मुख्यालय तक जा सके. आज तक इस क्षेत्र में संचार का कोई साधन नहीं है. स्वास्थ्य सुविधाएं तक मयस्सर नहीं है. उन्होंने बताया कि संचार सुविधा के लिये उन्होंने बीएसएनएल के जिला प्रबंधक से बात की है ताकि वायरलेस नेटवर्क से इस क्षेत्र को जोड़ा जा सके.

राकेश कुमार / संजय सिंह

बिहार विधानसभा का 02 रामनगर विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित है. इस सीट पर अभी भाजपा की भागीरथी देवी विधायक हैं. इसे भाजपा अपनी परंपरागत सीट मानती है तथा इसे जिले में अपनी पार्टी के लिये सर्वाधिक सुरक्षित सीट भी मानती है. कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस विधान सभा क्षेत्र पर अब भाजपा का कब्जा है. यहां से पिछले विधान सभा चुनाव में भाजपा की भागीरथी देवी ने कांग्रेस के नरेश राम को हरा कर जीत हासिल की थी. विगत विधान सभा चुनाव में भाजपा की भागीरथी देवी ने कांग्रेस के नरेश राम को 29782 मतों से पराजित किया था. यहां के कुल मत 255038 में से भाजपा प्रत्याशी को 51993 वोट तथा कांग्रेस प्रत्याशी 22211 वोट मिले थे. कभी कांग्रेसी नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री स्व. केदार पांडेय का गृह क्षेत्र रहा यह विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता था. लेकिन राजनैतिक रूप से काफी सजग इस क्षेत्र में कांग्रेस विगत कई चुनाव से पिछड़ती नजर आ रही है. बावजूद इसके यहां आज भी कांग्रेस का संगठन नजर आता है.

भौगोलक रूप से उत्तर की तरफ शिवालिक की पहाड़ियों से घिरे तथा गंडक नदी से निकली नहरों से सींचित होने के कारण यह क्षेत्र काफी उपजाऊ है. गन्ना, धान, सरसो, मसूर यहां की प्रमुख फसल हैं. इस क्षेत्र में एक चीनी मिल अव-स्थित है. जिसकी स्थिति काफी अच्छी होने के कारण यहां के किसान काफी मात्रा में गन्ना की खेती करते हैं तथा काफी संपन्न हैं. यहां के दोन क्षेत्र में धान की परंपरागत किस्मों की काफी खेती होती है. दोन क्षेत्र जो चारों तरफ से वाल्मीकि टाईगर रिजर्व के जंगलों से घिरा है. जिसे धान का मायका या धान का कटोरा के रूप में ख्याति प्राप्त है. बावजूद इसके परंपरागत धान को बचाने व उसके बेहतर विकास के लिये कोई सरकारी प्रयास आज तक नहीं किया गया है. इस विधान सभा क्षेत्र में काफी बड़ी आबादी थारू समुदाय की है, जो जंगलों के बीच दोन क्षेत्र के गांवों में निवास करती है. अपनी न्यूनतम जरूरत के लिये जंगल पर निर्भर रहने वाले इस समुदाय के लोगों की परेशानी वाल्मीकी टाइगर रिजर्व के गठन के बाद काफी बढ़ गई है. जंगल पर आश्रित रहने वाली थारू जन-जाति आज जल-जंगल-जमीन की लड़ाई लड़ रही है. इस चुनाव में इनके वोट पर भी राजनैतिक दलों की पैनी निगाह रहेगी. एनड़ीए की सरकार के समय उन्हें एससी/ एसटी का दर्जा मिला जिसके बाद से इन्हें भाजपा समर्थक माना जाता है. लेकिन आजादी के बाद से आज तक यह बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेल रहे हैं. आज भी इन गांवों का प्रखंड मुख्यालय से सीधा सड़क संपर्क नहीं हो पाया है. बिजली, शुद्ध पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा आदि इन्हें आज भी मयस्सर नहीं है.

रामनगर विधान सभा से कमोबेश भाजपा की स्थिति काफी साफ है. लगता है विगत दो बार की तरह ही भाजपा अपने वर्तमान विधायक भागीरथी देवी पर भरोसा करते हुए इस बार भी उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारेगी. कांग्रेस की तरफ से विगत विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे नरेश राम भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं. वह पूरे क्षेत्र लोगों के साथ हर सुख दुख में साथ रहने की बात करते हैं. उन्हें इस बात का भरोसा है की पार्टी इस बार भी उन्हें ही टिकट देगी तथा वह इस सीट से विजयी होंगे. कांग्रेस के ही पूर्णमासी राम इस बार इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. राजद सरकार में मंत्री रहे श्री राम दो बार बगहा से विधायक तथा एक बार गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से जदयू के सांसद भी रह चुके हैं. विधायक भागीरथी देवी की मानें तो इस विधान सभा क्षेत्र में काफी विकास कार्य हुआ है. नगर पंचायत के मुख्य मार्ग के भुवनेश्वर चौक से सनखर चेक पोस्ट तक पांच करोड़ की लागत से पीसीसी, नप क्षेत्र में तीन करोड़ की लागत से चचरी पुल, विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत करीब पचास करोड़ की लागत से पुल-पुलिया, पुस्तकालय, नाला अदि का निर्माण कराया गया. दोन क्षेत्र के समग्र विकास के संबंध में विधायक ने बताया कि इस क्षेत्र में संचार सुविधा के लिये जल्दी ही बीएसएनएल मोबाइल टावर लगायेगा. इस पर सहमति बन गयी है. जिसके बाद दोन क्षेत्र की इस बड़ी समस्या का अंत हो सकेगा. थरूहट विकास अभिकरण के द्वारा भी दोन के विकास के लिये रोड मैप बना लिया गया है. जिसको जल्दी ही अमलीजामा पहनाया जायेगा.

आसन्न विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से पूर्णमासी राम की दावेदारी के बाद यह सीट भाजपा के लिये काटों का ताज साबित हो सकती है. बकौल श्री राम रानगर विधान सभा क्षेत्र का काफी हिस्सा दोन क्षेत्र है. जिसके विकास के लिये स्थानीय विधायक ने आज तक कुछ भी नहीं किया है. जिसको लेकर दोन क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है. जिसका खामियाज उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा. यहां की जनता को एक अदद सड़क तक मयस्सर नहीं है. जिसके सहारे वह प्रखंड समेत जिला मुख्यालय तक जा सके. आज तक इस क्षेत्र में संचार का कोई साधन नहीं है. स्वास्थ्य सुविधाएं तक मयस्सर नहीं है. उन्होंने बताया कि संचार सुविधा के लिये उन्होंने बीएसएनएल के जिला प्रबंधक से बात की है ताकि वायरलेस नेटवर्क से इस क्षेत्र को जोड़ा जा सके. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोकसभा चुनाव 2014 के समय के आंकड़े

कुल मतदाता - 255038
महिला मतदाता - 120150
पुरुष मतदाता - 134882
कुल मतदान केंद्रों की संख्या- 258

रामनगर विधान सभा से कमोबेश भाजपा की स्थिति काफी साफ है. लगता है विगत दो बार की तरह ही भाजपा अपने वर्तमान विधायक भागीरथी देवी पर भरोसा करते हुए इस बार भी उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारेगी. कांग्रेस की तरफ से विगत विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे नरेश राम भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं. वह पूरे क्षेत्र लोगों के साथ हर सुख दुख में साथ रहने की बात करते हैं. उन्हें इस बात का भरोसा है की पार्टी इस बार भी उन्हें ही टिकट देगी तथा वह इस सीट से विजयी होंगे. कांग्रेस के ही पूर्णमासी राम इस बार इस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. राजद सरकार में मंत्री रहे श्री राम दो बार बगहा से विधायक तथा एक बार गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से जदयू के सांसद भी रह चुके हैं.

पूर्वी चंपारण निकाय चुनाव

मनी और मैनेजमेंट वाले ही बनेंगे सिकंदर

साहेबगंज के जदयू विधायक राजू सिंह जदयू के बागी हैं. वे भी अपनी पत्नी विधान पार्षद रेणु सिंह के लिए प्लेटफार्म की तलाश में थे. वे भी भाजपा खेमे में सेंध मारने में लगे हुए हैं.जानकारों के अनुसार उन्होंने भी भाजपा के बड़े नेताओं से सम्पर्क साध रखा है. इधर पूर्व में क्षेत्र से विधान पार्षद रहीं कलावती देवी राजद गठबंधन से स्वयं को उम्मीदवार मान रहीं हैं. मनी और मैनेजमेंट के इस चुनाव में धन बल मुख्य फैक्टर है. प्रत्याशियों द्वारा मनीबैग खोल दिया गया है. एक हाथ से पैसा देकर दूसरे हाथ से मतदाता जनप्रतिनिधियों से सर्टिफिकेट लेकर अपना मत सुरक्षित करने का सिलसिला जारी है.जानकारों के अनूसार चुनाव की समाप्ति तक तीन से साढ़े तीन करोड़ रुपये का खर्च होने की संभावना है.

राकेश कुमार

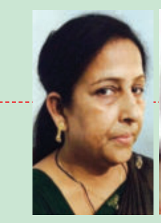

पूर्वी चंपारण के निकाय चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों के साथ ही मतदाताओं के बीच भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है.जल्द ही नामों का ऐलान होने वाला है. निवर्तमान विधान पार्षद रेणु सिंह और भाजपा के नेता राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता भाजपा के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं. रेणु सिंह जदयू के बागी विधायक राजू सिंह की पत्नी हैं. वहीं राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता हाल ही में राजद को छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं. इधर जदयू राजद गठबंधन से पूर्व विधान पार्षद कलावती देवी दावेदार हैं. जबकि दिल्ली में रहने वाले ढाका निवासी खालिद अनवर भी राजद के प्रबल दावेदार हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा नेता अतीक अहमद भी दावेदारी को लेकर ताल ठोंक रहे हैं. अभी तक मुख्य रूप से चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं. हालाकि कई अन्य लोगों ने भी चुनाव लड़ने का मन बनाया था, परन्तु इस खर्चीले चुनाव में खड़ा होना सब के बस की बात नहीं. पूर्वी चम्पारण निकाय चुनाव क्षेत्र बहुत विस्तृत है. पूर्वी चम्पारण एवं शिवहर लोक सभा क्षेत्र के बारह विधान सभा क्षेत्र के 27 प्रखण्डों के इस चुनाव क्षेत्र में 6013 मतदाता हैं. मत से ज्यादा मैनेजमेंट के आधार पर पर लड़े जाने वाले निकाय चुनाव की तैयारी तो भावी प्रत्याशियों ने महीनों पहले ही शुरू कर दी थी. जनमत की जगह जाति, काम के जगह कैश के बल पर चुनाव की तैयारी चल रही है. चुनावी बाजार में खुल कर बोली लगायी जा रही है. पांच हजार से पचास हजार तक के खरीददार हैं जो कद के अनुरूप मतदाता जनप्रतिनिधियों की बोली लगा रहे हैं. समूह में मतदाताओं को पक्ष में लाने वालों को मैनेजमेंट के नियम के अनुसार सेंटर आफ इन्फ्लूएन्स मान कर बड़ा मेहनताना दिया जा रहा है. मत के ठेकेदारों की बल्ले-बल्ले है. ऐसे तिकड़मबाज सुबह एक खेमे में तो शाम को दूसरे खेमे में नजर आ रहे हैं.

पूर्वी चम्पारण विधान सभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि यह सीट केन्द्रीय कृषि मंत्री सह स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह के संसदीय क्षेत्र में है. जबकि तीन विधान सभा क्षेत्र शिवहर लोक सभा क्षेत्र का है. शिवहर की सांसद भाजपा की रमा देवी हैं. कुल मिला कर पूर्वी चम्पारण की यह सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय माना जा रही है. ऐसे इस सीट पर काबिज होने के लिए भाजपा एक रणनीति के तहत काम कर रही है. विधान सभा चुनाव भी सिर पर है. पूर्वी चम्पारण के मोतिहारी विधान सभा सीट पर भी भाजपा का कब्जा है. ऐसे में भाजपा ने दोनों सीटों पर विजय पताका फहराने के लिए जबरदस्त योजना बनाई है. राजनीतिक धुरंधरों की मानें तो इसी रणनीति के तहत राजद नेता और 2010 के विधान सभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी बनाने की शर्त पर भाजपा में लाया गया. श्री गुप्ता वैश्य जाति से आते हैं और आम लोगों में इनकी अच्छी साख है.श्री गुप्ता को भाजपा में लाने के पीछे आगामी विधान सभा सीट को सुरक्षित करना भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है. मोतिहारी विस सीट राजद की मानी जाती है. इस विस चुनाव में राजद नेता व पूर्वी चम्पारण लोस चुनाव में प्रत्याशी रहे विनोद श्रीवास्तव अपनी पत्नी को चुनाव में उतारने का संकेत दे चुके हैं. उनके चुनाव मैदान में उतरने से भाजपा के परंपरागत कायस्थ वोट के कटने की प्रबल संभावना है. विगत लोस चुनाव में कायस्थों ने मोदी के नाम पर केन्द्र की सरकार के लिए भाजपा को वोट दिया था, लेकिन इस बार कायस्थ वोट कास्ट के आधार पर वोट करेंगे. दूसरी ओर बबलू गुप्ता अगर राजद के टिकट पर चुनाव मैदान में खड़े हो जाते तो वैश्य मत भी बिखर जाता.यहां वैश्य मत भाजपा का परंपरागत वोट रहा है.वैश्य मत के बिखराव और कायस्थ मतों के कटने से भाजपा के लिए यह सीट निकालना कठीन हो सकता था. इसी चुनावी रणनीति के मद्देनजर विस चुनाव के राजद के प्रमुख भावी उम्मीदवार बबलु गुप्ता को भाजपा में शामिल किया गया, जिससे वैश्य मतों के बिखराव को रोका जा सके.इधर बबलु गुप्ता भी बडे नेता के आदेश को ठुकरा नहीं सके.

दूसरी ओर साहेबगंज के जदयू विधायक राजू सिंह जदयू के बागी हैं. वे भी अपनी पत्नी विधान पार्षद रेणु सिंह के लिए प्लेटफार्म की तलाश में थे. वे भी भाजपा खेमे में सेंध मारने में लगे हुए हैं.जानकारों के अनुसार उन्होंने भी भाजपा के बड़े नेताओं से सम्पर्क साध रखा है. इधर पूर्व में क्षेत्र से विधान पार्षद रहीं कलावती देवी राजद गठबंधन से स्वयं को उम्मीदवार मान रहीं हैं. मनी और मैनेजमेंट के इस चुनाव में धन बल मुख्य फैक्टर है. प्रत्याशियों द्वारा मनीबैग खोल दिया गया है. एक हाथ से पैसा देकर दूसरे हाथ से मतदाता जनप्रतिनिधियों से सर्टिफिकेट लेकर अपना मत सुरक्षित करने का सिलसिला जारी है.जानकारों के अनूसार चुनाव की समाप्ति तक तीन से साढ़े तीन करोड़ रूपये का खर्च होने की संभावना है. ■

feedback@chauthiduniya.com

Mob. : 9386745004, 9204791696
www.iiher.org,
Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH

Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

Name of Courses		Eligibility	Duration
POST GRADUATE COURSES :			
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate in Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/-. only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डा. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
22 जून –28 जून 2015
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

तालाबों-पोखरों के कंक्रीट कब्र पर सियासत का मंच सजा है

भूमाफिया का समाजवाद!

तालाबों, पोखरों व झीलों को पाटकर बसाई गईं बस्तियां

(सरकारी आंकड़ा)

तहसील	कुल संख्या	अवैध कब्जे	हटाए कब्जे	अवशेष
सदर	5965	2463	532	1874
बीकेटी	1696	626	570	56
मोहनलालगंज	3317	607	583	24
मलिहाबाद	1705	97	17	80

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरशाही के आला नुमाइंदे हर बार तालाब खोदने, तालाब ढूंढ़ने या तालाब से कब्जा हटाने की कोशिश करने का उपक्रम करते दिखते हैं. यह प्रहसन हर सरकार खेलती है और तालाबों पर भूमाफियाओं से कब्जे कराती रहती है. इस सरकार के भी मुख्य सचिव समेत कई आला नौकरशाहों को आपने पिछले दिनों फावड़ा लिए हुए तालाब खोदते देखा होगा. इस नौटंकी की असली कथा यह है कि प्रदेश और राजधानी लखनऊ के तकरीबन सारे तालाब भूमाफियाओं के कब्जे में चले गए. तालाबों-पोखरों को पाटकर उन्हें प्लॉट बना कर बेच डाला गया या तालाबों पर बड़े-बड़े अपार्टमेंट खड़े करने की बाकायदा इजाजत दे दी गई. राजधानी लखनऊ में अंसल जैसी तमाम बिल्डर-वेशी भूमाफिया कंपनियों की सरकार से इतनी मिलीभगत है कि सिटी बनाने के नाम पर दर्जनों तालाब आलीशान कॉलोनियों के गर्भ में चले गए. सरकार की जानकारी और सहमति से यह हुआ्. उसी सरकार के नौकरशाह फावड़ा कुदाल लिए तालाब खोदने का नाटक करते पिछले दिनों नजर आ रहे थे. इन अफसरों में मुख्य सचिव आलोक रंजन के साथ-साथ लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर भी शरीक थे.

विडंबना यह है कि ये नौकरशाह बख्शी का तालाब क्षेत्र में तालाब खोदने के लिए फावड़े चला रहे थे, जिस इलाके का नाम ही तालाब पर रखा गया था, लेकिन आज वहां से तालाब नदारद हैं और अब उसे फिर से मनरेगा योजना के तहत खोदने की कवायद हो रही है. बख्शी का तालाब इलाके में तालाबों की खुदाई मनरेगा के तहत होनी है. राज्य सरकार ने उन तालाबों का चयन किया है, जिनकी खुदाई सबसे पहले होगी. इसी कड़ी में एक तालाब की खुदाई के काम में मुख्य सचिव आलोक रंजन समेत कई अफसर जुटे. धूप तेज थी, लेकिन अफसरों ने फावड़ा थामा और मिट्टी काटने का दृश्य कैमरों में कैद कराया. जितने अफसरों ने फावड़ा थामा था, वे सभी सीएम अखिलेश यादव के खास माने जाते हैं. ये सभी अफसर बड़े-बड़े बिल्डरों की शक्ल वाले भूमाफियाओं से उपकृत और उनके आगे नत-मस्तक हैं. जिन्होंने राजधानी लखनऊ और इर्द-गिर्द के इलाकों के सारे तालाब-पोखरों को ईंट-गारों से ढांप दिया है.

योजना है कि पूरे लखनऊ जिले में करीब 500 तालाब खोदे जाने हैं. लेकिन नौकरशाहों से कोई यह पूछने वाला नहीं कि जो तालाब पहले मौजूद थे, वे कहां चले गए? तथ्य यह है कि लखनऊ में पहले तमाम तालाब हुआ करते थे, लेकिन रियल-इस्टेट के अंधाधुंध विस्तार और कंस्ट्रक्शन की वजह से तालाब गुम हो गए. तालाबों को पाटकर जमीन माफियाओं ने कॉलोनियां बना दीं. बख्शी का तालाब इलाके में भी 96 तालाब हुआ करते थे. इनमें से ज्यादातर खत्म हो चुके हैं.

राजधानी लखनऊ की वीभत्स स्थिति की कल्पना आप इस बात से ही कर सकते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक राजधानी में कुल 12653 पोखर, तालाब, झील, वाटर रिजरवॉयर और कुएं मौजूद थे. जिसमें से करीब चार हजार तालाबों पर अब अवैध कब्जे हैं. भू-माफियाओं और बिल्डरों ने इन्हें पाट दिया है. अब यहां बहुमंजिला भवन और मकान खड़े हैं. तालाबों, पोखरों और झीलों को पाटकर बसाए गए इन कंक्रीट के भवनों में रहने वाले लोगों को पता नहीं है कि वे डैंजर-जोन में बसे हैं. भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर लखनऊ में नेपाल जैसी त्रासदी हुई तो तालाबों, झीलों और पोखरों की जमीनों पर बनाई गई इमारतें सबसे पहले ढहेंगी. यानी, राजधानी लखनऊ की चारों तहसीलों में जिन हजारों तालाबों, पोखरों और झीलों को पाटकर बिल्डरों और भू-माफियाओं ने जो मकान, अपार्टमेंट बनाए हैं उसमें रहने वाले लाखों लोगों की जिन्दगी संकट में ही रहेगी. केवल भूमाफियाओं और बिल्डरों ने ही नहीं बल्कि एलडीए और आवास विकास जैसे सरकारी महकमों ने भी कई तालाबों और झीलों को पाटकर आवासीय कॉलोनियां बसा दी हैं. कई सरकारी विभागों की बिल्डिंगें भी तालाबों पर बनाई गई हैं.

तकरीबन चार हजार तालाबों पर कब्जे का आंकड़ा सरकारी है. लिहाजा, इस आंकड़े की सत्यता की कोई गारंटी नहीं. तालाबों पर कब्जे की जमीनी हकीकत इन सरकारी आंकड़ों से बिल्कुल अलग और भयावह है. अब तो कहीं एक-दो तालाब दिख भी जाएं तो गनीमत है. अगर चार हजार तालाबों पर कब्जे को भी सामने रखें तो तकरीबन सात सौ हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अवैध कब्जा हो चुका है. लखनऊ के निवासी बताते हैं कि पहले तालाबों, पोखरों और झीलों के होने से भू जल स्तर सही रहता था, जो आज विलुप्त ही होने पर है.

लखनऊ के शहरी इलाकों में किस तरह तालाबों, झीलों और कुओं पर कब्जा हुआ, यह दृश्य देखेंगे तो कांप जाएंगे. अलीगंज के चांदगंज, अलीनगर के सुनहरा में करीब 25 बीघा क्षेत्रफल का तालाब पाट दिया गया. तेलीबाग के तालाब भूमाफियाओं और आवास विकास ने बांट लिए. एलडीए ने गोमती नगर में तालाबों की भूमि बिल्डरों को दे दी. आशियाना के ग्राम किला मोहम्मदी में तालाब पर एलडीए ने प्लॉटिंग कर दी. आशियाना में खजाना मार्केट के सामने तालाब पर अवैध निर्माण हो गए. हैवतमऊ मवैया में दो तालाब कब्जा कर पाट दिए गए. इसी तरह उतरेठिया, चांदन, जानकीपुरम, मड़ियांव, चिनहट और पारा में अनगिनत तालाब पाट दिए गए. यही स्थिति लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की भी की गई. मलिहाबाद के खंडसरा गांव के तालाब का नामोनिशान मिट चुका है. तालाब सहित उसके पास स्थित चारागाह पर भी भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है. मोहनलालगंज के कोरियानी गांव में भी भू-माफियाओं ने तालाब पर कब्जा कर लिया है, चारागाह भी नहीं छोड़ा. जानवरों के चारागाह भी बेच दिए गए और आसपास के तालाबों पर कब्जा जमा लिया गया. शहरी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों, पोखरों और झीलों को पाटकर आवासीय कॉलोनियों से लेकर अस्पताल, स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बना दिए गए और यह क्रम लगातार जारी है. शहरी क्षेत्र के अलावा शहरी सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों और झीलों को पाटकर एलडीए, आवास विकास और कुछ भू-माफियाओं ने आवासीय कॉलोनियां विकसित कर दी हैं. पीजीआई का भी एक हिस्सा तालाब को ही पाटकर बनाया गया है.

आजादी के बाद 68 साल की अवधि में उत्तर प्रदेश में 68 हजार से ज्यादा तालाबों, पोखरों, झीलों और कुओं का अस्तित्व खत्म कर दिया गया. प्रदेश में कथित विकास का यह कड़वा सच है. सरकार और तंत्र को अपनी जेब में रखने वाले बिल्डर और भूमाफिया अंधाधुंध शहरीकरण कर रहे हैं. जल का प्राकृतिक स्त्रोत तेजी से विलुप्त होता जा रहा है. बिल्डर और भू-माफिया उन्हें पाटकर उनकी कब्र पर आलीशान इमारतें खड़ी कर रहे हैं. 1947 में प्रदेश के राजस्व दस्तावेजों में तालाबों, पोखरों, झीलों और कुओं के रूप में जल के 8 लाख 91 हजार 214 प्राकृतिक स्त्रोतों का विवरण दर्ज था. कुछ दस्तावेज ऐसे जलीय स्त्रोतों की संख्या नौ लाख पंद्रह हजार पांच सौ पच्चीस बताते हैं. तथाकथित विकास के नाम पर हुई धोखेबाजी ने इनके अस्तित्व को गंभीर संकट में डाल दिया. राजस्व परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2015 में सरकारी अभिलेखों में दर्ज जल स्त्रोतों की संख्या घटकर 8 लाख 22 हजार 899 रह गई है. इन 68 साल में सूबे में 68,315 जल स्त्रोत कम हुए हैं. इन आंकड़ों को औसत के नियम से देखें तो हर साल प्रदेश में करीब एक हजार जल स्त्रोतों का निशान मिटता जा रहा है. तालाबों, पोखरों, झीलों और कुओं का अस्तित्व मिटा तो पानी के भंडारों का दायरा भी सिकुड़ गया. जल के प्राकृतिक स्त्रोतों पर भू-माफिया की गिद्ध दृष्टि का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि आधिकारिक तौर 1 लाख 10 हजार 950 तालाबों, पोखरों, झीलों व कुओं पर अवैध कब्जे पाए गए हैं. अवैध कब्जे से मुक्ति के सरकारी दावे भी किए जाते हैं और आंकड़े भी परोसे जाते हैं, लेकिन जमीनी सर्वेक्षण में वे सब फर्जी पाए जाते हैं. सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि पानी के 43,922 भंडार भूमाफियाओं के अवैध कब्जे में हैं. लेकिन असलियत यह है कि एक लाख ग्यारह हजार नौ सौ अड़सठ तालाबों पर कब्जा कर लिया गया है.

प्रदेश के अन्य जिलों में भी तालाबों के अतिक्रमण का सिलसिला भयावह है. वाराणसी मंडल के जौनपुर में सरकारी दावे के मुताबिक मात्र 631 पर कब्जा है, जबकि वहां हजार से अधिक तालाबों पर कब्जा हो चुका है. ऐसी ही स्थिति अन्य जिलों की भी है. जल स्रोतों में कब्जे के मामले में इलाहाबाद मंडल सबसे आगे है, जबकि आगरा में सबसे कम 59 जल स्रोतों पर कब्जा है. सीतापुर में कुल 17,880 तालाबों समेत अन्य जल स्रोतों में 133 पर अवैध कब्जा है. हरदोई में भी 967 जल स्रोतों पर कब्जा है. इसके साथ सोनभद्र, रामपुर, चंदौली, कासगंज, बलिया, इटावा, महोबा, जालौन, ललितपुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, अमरोहा व मुरादाबाद प्रत्येक जिलों में तालाब, पोखर, झील या कुओं पर कब्जे के उदाहरण है. लेकिन सरकारी तंत्र एक तरफ इन कब्जों से इन्कार भी करता है और दूसरी तरफ यह भी कहता है कि कई तालाबों को कब्जे से मुक्त करा लिया गया है. मुक्त कराने के बाद तालाबों को उसके मौलिक शक्ल में लाया गया कि नहीं, इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. जमीनी हकीकत यही है कि अधिकांश तालाबों पर भूमाफियाओं और दबंगों का कब्जा बरकरार है.

कब्जे की हालत यह है कि इलाहाबाद में 137601 तालाब, जमगढ़ में 105351 तालाब, सहारनपुर में 68581 तालाब, फैजाबाद में 52791 तालाब, लखनऊ में 26581 तालाब, मेरठ में 18531 तालाब, देवीपाटन में 11311 तालाब, चित्रकूट में 4591 तालाब, बरेली में 4561 तालाब, मुरादाबाद में 4051 तालाब, गोरखपुर में 3971 तालाब, बस्ती में 3831 तालाब, कानपुर में 3771 तालाब, विंध्याचल में 3281 लाब, अलीगढ़ में 2011 तालाब, वाराणसी में 1611 तालाब और आगरा में 59 तालाब अवैध कब्जे में हैं और उनका नामोनिशान मिट चुका है. ■

feedback@chauthiduniya.com

हाईकोर्ट का आदेश टांय-टांय फिस्स

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तालाबों, पोखरों, चारागाहों, शमशान और कब्रिस्तान से अवैध कब्जे हटाने का स्पष्ट आदेश दे रखा है. ओमप्रकाश वर्मा की याचिका (6472-एमबी/2012) पर हाईकोर्ट ने पांच मार्च 2013 को ही यह आदेश दिया था. लेकिन कब्जे की स्थिति क्या है, यह सामने है. सरकार अदालतों को दिखाने के लिए कार्रवाई का प्रहसन खेलती है और भूमाफिया तालाबों-पोखरों की छाती पर अपनी मर्जी से बहुमंजिली इमारतें खड़ी करते रहते हैं. अभी प्रदेश की मौजूदा समाजवादी सरकार तालाब मुक्त कराने का प्रहसन खेल रही है. इसके पहले बसपा सरकार भी यह खेलती रही है. यह एक रैतिक (रिचुअल) परेड की तरह हो कर रह गया है. ■

निषाद आंदोलन हिंसा का शिकार

चौथी दुनिया ब्यूरो

राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की कामयाबी ने ऐसा असर डाला कि निषाद समुदाय के लोग भी आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए. आंदोलन शुरुआत में ही इतना हिंसक हो गया कि खूब पथराव और आगजनी हुई. लाठी चार्ज भी हुआ और फायरिंग भी हुई. पुलिस फायरिंग में एक आदमी मारा गया, जबकि हिंसा में दर्जनों लोग जख्मी हुए. प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक कर रेल यातायात को बुरी तरह बाधित किया, रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचाया, हाई-वे जाम किया और दो दर्जन वाहन भी फूंक डाले. घायलों में दर्जनों लोगों के अलावा डीएम, डीआईजी और एसपी समेत 12 पुलिसवालों के भी नाम गिनाए गए हैं. आंदोलन के नेता संजय निषाद घटना के बाद से लापता हैं. कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने निषाद समेत 20 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. गोरखपुर के जिलाधिकारी रंजन कुमार ने भी कहा कि संजय निषाद के बारे में कुछ पता नहीं है. हिंसा की आग पड़ोसी जिले संत कबीर नगर के नजदीकी इलाकों में भी फैली, जिसे काफी मशक्कत के बाद काबू में किया जा सका.

गोरखपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मगहर के पास सात जून को सुबह आठ बजे से ही राष्ट्रीय निषाद एकता मंच के बैनर के नीचे हजारों लोग जुटने लगे थे. संजय निषाद की अगुवाई में पहले कबीर मंदिर के पास निषादों की मीटिंग हुई. आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए संजय निषाद ने कहा कि सरकार ने संविधान में व्यवस्था न होने के बावजूद गूर्जरों को आरक्षण दे दिया, लेकिन एक साल से भी ज्यादा समय से शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे निषाद समुदाय की उपेक्षा की जा रही है. इसके बाद आंदोलनकारी तीन गुटों में बंट गए. पहला गुट रेलवे ट्रैक की तरफ गया, दूसरा नेशनल हाई-वे की तरफ और तीसरा व्यवस्था में लग गया. देखते-देखते रेलवे ट्रैक और गोरखपुर-लखनऊ नेशनल हाई-वे जाम कर दिया गया. मौके पर पहुंची आरपीएफ, पीएसी और पुलिस फोर्स ने रेलवे ट्रैक से आंदोलनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे तैयार नहीं हुए. दिन में करीब तीन बजे गोरखपुर के जिलाधिकारी रंजन कुमार, डीआईजी संजीव गुप्त और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन वे सब भी प्रदर्शनकारियों को हिंसक होने से नहीं रोक पाए. निषादों ने रेल की पटरियों पर कब्जा जमा लिया और करीब आठ-नौ घंटे तक रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमाए रखा. पुलिस ने हिंसक झड़प के बाद आंदोलनकारियों को वहां से हटाया, मगर आसपास के इलाकों में तनाव काफी फैल गया और भीड़ हिंसक हो उठी. कहा जा रहा है कि संत कबीर नगर में निषादों का दो दिवसीय सम्मेलन था, वहां पर कुछ स्थानीय नेताओं ने लोगों को भड़का दिया और उन्होंने उग्र होकर जाकर रेलवे ट्रैक और हाई-वे जाम करना शुरू कर दिया. आरपीएफ और स्थानीय पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वे नहीं माने. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे 15 दिन तक ट्रैक जाम रखेंगे और अपनी मांगें मनवाकर ही उठेंगे. बाद में भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग कर उन्हें रेलवे ट्रैक से खदेड़ा. इसके बाद आंदोलनकारियों के एक जत्थे ने गोरखपुर लखनऊ राजमार्ग पर जाम लगा दिया. हिंसा में इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के मड़ैया दलीपनगर गांव के रहने वाले 20 साल के युवक अखिलेश कुमार की मौत हो गई. लोगों का कहना है कि युवक की मौत पुलिस फायरिंग में हुई. इस मामले में सहजनवां थाने में 20 नामजद और 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलवा, तोड़फोड़, रेलवे ट्रैक जाम करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. डीआईजी संजीव कुमार ने कहा कि इनमें से 15 लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. कानून व्यवस्था महकमे के आईजी ए. सतीश गणेश ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए निषाद समुदाय के आंदोलन का वीडियो फुटेज मांगा गया है. डीजीपी मुख्यालय की ओर से तीन कंपनी पीएसी लगायी गई है. साथ ही दो कंपनी पीएसी रिजर्व में रखी गई है.

सात जून को दिन भर हिंसा, आगजनी और फायरिंग के बाद आठ जून को सहजनवां से लेकर मगहर तक खौफ कायम रहा. यह बात भी बाहर आ रही है कि पुलिस फोर्स से भी कुछ गलतियां हुईं. खुफिया महकमे को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं. पुलिस और प्रशासन के अफसरों की टीम मगहर के पास उस जगह पर गई जहां निषाद समुदाय और पुलिस के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था. दूसरी टीम ने इस मामले में शामिल नेताओं की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की. पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मारे गए युवक का नाम अखिलेश निषाद पुत्र आत्माराम है और वह मड़ैया दिलीप नगर थाना बकेवर जिला इटावा का निवासी था. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल खत्री ने इस मामले में सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मृतक के परिवारजनों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक नहीं, कई जातियों का लंबित है दावा

जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है. सियासत गरमा रही है. इसी में आरक्षण की राजनीति भी शामिल है. निषाद समुदाय की ओर से पांच प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण की मांग पर राज्य सरकार असमंजस में है. पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि निषाद समेत 17 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही सहमति दे दी है. इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा न मिल पाने का ठीकरा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार पर फोड़ा है. आयोग के अध्यक्ष राम आसरे विश्वकर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझ कर कोई न कोई अड़चन लगा देती है. साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष निषादों की मांग को असंवैधानिक भी बताते हैं. वे कहते हैं कि राज्य सरकार इन सभी को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए पहले ही सहमति जता चुकी है. केंद्र सरकार में मामला लटका हुआ है. लेकिन निषाद जो पांच प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण की मांग कर रहे हैं उसे सरकार अगर मान भी लेती है, तो कोर्ट उसे नहीं मानेगी, क्योंकि आरक्षण में आरक्षण दिए जाने का कोई नियम ही नहीं है. पिछड़ा वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के लिए यूपी सरकार की ओर से केंद्र सरकार को तीन बार पत्र भेजा गया है. 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की पहल अक्टूबर 2005 में शुरू हुई थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने संप्रग सरकार को पत्र लिख कर उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग की थी. मुलायम सिंह के पत्र पर तत्कालीन यूपीए सरकार महीनों खामोश रही. प्रदेश सरकार ने जब फिर से पत्र व्यवहार शुरू किया, तो केंद्र ने कई ऐसी जानकारियां मांग लीं जिसे पूरा करना काफी कठिन था. 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो केंद्र को फिर से दो बार सूची भेजी, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया. ■

भूमाफिया का समाजवाद!

पृष्ठ 17 का शेष

हाईकोर्ट भवन के लिए ही एलॉट कर दिया तालाब

तालाबों-पोखरों से अवैध कब्जा कैसे हटे जब हाईकोर्ट का भवन और परिसर ही तालाबों को अपने कंक्रीट के घेरे में ले रहा हो! तालाबों की मुक्ति का अभियान चलाने वाली प्रमुख समाजसेवी संस्था जनाधिकार के कर्ताधर्ता अशोक शंकरम का यह सवाल उत्तर प्रदेश की सारी राजनीतिक-प्रशासनिक-न्यायिक स्थितियों को सामने ला खड़ा करता है. गोमतीनगर क्षेत्र में फैजाबाद रोड के पास हाईकोर्ट का नया भवन तैयार हो रहा है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा मुहैया कराई गई जमीन पर राजकीय निर्माण निगम हाईकोर्ट का नया भवन और परिसर तैयार कर रहा है. एलडीए ने प्रशासन से मिलीभगत करके तालाब की जमीन (गाटा संख्या-52) भी हाईकोर्ट के भवन के लिए एलॉट कर दिया. अब स्थानीय विजयपुर गांव के लोग भुगतें. इस सरकारी कब्जे के खिलाफ लगातार प्रशासन को लिखा गया, लेकिन तालाब को घेर कर उसे निर्माणाधीन कोर्ट परिसर में ले लिया गया है. अब इसकी कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, यह एक अहम सवाल है. जनाधिकार तालाब मुक्त कराने की जद्दोजहद कर रहा है.

जनाधिकार ने लखनऊ समेत कई अन्य इलाकों में भी तालाबों, पोखरों, झीलों और कुओं को बिल्डरों और भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने का कानूनी अभियान छेड़ रखा है. संस्था ने लखनऊ के कुछ प्रमुख तालाबों को मुक्त कराने में सफलता हासिल की और कई तालाबों पर कब्जा जमाए बैठे बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ संघर्ष जारी है. अशोक शंकरम कहते हैं कि तालाबों पर कब्जे के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करने के साथ-साथ स्थानीय आम नागरिकों को भी उनके अधिकार के प्रति सचेत और सक्रिय करने का अभियान चल रहा है. कई स्थानों पर स्थानीय लोगों के तीव्र विरोध के कारण भूमाफियाओं को पीछे भी हटना पड़ा है. श्री शंकरम ने बताया कि भूमाफियाओं के साथ प्रशासन और नौकरशाहों की पूरी मिलीभगत रहती है और उन्हें नेताओं का संरक्षण प्राप्त रहता है. इस वजह से अदालत के आदेश पर भी जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने में काफी दिक्कतें पेश आती हैं. उन्होंने गोमती नगर के कंचनपुर मटियारी जैसे कई उदाहरण दिए, जहां तालाबों को पाट कर घर बनाने की मनाही कर दी गई, लेकिन फिर भी प्रशासनतंत्र को ठेंगा दिखा कर भवन निर्माण कार्य जारी रहा.

कर्णघंटा सरोवर-नीचीबाग से बुलानाला जाने वाले मार्ग में यह सरोवर स्थित है. अब यह विलुप्त होने की कगार पर है. गुरु पूर्णिमा को इस सरोवर पर स्थित शिवलिंग और महर्षि वेदव्यास की मूर्ति की पूजा की जाती है. पूरे वर्ष ये मूर्तियां कुंड के जल में डूबी रहती हैं. गुरु पूर्णिमा के दिन नगर निगम पंप से सरोवर का पानी खाली कर देता है. इस कुंड पर ही तुलसीदास जी ने प्रथम हनुमान मंदिर बनाया.

पीएम के संसदीय क्षेत्र के नरक कुंड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के ऐतिहासिक कुंड और तालाब आज नरक कुंड में तब्दील हो चुके हैं. अधिकतर कुंड अवैध कब्जे का शिकार हैं और स्थितियां वाकई नारकीय हैं.

लोलार्क कुंड-वर्तमान समय में स्थिति यह है कि अधिकांश कुंडों को पाटकर ऊंची-ऊंची इमारतों और आलीशान कालोनियां खड़ी कर ली गई हैं, लोलार्क कुंड भदैनी मुहल्ले में है. यहा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को एक विशाल मेला लगता है. लोलार्क छठ के नाम से प्रचलित है. कुंड की अनेक मान्यताओं में यह भी शामिल है कि इसमें स्नान करने से बांझ महिलाओं को भी संतानोत्पत्ति होती है और चर्म रोगियों को लाभ मिलता है. शां कारों के अनुसार अकबर और जहांगीर के युग में इस कुंड को वाराणसी का नेत्र माना जाता था. दोनों जगतों के मध्य प्रदक्षिणा पथ है जिसे कहा जाता है कि अहिल्याबाई, अमृतराव तथा कूच बिहार के महाराजा ने बनवाया था. इस कुंड के एक ताखे पर भगवान सूर्य का प्रतीक चक्र बना हुआ है. लोलार्क कुंड धीरे-धीरे बर्बादी के कगार पर है. यह चारों ओर से घरों से घिर गया है. लोगों के घरों का कचरा कुंड में आता है. कुंड की दशा अत्यन्त दयनीय है. उसका लगातार अतिक्रमण हो रहा है. बेनिया कुंड-आज से कई हजार वर्ष पूर्व काशी का बेणी तीर्थ था. आज बेनिया बाग के विशाल मैदान के एक छोर का कूड़ा-करकट व बड़ी-बड़ी जंगली घास से युक्त छोटी से गंदी झील में तब्दील हो चुका है. रख-रखाव के अभाव में इस झील में पानी इतना कम है कि वह किसी काम लायक नहीं है और पानी इतना गंदा व दुर्गन्धयुक्त है कि कोई भी आदमी इसमें हाथ डालना तक उचित नहीं समझता. वैशाख व ज्येष्ठ मास की गर्मी में इस झील का पानी सूखकर नाम मात्र रह जाता है. कूड़े के ढेर व घरों के मलबे आदि के कारण कुंड पटना शुरू हो गया और बाद में बेनियाबाग का मैदान हो गया. कुंड एक गन्दे पोखरे के रूप में आज भी विद्यमान है. यहां गंदगी की भरमार है. बकरिया कुंड (उत्तरार्क या बर्करी कुंड)-यह हिन्दुओं का पवित्र सूर्य तीर्थ है. यह कुंड अलईपुर क्षेत्र में स्थित बकरिया कुंड मुहल्ले में है, जिसे आज बोल-चाल की भाषा में बकरिया कुंड के नाम से जाना जाता है. इस धार्मिक व प्राचीन विरासत के रख-रखाव की घोर उपेक्षा के कारण यह कुंड अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं. इतिहासकारों का कहना है कि बर्करी कुंड के बगल में पहले बौद्ध विहार था. औरंगजेब तथा अन्य आक्रमणों से उसकी यह दुर्गति बनाई गई. इस कुंड के आस-पास अब कई आवासों का निर्माण हो गया है जिसके कारण कुंड का दायरा लगातार सिमटता चला जा रहा है.

कर्णघंटा सरोवर-नीचीबाग से बुलानाला जाने वाले मार्ग में यह सरोवर स्थित है. अब यह विलुप्त होने की कगार पर है. गुरु पूर्णिमा को इस सरोवर पर स्थित शिवलिंग और महर्षि वेदव्यास की मूर्ति की पूजा की जाती है. पूरे वर्ष ये मूर्तियां कुंड के जल में डूबी रहती हैं. गुरु पूर्णिमा के दिन नगर निगम पंप से सरोवर का पानी खाली कर देता है. इस कुंड पर ही तुलसीदास जी ने प्रथम हनुमान मंदिर बनाया. जिसे कोढ़ियाबीर हनुमान के नाम से जाना जाता है. इस सरोवर की भी स्थिति दयनीय है.

मातृ कुंड-मातृ कुंड लल्लापुरा में पितृ कुंड के पहले स्थित था. इस कुंड को क्षेत्रीय लोगों ने कूड़ा डालकर धीरे-धीरे पाट दिया. बाद में कुंड की खुदाई करने पर मातृ देवी की मूर्ति मिली, जिसे कुंड के ऊपर मंदिर बनवाकर स्थापित कर दिया गया. पहले तीर्थ यात्री यहां आकर मातृ देवी का पूजन-अर्चन करते थे फिर तर्पण करते थे. इस कुंड को बचाये रखने की जद्दोजहद तो चल रही है, लेकिन अतिक्रमण उससे तेज गति से चल रहा है. मातृ कुंड का अधिकांश हिस्सा पाट दिया गया है और वहां पर अब सिगरा थाने की माताकुंड पुलिस चौकी तथा रामलीला मैदान है. इसी तरह से पितृकुंड भी जलकुम्भी से आच्छादित है. इसके किनारे तीन तरफ से भवनों का निर्माण किया जा चुका है. कुंड को सम्पूर्ण रूप से पाटने के इरादे से मकानों से कूड़ा कचरा इसी कुंड में फेंका जा रहा है. कुंड के सामने पूर्व दिशा की ओर से अवैध गुमटियां लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है.

रामकटोरा-जगतगंज क्षेत्र में सड़क किनारे रामकटोरा कुंड स्थित है. इसकी भी हालत खस्ता है. कुंड के पास राम, लक्ष्मण, जानकी और बजरंग बली का मंदिर भी है. मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख भी लगा हुआ है. जिसके अनुसार मंदिर का निर्माण दो सौ वर्ष पहले जगतगंज के जमींदार इन्द्र नारायण सिंह ने कराया था. कहा जाता है कि हिन्दी साहित्य के कालजयी रचनाकार जयशंकर प्रसाद और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र इसी कुंड के तट पर बैठकर लेखन किया करते थे. इस कुंड में पांच भूजल स्रोत भी हैं. जिसकी वजह से यह कभी नहीं सूखता है. सही रख रखाव नहीं होने से इस कुंड की दशा खराब है. ■

feedback@chauthiduniya.com

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक में बनाया विचार

योग और सूर्य नमस्कार इस्लाम विरोधी

सूफी यायावर

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब गीता ज्ञान प्रतियोगिता में अव्वल आई मुस्लिम बच्ची मरियम सिद्दीकी को सम्मानित कर रहे थे, उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलमबरदार सूर्य नमस्कार और योग को गैर-इस्लामिक करार देने में मशगूल थे. बोर्ड ने सूर्य को नमस्कार करने और योग करने को धर्म की आजादी में बाधा माना और इसकी मुखालफत करने की तमाम रणनीति बना डाली.

केंद्र सरकार द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ रणनीति बनाई और एक पैनल का गठन करने का निर्णय लिया जो मुस्लिम समुदाय के बच्चों को बताएगा कि योग करना और सूर्य को नमस्कार करना इस्लाम के खिलाफ है. बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार और योग को अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ हम कैंपेन चलाएंगे. मौलाना वली रहमानी इस कैंपेन का नेतृत्व करेंगे.

बोर्ड के एक अन्य सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि योग दिवस असंवैधानिक है. कैसे एक सरकार किसी धार्मिक प्रतीक या परंपरा को स्कूल परिसर में मंजूरी दे सकती है. हमने इसके खिलाफ राजस्थान कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है. लोगों को इसके खिलाफ जागरूक करने के लिए बोर्ड अब सोशल मीडिया का सहारा लेने की तैयारी में है. अपना स्टैंड पोस्ट करने के लिए बोर्ड सोशल मीडिया पर लोगों को जोड़ेगा. सनद रहे, कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया के इस्तेमाल को भी गैर इस्लामिक करार दिया गया था. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस रुख और रणनीति के जवाब में अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी द्वारा संचालित स्कूल के प्रिंसिपल मुहम्मद अब्बास नियाजी ने कहा कि योग एक एक्सरसाइज है. कोई भी धर्म हेल्दी लाइफ-स्टाइल के खिलाफ नहीं है. इस एक्सरसाइज पर बेवजह राजनीति हो रही है. सूफी मान्यताओं में भी एक तरह के योग की चर्चा है. इसमें आप ध्यान लगाते हैं और ईश्वर से संपर्क साधते हैं.

बहरहाल, पर्सनल लॉ बोर्ड ने सूर्य नमस्कार और योग के साथ-साथ घर वापसी जैसे राजनीतिक मुद्दे को भी अपने अभियान में जोड़ लिया है. हिंदू संगठनों के घर वापसी अभियान के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देशव्यापी मुहिम छेड़ेगा. बोर्ड इसे धार्मिक आजादी में खलल मानता है. उसका कहना है कि जब हमें संविधान से धर्म के प्रचार-प्रसार की आजादी मिली है, तो कोई इसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकता है. बोर्ड ने सूर्य नमस्कार को गैर इस्लामिक मानते हुए इसका भी विरोध करने का ऐलान किया. ये फैसले लखनऊ में नदवातुल उलूम कॉलेज में हुई बोर्ड की बैठक में लिए गए. बैठक में फैसला किया गया कि बोर्ड में युवा सदस्य शामिल किए जाएं. अभी बोर्ड के सदस्यों की उम्र 60 साल से ज्यादा है. युवाओं के शामिल होने से बोर्ड में तकनीक का प्रयोग भी बढ़ेगा. बैठक में बोर्ड को मीडिया से नजदीक होने का भी फैसला हुआ.

नदवा कॉलेज में हुई बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में कहा गया कि मोदी सरकार सूर्य नमस्कार, गीता व योग को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश कर रही है. इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. हर स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा. बैठक में घर वापसी का अभियान चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. साथ ही इसे मुसलमानों की धार्मिक आजादी के लिए खतरा करार दिया गया. यह भी फैसला किया गया कि इस तरह के अभियानों का हर स्तर पर जवाब दिया जाए. बैठक में पिछले कुछ दिनों से न्यायालयों से शरीयत कानून के खिलाफ आ रहे फैसलों पर चिंता जताई गई. बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में बोर्ड कार्यकारिणी ने केंद्र सरकार के एक साल के कार्यकाल में मुसलमानों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के रुख पर चर्चा की. सभी ने कहा कि सरकार के कुछ कदम मुसलमानों को आशंका में डाल रहे हैं. स्कूलों के पाठ्यक्रम में सूर्य नमस्कार, गीता व योग को शामिल करने की कोशिश ठीक नहीं है. स्कूलों में सभी धर्मों के बच्चे आते हैं. इसलिए किसी एक धर्म के धार्मिक ग्रंथ को दूसरे धर्म के बच्चे पर जबरन थोपना गलत है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. पर्सनल लॉ बोर्ड इस बारे में मुस्लिम समाज को जागरूक करेगा. इसके लिए मजलिस-ए-अमल कमेटी का गठन करने का निर्णय हुआ है. कमेटी में सभी धर्म के नुमाइंदे रखे जाएंगे. बोर्ड को इस बात पर भी आपत्ति है कि विभिन्न अदालतों से शरई के खिलाफ फैसले क्यों आ रहे हैं. ऐसे फैसलों के खिलाफ पैरवी करने के लिए कमेटी गठित करने का भी बैठक में निर्णय किया गया. यह कमेटी हर फैसले की समीक्षा करके उसके खिलाफ सही जगह पर बात रखने या न्यायालय में अपील करने का काम करेगी. बोर्ड कार्यकारिणी की बैठक में उपाध्यक्ष मौलाना डॉ. कल्बे सादिक, महासचिव मौलाना निजामुद्दीन, प्रवक्ता अब्दुल रहीम कुरैशी, कार्यकारिणी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, जफरयाब जीलानी, कमाल फारूकी, शकील सामदानी सहित पूरे देश से आए बोर्ड के पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य शामिल थे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सलन लॉ बोर्ड ने मौलाना वली रहमानी को बोर्ड का कार्यवाहक महासचिव बनाने का फैसला किया. मौलाना निजामुद्दीन महासचिव बने रहेंगे, लेकिन उनकी उम्र व स्वास्थ्य की दिक्कतों को देखते हुए रहमानी को कार्यवाहक महासचिव बनाकर उनके काम में हाथ बंटाने को कहा गया है. बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर हैदराबाद से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, किछौछा से शाह फखरुद्दीन, जमाते इस्लामी से मौलाना जलालुद्दीन उमरी, प्रो. शकील समदानी, कोलकाता से नूरजहां, हैदराबाद से असमा जहरा, पटना से मौलाना निजामुद्दीन और अब्दुर्रहमान कुरैशी आए थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

अखिलेश से भी मिले बोर्ड के सदस्य

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने आठ जून को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शिया धर्मगुरु मौलाना डॉ. कल्बे सादिक कर रहे थे. प्रतिनिधिमंडल में बोर्ड के कार्यवाहक महासचिव मौलाना वली रहमानी, सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी के अलावा अपर महाधिवक्ता जफरयाब जिलानी भी शामिल थे. बोर्ड के सदस्यों ने जमींदारी एबॉलिशन एक्ट के अन्तर्गत आने वाले विरासत कानून, जिसमें शादी-शुदा लड़कियों व माता को लड़के के साथ हिस्सा नहीं दिए जाने का प्रावधान है, के सम्बन्ध में अपने विचार मुख्यमंत्री के समक्ष रखे. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि मुस्लिम शरीअत के अन्तर्गत शादी-शुदा लड़कियों तथा माता को भी विरासत में हक दिया गया है. इसलिए बोर्ड ने मांग की कि जमींदारी एबॉलिशन एक्ट में संशोधन करके शादी-शुदा लड़कियों व माता को भी हिस्सा देने की व्यवस्था की जाए. ■

कानून नहीं, अदालत से होगा अयोध्या मामले का समाधान

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अयोध्या मामले का हल कानून से नहीं, बल्कि अदालत से होगा. भाजपा नेता विनय कटियार और साक्षी महराज की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग किए जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह बात कही. पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता अब्दुल रहीम कुरैशी ने कहा कि कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है. हमने पहले ही कहा है कि मामले का समाधान कानून से नहीं बल्कि न्यायालय से होगा. मामला अब उच्चतम न्यायालय में है और वहां से जो भी फैसला आएगा, वो हमें स्वीकार्य होगा. ■

आपदा राहत घोटाला कांग्रेस के लिए घातक

राजकुमार शर्मा

केदारनाथ में आयी आपदा के बाद आपदा राहत राशि में भारी घोटाले की कालीख में सूबे की कांग्रेस सरकार स्याह हो चुकी है. यह एक सच्चाई है, जो कुछ हुआ वह कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कार्यकाल में हुआ. इसी सच को स्वीकारते हुए कांग्रेस हाई कमान ने आपदा के समय जनता की कसौटी पर बहुगुणा के खरा न उतरने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर हरीश रावत को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी. आपदा के बाद सरकार की नाकामी पर बहुगुणा के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज़ हरीश रावत ने ही उठाई थी. बहुगुणा के कार्यकाल में आपदा में लगे अफसरों ने मदद के नाम पर जो लूट-घसोट की. उस पर हरीश रावत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आंख बंद कर लिया, अब वही हरीश के गले की फांस बन गई है. हरीश को अब समझ में आ गया है कि मुख्यमंत्री चाहे जो रहा हो सरकार तो कांग्रेस की ही थी.

आपदा राहत घोटाले के सामने आने के बाद जहां लग रहा था कि इससे कांग्रेस के भीतर हरीश रावत खेमा मजबूत होगा, लेकिन इस खेमे ने सूचना आयोग पर हमला कर आंतरिक राजनीति का खेल खुद ही बिगाड़ा लिया है. मुख्यमंत्री हरीश रावत व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के बयानों को सूचनाधिकार कानून के विरोध में बताया जाने लगा है, जिस सूचनाधिकार कानून को कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते रहते हैं. उस पर कांग्रेस नेता लगातार हमला कर रहे हैं. आपदा राहत घोटाला सामने आने के बाद से कांग्रेस सरकार और संगठन दोनों ने जो रुख अपनाया है. उसे राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के सियासी भविष्य के लिए घातक और आत्मघाति मान रहे हैं. मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के राज्य सूचना आयोग पर सवाल खड़े करने को लेकर कांग्रेस के कई लोग अब प्रदेश के नेतृत्व के इस रुख से हैरान हैं. उनका मानना है कि इस संवेदनशील मामले में प्रदेश सरकार और प्रदेश संगठन को गंभीरता दिखाते हुए जांच के बाद दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. इस कारण अब जनता में यह धारणा बनने लगी है कि प्रदेश सरकार घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश में है. सूचना आयोग की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जांच मुख्य सचिव को सौंप दिया. इस मुद्दे को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावार है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सूचना आयुक्त अनिल शर्मा पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है. सवाल यह है कि आयोग इसके पहले भाजपा शासन के समय के एनआरएचएम घोटाले और अर्धकुंभ घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुका है, उस वक्त न तो कांग्रेस ने और न प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर सवाल खड़े किए. अब इसे कांग्रेस के दोहरे रवैये के रूप में देखा जा रहा है.

राज्य सूचना आयुक्तों की पेंशन रोकने के मामले में भी सरकार की किरकिरी हो रही है. इस आदेश को अब सूचना आयोग के खिलाफ बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस का यह रुख 2017 के विधानसभा चुनाव में ठीक उसी तरह भारी पड़ सकता है जैसा कि भाजपा को 2010 का कुंभ घोटाला पड़ा था. केंद्र की कांग्रेस नीति संप्रग सरकार ने भी उसके समय के तमाम घपले घोटालों के होने से इनकार किया था, जिसका परिणाम उसे 2014 के लोकसभा चुनावों में चुकाना पड़ा. राज्य सूचना आयुक्त अनिल कुमार शर्मा को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है. राज्य सूचना आयुक्त ने राज्य सरकार की अनदेखी के बाद केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर विशेष सुरक्षा की मांग की थी. जून 2013 की प्राकृतिक आपदा ने हजारों जिंदगी लील ली थी. भारी जानमाल का नुकसान हुआ, वह अलग. इस आपदा के बाद व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चला, अब दो वर्ष बाद राहत कार्यों के दौरान अधिकारियों की भूमिका ने सबको चौंका दिया. आपदा के दौरान की गई फिजूलखर्ची, अनियमितताएं और फर्जी बिलों का यह घोटाला सूचना के अधिकार के जरिए सामने आया. मामला क्योंकि इसी कांग्रेस सरकार के समय का है. इससे सूबे की कांग्रेस सरकार स्वयं को लगातार असहज स्थिति में पा रही है. यही वजह रही कि घोटाले के सार्वजनिक होते ही कांग्रेस ने मामले को सामने लाने वाले सूचना आयुक्त अनिल शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. भाजपा के लगातार हमलों के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत को फिर मोर्चा संभालना पड़ा. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्राथमिक तौर पर पूरे मामले को देखने के बाद इसमें घोटाले जैसी कोई बात नजर नहीं आ रही. इस मामले में इनकी सरकार को बेवजह निशाना बनाकर छवि धूमिल करने का प्रयास हो रहा है. सरकार सूचना आयुक्त के अधिकारों की समीक्षा करवा रही है, क्योंकि सूचना आयुक्त को सिर्फ सूचनाओं पर संज्ञान लेने का अधिकार है, वह न्यायाधीश की भूमिका में नहीं आ सकते. ■

feedback@chauthiduniya.com

घोटाला उजागर करने वाले अफसरों को मिली सजा

सूचना के अधिकार अधिनियम के नोडल सामान्य प्रशासन विभाग ने उत्तराखंड के सूचना आयुक्तों की पेंशन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. आरटीआई के तहत आपदा राहत घोटाले के खुलासे के बाद यह राज्य सूचना आयोग पर सीधा हमला भी माना जा रहा है. पेंशन रोकने के पीछे शासन ने सीमित संसाधन होने का तर्क दिया है. प्रदेश सरकार मुख्य सूचना आयुक्तों को पेंशन के अतिरिक्त 14 हजार रुपये अलग से भी दे रही है. इसके अलावा सेवा का अधिकार आयोग सहित आधा दर्जन आयोग हैं जिनमें सरकार पेंशन का लाभ दे रही है. सामान्य प्रशासन के प्रभारी सचिव शैलेश बगोली की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संवैधानिक निकायों के पदधारको को पेंशन का लाभ देने से प्रदेश सरकार के राजकोष पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. इससे विकास कार्यों के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी होगी. इसे देखते हुए ही प्रदेश सरकार ने 2005 में अंशदायी पेंशन योजना शुरू की थी. राज्य सरकार इस स्थिति में नही है कि राज्य सूचना आयुक्तों को पेंशन लाभ दे सके. शासनादेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सूचना आयुक्तों को सेवानिवृत्त होने पर पेंशन नहीं दी जाएगी और इस आदेश को जारी करने में कार्मिक, न्याय और वित्त की सहमति ले ली गई है. कुछ दिन पहले ही सूचना के अधिकार अधिनियम में राज्य सूचना आयुक्त ने आरटीआई एक्टिविस्ट भूपेंद्र कुमार की अपील पर आपदा राहत घोटाले की सीबीआई जांच का आग्रह किया था. ■

हरीश सरकार फेल, पड़ी हैं केदारनाथ में लाशें-निशंक

-रेनू शर्मा

हरिद्वार के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भगवान केदारनाथ में मानव कंकाल दिखने पर गहरा आक्रोश जताया. उन्होंने कहा कि केदारनाथ में अब भी लाशें मौजूद हैं. दर्शन करने के बाद निशंक ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से केदारनाथ में यात्रियों के लिए किसी प्रकार की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई है. सरकार ने केदारनाथ के नाम पर पैसों की जमकर लूट की है. आपदा के दो वर्ष बाद जिस तरह की तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई हैं. तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि केदारनाथ में आज भी लाशें पड़ी हुई हैं. यहां दुर्गंध आ रही है. सरकार ने लाशों को अभी तक साफ नहीं कराया है. जगह-जगह मानव कंकाल मिल रहे हैं. सरकार का ध्यान सिर्फ आपदा के पैसे को ठिकाने लगाने पर है. निशंक ने कहा कि केदारनाथ में अब भी कुछ कार्य नहीं हुए हैं. मंदिर के नाम पर भी पैसे की लूट हुई है. सरकार ने तीर्थ पुरोहितों की भी सुध नहीं ली है. उन्होंने कहा कि केदारनाथ में संपन्न सभी कार्यों की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपी जाएगी. निशंक ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महाघोटालों का बीजारोपण किया है. सरकार को इस मामले में ष्वेत पत्र जारी करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंपेंगे. उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सरकार साढ़े चार सौ करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रही है. निशंक ने कहा कि ऐसी भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं देखी गई. बिना रजिस्ट्रेशन व टेंडर के पांच-पांच करोड़ रुपये के काम कराए गए. उन्होंने कहा कि केदारनाथ में प्री-फैब्रिकेटेड हट्स पर्यावरण के लिए घातक है. वहां पक्के भवन बनने चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 18 जून को वह केदारनाथ गए थे और वहीं से उन्होंने मुख्यमंत्री से वार्ता की थी. उनके पास आपदा के एक-एक फुटेज हैं. तीर्थयात्री तड़प-तड़प कर मरते रहे और सरकार सोती रही. देश-विदेश के कोने-कोने से करोड़ों रुपये चंदे के रूप में सरकर को मिला और इस धनराशि की सरकार ने बंदरबांट की. सरकार आबकारी, खनन, सिडकुल व आपदा घोटाले में डूबी है. उन्होंने कहा कि भाजपा इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है. आपदा प्रभावितों की सरकार सुध नहीं ले रही है. उन्होंने कहा कि सीएम हरीश रावत केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद बहुत अच्छी बात होने की बात कहते हैं और बाद में केंद्र पर असहयोग का झूठा आरोप लगाते हैं. वह जान लें कि जनता को बरगलाया नहीं जा सकता है. निशंक ने हरीश सरकार पर कई सारे आरोप लगाए. ■

नीरज, उदय प्रताप और मरियम को मिला सम्मान

एक-दूसरे की बड़ाई और इज्जत आफजाई

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव डॉ0 गोपाल दास नीरज को साहित्य शिरोमणि सम्मान प्रदान करते हुए

डॉ0 उदय प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री साहित्य शिरोमणि सम्मान प्रदान करते हुए

कु0 मरियम सिद्दीकी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से साहित्य शिरोमणि सम्मान लेते हुए

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में दो साहित्यकार हैं, एक उदय प्रताप सिंह और दूसरे गोपाल दास नीरज. इन दोनों साहित्यकारों को फिर से सम्मानित करने का आयोजन पिछले दिनों सरकार ने किया. नीरज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कोई सवाल नहीं उठ सकता. लेकिन प्रदेश के लोग अगर यह पूछते हैं कि साहित्य और सृजन में उत्तर प्रदेश में और लोग भी हैं कि नहीं, तो यह सवाल जायज लगता है. इस बार के सम्मान-आयोजन में थोड़ा स्वाद परिवर्तन गीता के अध्ययन और ज्ञान को लेकर सुर्खियों में आई बच्ची मरियम सिद्दीकी को सम्मानित किए जाने से जरूर हुआ. सम्मान कार्यक्रम में एक दूसरे की प्रशंसा करने की सीमाओं का भी ध्यान नहीं रखा गया.

समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश की सत्ता के मुखिया अखिलेश यादव ने गीता ज्ञान प्रतियोगिता जीतने वाली मरियम सिद्दीकी को 11 लाख रुपये की धनराशि वाले विशिष्ट सम्मान से नवाजा. वहीं मरियम ने भी 11-11 हजार रुपये के दो चेक गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कोष में दिए. कवि गोपाल दास नीरज और उदय प्रताप सिंह को 21-21 लाख रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया. हिंदी संस्थान, जिसके उदय प्रताप सिंह अध्यक्ष हैं, के कर्मचारियों ने अपने वेतन से जुटाए 36 हजार 112 रुपये का एक चेक भूकंप पीड़ितों के लिए भेंट किया.

सम्मान से गदगद हिंदी संस्थान के अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने तो मुलायम सिंह की तुलना अकबर से ही कर डाली. ऐसा कहते समय उनके दिमाग में समाजवादी पार्टी की मुस्लिम-मुलायम राजनीति का ध्यान रहा होगा. उन्होंने कहा कि अकबर को कला से प्रेम था, इसलिए वह महान शासक बना. मुलायम भी कला और साहित्य के लिए महान काम कर रहे हैं. यश भारती सम्मान दिए. फिर हिंदी संस्थान के पुरस्कार शुरू किए. पुरस्कार बंद हो गए, तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिर शुरू करवाए. सैफई महोत्सव में भी नेता नहीं कलाकारों को सम्मानित किया जाता है. साहित्य शिरोमणि सम्मान पाने वाले भाषा संस्थान के अध्यक्ष गोपाल दास नीरज ने भी प्रशंसा में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. नीरज ने कहा कि अब सिर्फ शरीर ही मेरा है, सम्मान जो मिला, मुलायम सिंह यादव ने ही दिया. इतना सम्मान मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया. यह सम्मान मेरे लिए ऑस्कर और नोबेल के बराबर है. उन्होंने सबसे पहले मुझे राज्य अतिथि बनाया, यश भारती सहित कई सम्मान दिए. अब यह सम्मान तो मेरे लिए सबसे अहम है.

इस प्रशंसा पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कहां चूकने वाले थे. उन्होंने भी दोनों साहित्यकारों को अनमोल रत्न बताया और कहा कि ये हीरे नेताजी (मुलायम) की खोज हैं, हमें तो बस इनका सम्मान करने का मौका मिल रहा है. नीरज जी और डॉ. उदय प्रताप सिंह ने अपनी रचनाओं के जरिए समाज को नई दिशा दिखाई और समाजवादियों का मार्गदर्शन किया है. दोनों रचनाकारों का साहित्य अत्यन्त प्रेरक एवं प्रासंगिक है. नीरज जी भाषा संस्थान के और उदय प्रताप जी हिन्दी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष हैं. अपनी मेहनत और प्रयासों से इन्होंने दोनों संस्थानों को नया जीवन प्रदान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया में अपनी उपलब्धियों से उत्तर प्रदेश का नाम रौशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किए जाने की शुरुआत नेताजी द्वारा की गई. इस परम्परा का पालन वर्तमान समाजवादी सरकार भी कर रही है. प्रत्येक क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल करने वालों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है. हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए नेताजी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

मुलायम ने भी कहा कि यों तो गोपाल दास नीरज का सम्मान देश-विदेश में हुआ है लेकिन परिवार में होने वाले सम्मान की अधिक अहमियत होती है. उन्हें यह सम्मान उनके परिवार में दिया जा रहा है. मुलायम ने नीरज जी से अपने पुराने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि साधारण परिवेश में जन्मे डॉ. गोपाल दास नीरज ने अपने संघर्ष, प्रतिभा और साहित्य साधना से पूरी दुनिया में हिन्दी और देश का सम्मान बढ़ाया है. इसी प्रकार डॉ. उदय प्रताप सिंह ने साहित्य सृजन के साथ-साथ राजनीति के माध्यम से जनसेवा की. मुलायम ने यह भी कहा कि देश-दुनिया में गैरबराबरी बढ़ रही है. इसकी वजह से आंदोलन बढ़ रहे हैं. गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो आंदोलन और बढ़ेंगे. मुलायम ने हिंदी की वकालत करते हुए कहा कि हम अंग्रेजी का विरोध नहीं करते, लेकिन सरकारी कामकाज हिंदी में भी होना चाहिए. अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए. मुलायम ने कहा कि न्यायालयों में भी हिंदी में काम हो और प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी की बाध्यता खत्म होनी चाहिए. फिर उन्होंने सियासी संतुलन भी साधा और कहा कि हिंदी और उर्दू दो हाथ हैं. इन्हें हमें एक साथ आगे बढ़ाना होगा. मुख्यमंत्री ने सम्मान समारोह के मौके पर हिंदी संस्थान के अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह की किताब तुम्हें सोचता रहा, का विमोचन भी किया. साथ ही शेरजंग गर्ग की हिंदी में अनुदित गीतांजलि का भी उन्होंने विमोचन किया. कार्यक्रम में मरियम सिद्दीकी ने श्रीमद्भागवत गीता के श्लोक का पाठ किया और कौमी एकता पर आधारित कुछ शेर भी प्रस्तुत किए. ■

feedback@chauthiduniya.com

गीता-ज्ञानी मरियम को ब्रांड अंबेसडर बनाएंगे अखिलेश

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गीता ज्ञान प्रतियोगिता जीतने वाली छठे क्लास की छात्रा कुमारी मरियम सिद्दकी को ब्रांड अंबेसडर बनाने का प्रस्ताव दिया है. मुम्बई में आयोजित श्रीमद्भागवत गीता चैम्पियन्स लीग में पहला स्थान प्राप्त करने वाली कक्षा 6 की छात्रा कुमारी मरियम सिद्दीकी कहती हैं कि सभी धर्मों के बारे में जानने की उनकी इच्छा ने ही उन्हें यह कामयाबी दी है. इस्कॉन की ओर से आयोजित गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानने का मौका मिला तो मरियम ने अपने पिता से पूछकर तैयारी शुरू कर दी. एक महीने गीता पढ़ी और महाराष्ट्र के करीब 4000 से ज्यादा प्रतिभागियों को पछाड़कर छठवीं क्लास की इस छात्रा ने प्रतियोगिता जीत ली. मुंबई में रहने वाली कानपुर की इस छात्रा को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सम्मानित किया तो इस प्रतियोगिता को जीतने की उनकी खुशी और बढ़ गई. मरियम ने कहा कि अब तक जितने भी धर्मों को जाना, यही लगा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है. मरियम लखनऊ आकर काफी खुश थीं. वह बताती हैं कि कानपुर उनका मूल निवास है और लखनऊ में उनके चाचा रहते हैं. जब भी लखनऊ आती हैं, तो यह शहर अपना सा लगता है. यहां का खाना अच्छा लगता है. मरियम ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से खास मुलाकात की. ■

मजदूरों की हालत दयनीय

सत्येंद्र

मजदूर दिवस या मई दिवस पिछले ही महीने था. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मजदूरों के प्रेम की तमाम बातें कहीं और पोस्टरों से लखनऊ शहर पाट दिया. लेकिन समाजवादी सरकार का मजदूर प्रेम का जमीनी यथार्थ कुछ और ही है. लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ में भवन निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूरों का एक तिहाई हिस्सा हर छह माह पर किसी-न-किसी हादसे का शिकार हो जाता है. ज्यादातर मजदूर ऊंचाई से गिरने के कारण घायल होते हैं. कई बार तो मजदूरों की मौत हो जाती है. घायल होने वाले मजदूरों में 31 प्रतिशत काम के दौरान जख्मी होते हैं और 19 प्रतिशत पर निर्माण सामग्री गिरने से और 9 प्रतिशत भारी या धारदार सामग्री उठाने से घायल होते हैं. 63 प्रतिशत मजदूर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाते. घरेलू नुस्खों से ही वे अपना इलाज करते हैं, जो कई बार प्राणघातक हो जाते हैं. इतना ही नहीं पौष्टिक भोजन के अभाव में अधिकतर मजदूर स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से जूझते रहते हैं. इसी सर्वेक्षण के अनुसार 50 प्रतिशत मजदूर शरीर में लगातार दर्द से, 42 प्रतिशत सांस की बीमारी से परेशान रहते हैं, 17 प्रतिशत मूत्र सम्बन्धी समस्याओं से ग्रस्त हैं, 27 प्रतिशत को त्वचा का संक्रमण है और 30 प्रतिशत को हर समय सिरदर्द, चक्कर, उल्टी की शिकायत रहती है. दरअसल कार्यस्थल पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं होता, यहां तक कि शौचालय व पीने का पानी भी नहीं. ऐसे में ये परेशानियां उनके स्वास्थ्य की गम्भीर समस्याओं में बदल जाती हैं.

लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए मजदूरी, सुरक्षा के उपकरण व कार्यस्थल पर सुविधाओं के लिए पूंजीपति हमेशा ही कम से कम खर्च करते हैं. इससे मजदूरों के स्वास्थ्य पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है, पर इससे पूंजीपतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रशासन तंत्र भी इस पर निगरानी नहीं रखता. इस सर्वेक्षण ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है कि 81 प्रतिशत मजदूरों को सुरक्षा के कोई उपकरण ही नहीं मुहैया कराए जाते हैं. मोटे अनुमान के अनुसार त लखनऊ में लगभग 6 लाख मजदूर हैं, जिनका बहुतायत निर्माण क्षेत्र में लगा हुआ है. ज्यादातर मजदूरों को काम लेबर चौक से ही मिलता है. इनमें से अधिकतर कभी भी पूरे महीने काम नहीं पाते. अधिकतर को महीने में औसतन 15 से 20 दिन ही काम मिल पाता है. यहां काम करने वाले मजदूरों का बहुसंख्यक आप्रवासी है, जो पूर्वांचल, लखीमपुर, सीतापुर व आसपास के गांवों सहित पश्चिम बंगाल, असम, ओड़ीशा और बिहार से यहां आते हैं. इस अध्ययन में शामिल 87 प्रतिशत मजदूर 18 से 37 वर्ष के थे, जबकि 9 प्रतिशत की उम्र 18 वर्ष से कम थी.

जिस प्रदेश में मजदूरों की यह स्थिति है, उसी उत्तर प्रदेश की सरकार का रवैया यह है कि पिछले पांच वर्षों में भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की मद में जमा 1140 करोड़ रुपये में से सरकार अब तक मात्र 76.59 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई है. गौरतलब है कि अभी तक सरकार द्वारा ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया जा सका है जिनसे मजदूरों की सही स्थिति का पता लगाया जा सके. फिर सरकार ने 76 करोड़ कहां और किसलिए खर्च कर दिए, यह भी स्पष्ट नहीं है. असंगठित मजदूरों के कल्याण के दिखावे के लिए बीच-बीच में फर्जी घोषणाएं करने वाली प्रदेश सरकार का आलम यह है कि असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत नियमावली बनाने का काम ही आज तक नहीं किया गया, जिससे इस कानून से मिलने वाले पंजीकरण तथा अन्य लाभों से मजदूर वंचित हैं.

यह सर्वेक्षण भले ही लखनऊ में हुआ हो, पर आज कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में असंगठित मजदूरों के यही हालात हैं. देश के लगभग साढ़े तीन करोड़ निर्माण मजदूरों की स्थिति तो और भी ख़राब है. काम के घंटों, सुरक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी श्रम कानूनों का इनके लिए कोई मतलब नहीं. अक्सर ठेकेदार या मालिक पैसा देने के बजाय पीट देता है और मजदूर सिवाय गिड़गिड़ाने के कुछ नहीं कर पाता. आपको ध्यान होगा कि लखनऊ के निर्माणाधीन हाइकोर्ट परिसर में चौथी मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके बाद सैकड़ों मजदूरों ने हाई-वे जाम कर दोषियों पर कार्रवाई व पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे देने की मांग की थी. लेकिन बाद में पुलिस ने मामला रफा-दफा कर दिया. पुलिस, कानून और सरकारों पर विश्वास करके देश-प्रदेश की जनता पिछले 68 साल से लगातार धोखे ही खाती आ रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

27 लाख मजदूर बेरोजगार, काम कर रहे हैं लाखों बाल मजदूर

बीते एक दशक में उत्तर प्रदेश के करीब डेढ़ लाख छोटे और मध्यम उद्योग धंधे बंद हुए हैं. उद्योगों के बंद हो जाने के कारण लाखों मजदूर बेकार हो गए हैं या फिर दिहाड़ी के लिए मजबूर हैं. राज्य सरकार के विकास के नारों की असलियत यही है. केंद्र सरकार की मध्यम और लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय चतुर्थ सेंसस रिपोर्ट के आंकड़े उत्तर प्रदेश की औद्योगिक हकीकत बयान करती है. प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर करीब 51 प्रतिशत लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं. महिला उद्यमियों की संख्या नगण्य है. महिलाओं की उद्यम में केवल दो प्रतिशत ही भागीदारी है. रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं का उद्योग प्रबन्धन में कोई योगदान नहीं है. 97 प्रतिशत उद्योग पुश्तैनी तौर पर चलाए जा रहे हैं. यूपी में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की उद्योगों में भागीदारी नहीं के बराबर है. केवल आठ प्रतिशत अनुसूचित जाति और केवल एक प्रतिशत जनजाति के लोग उद्योगपति कहे जा सकते हैं. यूपी में सबसे ज्यादा उद्यमी पिछड़ी जाति के हैं. इनकी भागीदारी करीब 53 प्रतिशत है, जबकि अन्य जातियों की उद्योग में रुचि केवल 34 प्रतिशत ही है. केंद्र सरकार की चौथी अध्ययन रिपोर्ट में 26 प्रतिशत उद्योग स्थाई रूप से बंद दिखाए गए हैं, जबकि अस्थाई रूप से करीब 12 प्रतिशत उद्योग बंद हुए हैं. प्रदेश में उद्योगों के बंद होने के पीछे सबसे बड़ा कारण सामाजिक असुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी है. औद्योगिक संगठनों के मुताबिक सरकार उद्योगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति किए जाने के दावे जरूर करती है, लेकिन हकीकत में यह गलत दावा है. बिजली की हालत अत्यंत खस्ता है. सड़कों की भी हालत खराब है. उद्योगों के लिए जरूरी सामान लाने ले जाने के खर्चे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं. दूसरी तरफ प्रदेश में बाल मजदूरी का बढ़ता आंकड़ा भी परेशानी बढ़ा रहा है. अकेले यूपी में ही करीब 12 लाख बाल मजदूर हैं. असंगठित क्षेत्रों में छह लाख बाल मजदूर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, लेकिन 12 लाख ऐसे मजदूर हैं, जिनसे जबरन काम लिया जा रहा है. फिरोजाबाद और भदोही ऐसे जिले हैं, जहां बाल मजदूरों की बड़ी संख्या है. भदोही के कालीन तथा फिरोजाबाद के कांच उद्योग में बड़ी संख्या में बाल मजदूर काम कर रहे हैं. बाल मजदूरों से ऐसे हालत में काम लिया जा रहा है, जिसमें कोई भी काम नहीं करना चाहेगा. खासकर कांच उद्योग में मजदूरों को बुरी हालत में काम करना पड रहा है. बाल मजदूरों में सिर्फ बच्चे ही नहीं होते बल्कि लड़कियां भी होती हैं. लड़कियां उत्पीड़न के विभिन्न तौर तरीकों से इस्तेमाल होती हैं. फिरोजाबाद के कांच उद्योग में 80 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे काम करते हैं. चूड़ियों को जोड़ने के लिए उन्हें कोयले की भट्टी के पास बैठना पड़ता है. भट्टी के पास रहने के कारण वह क्षय रोग के शिकार हो जाते हैं. आंकड़े बताते हैं कि विंध्याचल मंडल के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में बाल मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. बाल मजदूरी में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. पिछले 10 वर्षों में मिर्जापुर में जहां 12349 बाल मजदूरों की संख्या बढ़ी, वहीं सोनभद्र में 10077 बढ़ गए. वर्ष 2011 की जनगणना के बाद बाल श्रमिकों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे भयावह नजर आती है. ■

-वैष्णवी वंदना